हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 31 अगस्त, 2026 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 02.00 बजे अपराह्न आरंभ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

31.08.2026/1400/टी0सी0वी0/ए0एस0-1

शोकोद्‌गार

अध्यक्ष : आप सबका सत्र के दूसरे सप्ताह में स्वागत है। मुझे आपको सूचित करते हुए दुःख हो रहा है कि पिछले सप्ताह और इस सप्ताह के बीच हमारे इस माननीय सदन के पूर्व विधायक श्री राम रत्न शर्मा जी का निधन हुआ है। इसलिए हम आज शोकोद्‌गार से प्रारंभ करेंगे। मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस माननीय सदन के पूर्व सदस्य रहे स्वर्गीय श्री राम रत्न शर्मा जी के निधन पर शोकोद्‌गार प्रस्तुत करें।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, श्री राम रत्न शर्मा जी नदौन विधान सभा क्षेत्र से संबंधित थे जिसका नाम बदलकर अब बड़सर विधान सभा क्षेत्र हो गया है। वे भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे। उनका जन्म 28 जनवरी, 1937 को हुआ था और वे लंबे समय से राजनीति तथा सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए थे। वे सामाजिक जीवन के कार्यों से हमेशा जुड़े रहते थे और हमेशा उनको उठाते रहते थे। वे बी0बी0एम0बी0 कॉलेज चकमो, बाबा बालकनाथ मंदिर प्रबंधक समिति, हमीरपुर के महासचिव, हिमाचल प्रदेश मंदिर प्रतिनिधि सभा के उपप्रधान, सिद्ध बाबा बालकनाथ समिति तथा हिमाचल प्रदेश कल्याण सभा के प्रधान रहे। वे हिमाचल प्रदेश विधान सभा के वर्ष 1982 से 1985 तक सदस्य रहे तथा हितकारी सभा हमीरपुर व अखिल भारतीय सामाजिक संस्था संघ के हिमाचल प्रदेश इकाई के सदस्य थे।

अध्यक्ष महोदय, वे भगवा वस्त्र पहनकर रहते थे। जब बी0एड0 कॉलेज की शुरुआत हुई तो उन्होंने बी0एड0 कॉलेज की शुरुआत के लिए एन0ओ0सी0 लिया। वे हमेशा बड़ा साधारण और सादगी भरा जीवन बिताते थे। वे बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके निधन पर हम सब लोग आज इस सदन में दुःख प्रकट कर रहे हैं। यह माननीय सदन ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और उनके परिवरजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता है। धन्यवाद।

Speaker : Anybody else wants to speak? माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप कुछ कहना चाहते हैं?

31.08.2026/1400/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, श्री राम रत्न शर्मा जी का दुखद निधन होने की खबर हाल ही में इस सदन के सत्र के बीच में मिली। श्री राम रत्न शर्मा

एन0एस0 द्वारा ....जारी

31-8-2026/1405/NS-AS/1

शोकोद्‌गार -----जारी--------श्री जय राम ठाकुर------जारी

भारतीय जनता पार्टी के उससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक समर्पित कार्यकर्ता रहे। वे भगवा कपड़े और धोती पहनते थे और यह उनकी एक पहचान थी। उनका जन्म श्री लोंगू राम जी के परिवार में जिला हमीरपुर के गांव चकमोह में दिनांक 28 जनवरी, 1937 को हुआ था। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि उनकी राम जन्मभूमि के आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका रही। जब वहां विवादित ढांचे को गिराया तो वे वहां से कुछ अवशेष और अन्य चीजें लेकर अपने घर तक पहुंचे थे। वे वहां से ईंटें लेकर आए थे। उनकी खास तौर पर एक विशेषता थी कि वे सर्दी के मौसम में भी धोती पहनते थे और ऊपर से कभी शॉल या कोई अंगवस्त्र ले लेते थे। जब हम उनसे हाथ मिलाते थे तो वे हमारा हाथ मजबूती के साथ पकड़ते थे क्योंकि वे योगासन करते थे। कई बार कहा जाता था कि वे काफी मिनटों तक शीर्षासन करते थे। उनकी दिनचर्या इस प्रकार की थी। वे बिल्कुल दुबले-पतले थे लेकिन बहुत मजबूत थे। एक बार वे विधान सभा सचिवालय के गेट के सामने धरने पर बैठ गए थे। बहुत सारे आंदोलनों में अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए उनकी एक अलग भूमिका रही है। कुल मिलाकर वे संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, स्वच्छ छवि के व्यक्ति थे और समाज सेवा की ललक हमेशा उनके मन में रही तथा इसी बात को लेकर वे जाने जाते थे। उनके दुखद निधन पर मैं भी अपनी ओर से और अपने दल की ओर से शोक व्यक्त करता हूं तथा परिवारजनों तक हमारी संवेदनाएं पहुंचें, इसके लिए अध्यक्ष महोदय आपसे आग्रह करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी शोकोद्‌गार में भाग लेंगे।

31-8-2026/1405/NS-AS/2

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल : अध्यक्ष महोदय, पिछले कल प्रातः मेरे विधान सभा क्षेत्र बड़सर से दो बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे आदरणीय श्री राम रत्न शर्मा जी का देहावसान हुआ। हमें जैसे ही इसका पता लगा हम उनके घर गए और हमारा सारा क्षेत्र शोकसंतप्त हो गया। श्री राम रतन जी जैसा कि यहां बताया गया कि बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, योगी थे और मुनि थे। जब उन्होंने राजनीतिक जीवन से संन्यास लिया तो वानप्रस्थ में भी रहे, वे पतंजलि में भी रहे और कम-से-कम 10-12 वर्षों तक पतंजलि में रहे। जब वहां हमारा जाना होता था, जब हम रिश्तेदारी में चकमोह जाते थे जहां इनका जन्म हुआ है तो वहां मेरी धर्मपत्नी का ननिहाल है और उनसे अक्सर मिलना-जुलना होता रहता था। वे हमसे काफी ज्ञान की बातें करते थे विशेष तौर पर सनातन धर्म के बारे में बहुत सारी चर्चा किया करते थे। वे युवाओं को संदेश देते थे कि नशे से दूर रहना है तथा समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना है। यह उनकी एक आदत थी। जब वे विधायक थे तो कई बार

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

31.08.2026/1410/RKS/DC-1

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जारी.....

अपने पूरे विधान सभा क्षेत्र की पदयात्रा करते थे। उस समय आज जैसे साधन उपलब्ध नहीं थे, बसों की संख्या कम थी लेकिन वे बहुत कर्मठ और जुझारू थे। हालांकि वह दुबले-पतले थे किन्तु वे अपने पूरे विधान सभा क्षेत्र की पदयात्रा करते थे। जहां कहीं भी उनका प्रवास होता था, वहां वे चाय नहीं पीते थे बल्कि दूध पीना पसंद करते थे। वे शक्कर की पुड़िया अपनी जेब में रखते थे और उसी शक्कर को दूध में मिलाकर पीते थे। पिछले लगभग एक वर्ष से उनका स्वास्थ्य काफी खराब चल रहा था। लगभग 6-7 महीने पूर्व उनके दीन दयाल उपाध्याय, बी0एड0 कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में मुझे भी सम्मिलित होने का

अवसर मिला था। उस अवसर पर उन्होंने धर्म और न्याय विषय पर लिखी अपनी एक पुस्तक मुझे भेंट की थी। हालांकि समय की कमी के कारण मैं उस किताब का पूर्ण अध्ययन नहीं कर पाया हूं लेकिन अब मैं उसे अवश्य पढ़ूंगा। श्री राम रत्न शर्मा जी बहुत ही कर्मठ और कर्मयोगी व्यक्ति थे। उनके दो पुत्र और पुत्रियां हैं। उनके एक पुत्र लंबे समय से अधरंग से पीड़ित हैं और लम्बे समय से बिस्तर पर हैं जबकि दूसरे पुत्र दुकान का कारोबार करते हैं। अध्यक्ष महोदय, यहां पर उनके प्रति जो शोकोद्गार रखा गया है उसे मैं भी अक्षरशः रखता हूं। मैं उनके परिवार के प्रति एक बार फिर से अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें नम्न करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दे तथा उनके परिजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति और धैर्य प्रदान करें। यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब माननीय नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री अपने शोकोद्गार प्रस्तुत करेंगे।

नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिला हमीरपुर के तत्कालीन नदौन विधान सभा क्षेत्र जिसे वर्तमान में बड़सर विधान सभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, से दो बार विधायक रहे श्री राम रतन शर्मा जी का दिनांक 30 अगस्त को निधन हो गया। इस संबंध में मुख्य मंत्री द्वारा जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसमें आपने मुझे भी बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। श्री राम रत्न शर्मा जी जब वर्ष 1990 में विधायक थे तो उस समय मैं हमीरपुर कॉलेज में पढ़ता था। हमें उनके बारे में अक्सर लोगों से सुनने को मिलता था। उस समय राम मंदिर आंदोलन देश का एक प्रमुख राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दा था और उसमें उन्होंने बढ़-चढ़कर भाग

31.08.2026/1410/RKS/DC-2

लिया। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के समय वे विधायक थे और उस आंदोलन में वे सक्रिय रूप से शामिल रहे। वहां से लौटते समय वे एक ईंट भी अपने साथ लेकर आए। बाद में जब ढांचा गिराने के संबंध में केस चला तो उसमें उनका नाम भी आया किन्तु वे अपने इरादों के पक्के थे। वे जिस कार्य को करने का संकल्प लेते थे उसे पूर्ण समर्पण और भाव के साथ पूरा करने का प्रयास करते थे। बड़सर विधान सभा क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध सिद्ध

पीठ बाबा बालक नाथ जी के मंदिर की प्रबंधन समिति के गठन में भी वे संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे। इसी ट्रस्ट द्वारा जो कॉलेज चकमोह में चलाया जा रहा है वहां आज सैकड़ों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अब तक हजारों विद्यार्थियों ने वहां से शिक्षा प्राप्त की है। उस संस्थान की स्थापना और उसके विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बाद में उन्होंने एक बी0एड0 कॉलेज की भी स्थापना की थी। उनका शिक्षा जगत में काफी योगदान रहा है। वे धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में गहन रुचि लेते थे।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

31.08.2026/1415/बी.एस./डी.सी.-1

शोकोद्गार जारी...नगर एवं ग्राम योजना मंत्री जारी...

मैं उनके निधन पर अपनी तरफ से संवेदना व्यक्त करता हूं और उनके परिवार को भगवान इस दुःख को सहन करने की शक्ति दे। मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं और दिवंगत आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दें। यही मैं कामना करता हूं, धन्यवाद।

अध्यक्ष : स्वर्गीय श्री राम रत्न शर्मा जी, पूर्व सदस्य के निधन पर जो उल्लेख सदन में प्रस्तुत किए गए हैं उसमें मैं भी अपने आपको शामिल करता हूं।

स्वर्गीय श्री राम रत्न शर्मा जी का जन्म दिनांक 28 जनवरी, 1937 को श्री लंगू राम शर्मा जी के घर ग्राम चकमोह, जिला हमीरपुर में हुआ था। श्री राम रत्न शर्मा जी दो बार वर्ष 1982 और 1990 में इस सदन के सदस्य रहे। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा भारतीय जन संघ में भी लंबे समय तक कार्य किया। वर्ष 1960 में उन्होंने जन संघ में जनरल सेक्रेटरी के तौर पर कार्य किया।

सरल और सहज व्यवहार के कारण उन्होंने क्षेत्र में अलग पहचान बनाई थी। विधायक बनने के बाद उन्होंने बड़सर क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि बना लिया। शिक्षा के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान रहा। उनकी विशेष रुचि सामाजिक कार्य बेरोजगारी तथा ग्रामीण निर्धनता को दूर करने में रही।

वह पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। पिछले कल यानी दिनांक 30 अगस्त, 2026 को 90 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए माननीय सदन की ओर से कामना करता हूं और परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। इस माननीय सदन की भावनाओं को शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दिया जाएगा।

अब मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अपने-अपने स्थान पर कुछ क्षण के लिए मौन खड़े हो जाएं।

(**सभा मण्डप** में **उपस्थित सभी अपने-अपने स्थान पर** दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कुछ क्षण के लिए **मौन के लिए खड़े हुए।**)

31.08.2026/1415/बी.एस./डी.सी.-3

प्रश्न काल आरंभ

प्रश्न संख्याः 3733 (स्थगित)

श्री केवल सिंह पठानियाः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्याः 3733

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सूचना एकत्रित की जा रही है।

प्रश्न संख्याः 4042 (स्थगित)

श्री बलबीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र की बहुत सारी योजनाओं से हिमाचल प्रदेश के सभी विधान सभा क्षेत्रों में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। एक पंचायत में मनरेगा के तहत भी कार्य हो रहे हैं और 'प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना' से भी कार्य भी हो रहे हैं। विधायक निधि से भी कार्य हो रहे हैं और एम0पी0 निधि से भी कार्य हो रहे हैं तथा शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान्स के भी कार्य हो रहे हैं।

लगभग 21-22 योजनाओं से एक पंचायत में पानी, सड़क और रास्ते के कार्य हो रहे हैं। मेरी मुख्य मंत्री महोदय से विनती है कि जो कार्य एम0बी0 में चढ़ाए जा रहे हैं उसमें

अगर फोटो के साथ ये सभी कार्य चढ़ाये जाएं कि इस टैंक पर 5 लाख रुपये इस योजना के तहत कार्य हुआ है। क्योंकि इसी तरह जाइका से भी कार्य हो रहे हैं और फॉरेस्ट की दो योजनाओं के तहत भी कार्य हो रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में बहुत सारे पानी के टैंक बनाए जा रहे हैं। इन 21-22 योजनाओं के माध्यम से पंचायतों में भी बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। इसके बावजूद इन सभी योजनाओं के तहत पैसे खर्च करने के बाद भी गांव तक पानी नहीं पहुंच रहा है।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

31.08.2026/1420/DT/HK-1

प्रश्न संख्या 4042 जारी...श्री बलवीर सिंह वर्मा जारी...

मेरी विनती है कि जिस योजना के तहत कोई कार्य हो रहा है उस कार्य की पूरी डिटेल जब एमबी में चढ़ती है तो उसके साथ उस कार्य के कम-से-कम चार फोटो भी जरूर चढ़ाए जाएं जिससे यह पता चल सके कि इस स्थान में इस योजना के तहत यह कार्य पूर्ण हुआ है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जल जीवन मिशन से जो टैंक बन रहे हैं और उसी टैंक को पंचायत वाले भी अपने काम में चढ़ा सकते हैं तथा उसी टैंक को जायका वाले भी अपने काम में चढ़ा सकते हैं और उसी टैंक को मनरेगा वाले भी चढ़ा सकते हैं। उसी टैंक का अगर अलग-अलग एमबी में फोटो होगा और स्थान का पता होगा तो उसमें पारदर्शिता होगी। मेरा यह मानना है कि यह कार्य किसी भी क्षेत्र में पारदर्शिता से नहीं हो रहा है। अगर पारदर्शिता से करना है तो इसमें फोटो समेत स्थान का नाम एमबी में चढ़ाया जाए, अगर ऐसा होगा तो इससे पूरा पता लगेगा कि किस गांव में कौन-सा कार्य किस योजना के तहत पूर्ण हुआ है।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपनी बात क्लैरिटी से नहीं कह पाए। लेकिन मैं इनके कहने के बाद थोड़ा सा यह समझा हूं कि ये चाहते हैं कि जो मनरेगा का कार्य है या कोई और कार्य जल जीवन मिशन के तहत हुआ है या एमएलए फंड अथवा एमपी फंड से हुआ है, तो उसकी एमबी होनी चाहिए और एमबी में फोटो भी चढ़ना चाहिए।

मेरे ख्याल से तो श्री बलबीर वर्मा जी पहली बार यह बात कही है। लेकिन मैं माननीय सदस्य से जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन-सी पंचायत है जहां ऐसे कार्य हुए हैं कि एक ही काम को चार बार अलग-अलग योजना में लगाया गया? आप उस पंचायत का नाम मुझे बताइए। अगर ऐसी पंचायत का आप नाम बताएंगे और ऐसी गलती पाई जाएगी तो सरकार इंक्वायरी करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी सरकार पारदर्शिता में विश्वास रखती है । जहां गलत हुआ होगा वहां हम ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनती करना चाह रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए। मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि किस

31.08.2026/1420/DT/HK-2

पंचायत में क्या कार्य हुआ और उसमें कितनी पारदर्शिता अपनाई गई है। मैं यह बोल रहा हूं कि एक पंचायत में अठारह योजनाओं से कार्य हो रहे हैं और केंद्र प्रायोजित तथा प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में कार्य हो रहे हैं। मैं यह बोल रहा हूं कि अगर एमबी में कोई काम चढ़ रहा है और उसका पैसा दिया जा रहा है तो उस एमबी में उस कार्य की फोटो नहीं चढ़ रही परंतु वह चढ़नी चाहिए। मेरे गांव में एक टैंक बना है मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि उसमें उस कार्य का फोटो भी चढ़े और उस टैंक का नाम भी चढ़े कि यह टैंक तीस लीटर का मनरेगा से बना है और यह जायका से एक लाख लीटर का बना है। इस तरह से कार्यों में पारदर्शिता नहीं हो रही है, मैं यही आग्रह कर रहा हूं कि ऐसा हो ताकि पारदर्शिता बने। बहुत सारी योजनाओं से पंचायतों में कार्य हो रहे हैं। अगर स्थान के नाम के साथ आप चार फोटो एम0बी0 में चढ़ेंगे तो उसमें किस योजना या हैड में हुआ है, उसमें पारदर्शिता होगी। इतनी-सी विनती है कि सभी योजनाओं में फोटो लगाएं और फिर ही उसका पैसा दें।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से फिर कहा रहा हूं कि थोड़ी स्पष्टता से अपनी बात रखिये। यह अपनी बात में स्पष्टता लाने में अनाकानी कर रहे हैं। आपको अपनी बात को स्पष्टता से कहना चाहिए। जो नियम बने हैं वे सरकार के बने हैं

और सरकार के अधिकारी उन्हें वेरिफाई करते हैं। हर एक सरकार के अधिकारी पर इसलिए संदेह नहीं कर सकते कि उन्होंने फोटो नहीं लगाये। एमबी में फोटो लगाने की जरूरत तब होगी कि अगर उस पंचायत में कोई टैंक जायका से भी बन रहा है और जल जीवन मिशन से भी बन रहा है। आप इस बात को छुपाइए मत। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ऐसा हुआ है तो आप मुझे बताइए। सरकार उसकी इंक्वायरी करवागी और जो कमियां होंगी उन कमियों को समझने के बाद, आपके विधान सभा क्षेत्र में जितनी भी पंचायतें हैं वहां किये गये कामों में यदी कहीं सुधार करना होगा तो हमारी सरकार उसमेंसुधार करेगी और आपकी बात का ध्यान रखेगी। पर आप थोड़ा-सा क्लियर करिए कि यह ऐसा हो रहा है। यह स्टैंडिंग जो वड्र्स हैं न... मेरा कहने का मतलब है कि कई चीजें स्टैंडिंग वड्र्स में होती हैं जैसे यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ते थे कि शिक्षा का बजट दस प्रतिशत हो और आज भी हमारे को तीस वर्ष बाद वही नजर आता है कि शिक्षा का बजट : These are standing slogans and words. इसलिए आप स्टैंडिंग शब्दों में बात न करें और स्पष्ट बताएं। मैं आपको गांरटी के साथ कहता

31.08.2026/1420/DT/HK-3

हूं कि जहां भी गलत होगा वहां हमारी सरकार निश्चित रूप से उचित कार्रवाई करगी क्योंकि हम पारदर्शिता से काम करने में विश्वास रखतें हैं और गलत के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे।

श्री विनोद सुल्तानपुरी श्री एन0जी0द्वारा जारी...

31.08.2026/1425/एच.के.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या - 4042........जारी--------अध्यक्ष के पश्चात......... जारी

Shri Vinod Sultanpuri : Mr. Speaker, Sir, thank you very much. सर, यह विशेष रूप से जाइका और आई0पी0एच0 (जल शक्ति विभाग) ने समानांतर एक ही कूहल को बनाया था और अब उसको जाइका द्वारा क्लेम किया जाने लगा तथा वे ही उसको रिपेयर

करने लगे हैं। विशेष रूप से ग्राम पंचायत कौटबेजा और ग्राम पंचायत दयोटी, इन दो ग्राम पंचायतों में जाइका ने क्लेम किया है और उनमें कॉन्ट्रैक्टर्स कौन हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। वे काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कोई पता नहीं है। एक ही स्कीम पर दो लोग क्लेम कर रहे हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट रुकिए। This question is very specific and pertains only to the Chopal Constituency. It is regarding the works being executed in the Chopal Constituency under various heads. आप तो अपनी विधान सभा क्षेत्र के मामले को पूछ रहे हैं।

श्री विनोद सुल्तानपुरी : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि दो विभाग क्लेम कर रहे हैं इसलिए I want some action from Hon'ble Chief Minister.

Speaker : I don't know Hon'ble Chief Minister wants to reply. Hon'ble Chief Minister...(Interruption) Please, please ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, श्री बलबीर सिंह वर्मा, आप भी अपने प्वाइंट को एड कर दीजिए।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जाइका के माध्यम से पानी को स्टोर करने के लिए बहुत सारे तालाब बनाए गए हैं। वे तालाब एक हफ्ते या दस दिन भी ठीक से नहीं टिक पाए और फट गए। मेरी यह मांग है कि अगर ये सारी चीजें पारदर्शिता के साथ हों और यदि उस स्थान के प्रॉपरली फोटो वगैरह हों, तो सच्चाई

31.08.2026/1425/एच.के.-एन.जी./2

सबको मालूम पड़ जाएगी। उनमें 15-15 लाख रुपये खर्च हुए हैं। मैं आपको उनकी फोटो सहित जानकारी दूंगा।

मेरे क्षेत्र में चार तालाब बनाए गए थे और उन पर 60 लाख रुपये खर्च हुए, लेकिन उनमें दो दिन भी पानी नहीं टिक सका। मैं यह चाहता हूं कि अगर इसमें पारदर्शिता के साथ काम हो और प्रॉपरली फोटोज़ हों, हर चीज की फोटो के साथ एम0बी0 में एंट्री हो, तो उसकी प्रॉपरली जांच-पड़ताल हो सकती है। धन्यवाद।

अध्यक्ष : आप नाम बता दीजिए। आप बता देंगे तो माननीय मुख्य मंत्री उनकी इंक्वायरी करवा देंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य न आपकी सुन रहे हैं और न मेरी सुन रहे हैं। अभी भी वही स्टैंडिंग बात कर रहे हैं। जाइका में ऐसा होता है, उस काल में ऐसा हुआ।

अध्यक्ष महोदय, **माननीय सदस्य श्री विनोद सुल्तानपुरी ने पंचायतों के नाम बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहे हैं। मैं उन कार्यों की इंक्वायरी के आदेश देता हूं कि जहां ऐसा काम हुआ है और कुछ गलत हुआ होगा, तो हम उसको बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे।**

अध्यक्ष महोदय, कई स्कीमों में ऐसी व्यवस्था है, जहां पर सरकार डवटेल करती है। यानी एक ही टैंक के निर्माण में आधा पैसा जाइका से आ जाता है और आधा पैसा कहीं और से आ जाता है। ऐसी भी स्कीम्ज़ होती हैं। **अगर इन पंचायतों में एक ही टैंक पर जाइका ने भी खर्च किया है, आई0पी0एच0 (जल शक्ति विभाग) ने भी खर्च किया है या किसी और विभाग ने खर्च किया है, तो मैं उसकी इंक्वायरी के आदेश दूंगा और पूरी जानकारी से इस सदन को भी अवगत करवा दूंगा।**

माननीय सदस्य, श्री बलबीर सिंह वर्मा अभी भी गहराई में जाकर नहीं बोल रहे हैं। ये अभी भी ऐसे कह रहे हैं जैसे बच्चों को कहानियों में सुनाते थे। मैं बार-बार इनसे पंचायतों या कार्यों के नाम लेने के लिए कह रहा हूं।

31.08.2026/1425/एच.के.-एन.जी./3

लेकिन ये एक बार भी नहीं बता रहे हैं। आप बताओ कि कहां पर क्या हुआ है और मैं कार्रवाई करूंगा, लेकिन आप बता नहीं रहे हैं।...(व्यवधान) आपको माननीय सदन में बताना चाहिए। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री बलबीर सिंह वर्मा, आप मुख्य मंत्री जी को लिख कर दे देना

31.08.2026/1425/एच.के.-एन.जी./4

प्रश्न संख्या -4552

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है, वह बहुत गैर-जिम्मेदारी के साथ दिया गया है। अगर आप इस प्रश्न के 'क' भाग के उत्तर में देखें, तो कहा गया है—जी हां। 'ख' भाग और 'ग' भाग का उत्तर देते-देते आपने इन दोनों को एक साथ क्लब कर दिया है। मैं प्रश्न के 'ग' भाग में आपसे यह जानना चाह रहा था कि क्या जांच में किसी प्रकार की चिकित्सकीय अथवा प्रशासनिक लापरवाही पाई गई? आपने उत्तर दिया है—जी हां।

अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गंभीर है और पिछले दिनों बहुत बड़ी चर्चा का विषय रहा। एक नौजवान महिला, जिसकी आयु मात्र 23 वर्ष थी, वह मेरे विधान सभा क्षेत्र के बालीचौकी क्षेत्र से संबंध रखती थी। नॉर्मल डिलीवरी या अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उस क्षेत्र के लोगों को जो नजदीकी और सुविधाजनक अस्पताल है, वह क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू पड़ता है। वह महिला कुल्लू के अस्पताल में एडमिट हुई और डॉक्टर्स का कहना था कि सब कुछ नॉर्मल है। पहले तो शायद

पी0बी0 द्वारा......जारी

31.08.2026/1430/YK/PB/1

प्रश्न संख्याः 4552 क्रमांगत... श्री जय राम ठाकुर...जारी

मुझे लगता है कि डॉक्टर्ज़ ने कहा था कि सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बाद में इमरजेंसी में ऑपरेशन के माध्यम से डिलीवरी हुई। मैं उन सारी तकनीकी चीजों में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन यह बात सत्य है कि उस महिला की डिलीवरी के बाद दुखद मृत्यु हुई। उसके बच्चे को बचा लिया गया लेकिन महिला की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के कारण परिवार में रोष था, इलाके के लोगों में भी रोष था और उसके बाद कुल्लू जिला के लोगों में भी रोष था। इस मामले में जो बात सामने आई उसके अनुसार डॉक्टर के व्यवहार को लेकर बहुत गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं। उस महिला की मृत्यु के पश्चात् एम0एस0 और एस0डी0एम0 द्वारा जो जांच की गई, उनकी रिपोर्ट्स का आपस में तालमेल नहीं है। एक जांच में कुछ और चीजें सामने आ रही हैं और दूसरी जांच में कुछ और बातें सामने आ रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि डॉक्टर के आने के समय और तारीखों के विषय में भी जो विवरण दिया गया है, वह भी आपस में कॉर्डिनेट क्यों नहीं हो रहा है? यहां गंभीर विषय यह है कि एक तरफ मुख्य मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कि हम हाई-एन्ड हैल्थ सर्विसेज यानी बहुत बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदेश में देने के लिए वचनबद्ध हैं और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन कुल्लू अस्पताल में उस समय ऑक्सीजन तक उपलब्ध नहीं थी और इस बात को वहां के प्रशासन ने भी स्वीकार किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें थोड़ा अधिक समय ले रहा हूं क्योंकि यह विषय बहुत गंभीर है। सुबह 9:15 बजे रजनी शर्मा उर्फ मंजू शर्मा, की तबीयत ज्यादा खराब हुई और डेढ़ बजे उसकी मृत्यु हो गई। उसे आगे रेफर भी नहीं किया गया। उसकी मृत्यु के पश्चात् जब कुछ सामाजिक संस्थाओं ने आंदोलन किए तो उन पर भी मामले दर्ज किये गए। वहां इस प्रकार की स्थिति बनी हुई थी कि लोग धरने पर और आमरण अनशन पर बैठे थे।

31.08.2026/1430/YK/PB/2

अध्यक्ष महोदय, उस परिवार के लोग अभी तक भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब जांच की रिर्पोट आएगी। वह जांच, जिसमें दो तरह की जांच हुई हैं, एक एम0एस0 के माध्यम से जांच हुई और दूसरी जांच के आदेश एस0डी0एम0 के माध्यम से दिए गए तथा उनकी रिपोर्ट आपस में मेल नहीं खा रही है। अभी तक विभाग के जवाब में कहा गया है कि यह मामला विचाराधीन है। हमने प्रश्न में पूछा था कि इसमें क्या कार्रवाई की गई और उसकी क्या रिपोर्ट आई? इसके जवाब में लिखा है कि मामला विचाराधीन है। इस विषय को लेकर प्रश्न के उत्तर देते समय और उसके बाद कहीं भी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, जहां उस बेटी की दुखद मृत्यु हुई और जिस अस्पताल में उसका इलाज होते हुए उसका देहांत हुआ, वहां के स्थानीय विधायक ने पब्लिक स्टेटमैंट में कहा था कि मण्डी के लोग इलाज के लिए कुल्लू क्यों आते हैं? ऐसा कहना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जय राम ठाकुर स्वंय मुख्य मंत्री रहे तो उन्होंने अपने क्षेत्र में बड़ा अस्पताल क्यों नहीं खोला? मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र के बालीचौकी में सिविल अस्पताल खोला था लेकिन उसे इस सरकार ने डिनोटिफाई कर दिया जबकि उसका भवन बन कर तैयार है। मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस मामले की जांच रिपोर्ट के मुताबिक सही बात क्या है? एक परिवार ने बेटी, एक पति ने पत्नी और एक बच्चे ने मां खोई है। इसके बावजूद भी इस पूरे मामले की जांच जो अभी तक स्पष्ट होनी चाहिए थी, वह स्पष्ट नहीं हो पाई है और सारी चीजें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। ऐसे में मंत्री जी स्पष्ट करें कि अभी तक जो रिपोर्ट विचाराधीन है, वह कब तक आएगी और उसमें सच्चाई क्या है? ताकि हम परिवारजनों को पूरी सच्चाई बता सकें।

स्वास्थ्य मंत्री श्री ए0पी0 के पास...

31.08.2026/1435/एच0के0/ए0पी0-01

प्रश्न संख्या 4552 जारी .....

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि जून, 2026 में जो यह दुःखद प्रकरण हुआ है जिसमें महिला की दुःखद मृत्यु हुई है। जिसकी संवेदना सभी के साथ है, there is no doubt in it. They have lost a young wife, and I, myself spoke with Late Smt. Manju's husband, उनके सामने हाथ जोड़े की बेटा, ऐसी बात नहीं है, हम भी आपके साथ ही हैं। यह जो दुःखद घटना हुई है। Really speaking, I am not technically qualified, but I think medical things have to really go into this, that's why it is taking so much time. माननीय मुख्य मंत्री महोदय, इस मामले में दो प्रकार की जांच बैठानी पड़ी। पहली जांच it was at Medical Superintendent's level, the second, was at the Joint Director of Health's level. And that is the reason why it is taking so much time. After all what happened between that 9:15 am and 1:30 pm. That will definitely be put in front of you. यह वारदात जो कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में हुई और वहां पर लोगों का जो रोष है, वह इस मामले में स्वाभाविक है। परंतु मैं समझता हूं कि ऐसा कोई डॉक्टर नहीं होगा जो चाहता हो कि उसके द्वारा जिस मरीज का इलाज किया जा रहा है, उसकी मृत्यु हो जाए। मैं सच आपको बताता हूं and it has come up at many levels, and I personally know that is why I spoke to them, ऐसी बात नहीं है कि डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया होगा। However, the behaviour probably that came शायद उसी वजह से 30 जून को जो संबंधित डॉक्टर थीं, उन्हें सस्पेंड किया गया। And the scrutiny is under process and I think we will have to wait for that report. इसलिए मैंने कहा कि मामला विचाराधीन है।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक चीज़ जानना चाह रहा हूं कि जो उत्तर दिया है, इसके भाग-ख और भाग-ग में कहा है कि -जी हां। जी हां का मतलब है कि आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि लापरवाही हुई है। अगर लापरवाही हुई है तो लापरवाही किसके स्तर पर हुई? देखिए, मैं डॉक्टर के बारे में नहीं कह रहा हूं क्योंकि डॉक्टर आदमी की ज़िंदगी बचाने के लिए होता है और इस मंशा के साथ कोई डॉक्टर

ऐसा नहीं करता। इस बात को लेकर मैं डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूं। लेकिन उसके बावजूद दूसरा पक्ष भी आप देखिए कि आखिरकार उस बेटी की दुःखद मृत्यु हुई है। उसका छोटा

31.08.2026/1435/एच0के0/ए0पी0-02

बच्चा छूट गया है। ऐसी सूरत में अगर लापरवाही हुई है, जिसे आपने उत्तर में स्वीकार किया है तो उस वक्त लापरवाही किस स्तर पर हुई है? दूसरा, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जॉइंट डायरेक्टर के स्तर पर जो कमेटी गठित की गई है, उसकी जो इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी, उसका जवाब कब आएगा? हमें उस इंक्वायरी रिपोर्ट के लिए कितने लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा? उसमें कितना समय लगेगा? तीसरा, जो लोग आंदोलन में बैठे थे, उन सारे लोगों के ऊपर मामले दर्ज करके रखे हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट भी आपने तुरंत बंद कर दिए कि पता नहीं क्या अराजकता फैल जाएगी। यहां हमारे खिलाफ सुबह से शाम तक आपने चार-चार पेज चलाकर रखे हैं। सुबह से शाम तक वे गाली देते हैं। उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज है, लेकिन वह पेज अभी भी गाली देने के लिए जारी है। अध्यक्ष महोदय, मैं पहले इन दो चीज़ों को लेकर मुख्य मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि अगर आपने उत्तर में स्वीकार किया है कि लापरवाही हुई है तो लापरवाही किस स्तर पर हुई है और क्या कार्रवाई की जानी है?

Speaker : What action is likely to be taken against them?

माननीय मुख्य मंत्री ....श्री ए0टी0 जारी....

31.08.2026/1440/AT/AG /01

प्रश्न संख्या 4552 जारी......

मुख्य मंत्री : हम आपकी हर बात सुनते हैं। आप चिंतित न रहें। आप प्यार से बोला करो। आठ मिनट में आपने प्रश्न पूछा है। जब आप आठ मिनट में प्रश्न पूछते हैं, अब थोड़ा-सा जवाब तो देना पड़ेगा। वैसे तो माननीय मंत्री जी ने कुछ चीजों को स्पष्ट किया है। मैं इस बारे में आपको और स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आपका भी मुझे फोन आया था कि कुल्लू में

एक ऐसी घटना हुई है और उस घटना के संबंध में फोन आने के बाद हमने उस पर तुरंत कार्रवाई की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर कुछ तथ्य हमारे सामने आए और मैं वे तथ्य सदन के सामने भी रखना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय,मैं इस सदन के माध्यम से एक अत्यन्त दुःखद एवं संवेदनशील घटना के संबंध में तथ्य स्पष्ट करना चाहता हूं। पर सबसे पहले, मैं स्वर्गीय रजनी शर्मा, उर्फ मंजू उम्र मात्र 23 वर्ष, के असामयिक निधन पर अपनी ओर से तथा प्रदेश सरकार की ओर से गहरा दुःख व्यक्त करता हूं। एक परिवार ने अपनी बेटी खोई है, एक पति ने अपनी पत्नी खोई है और एक नवजात बच्ची जन्म लेते ही अपनी मां के स्नेह से वंचित हो गई। ऐसी घटना को केवल आरोप-प्रत्यारोप या राजनीतिक बहस का विषय बनाना उचित नहीं होगा। सरकार की पहली चिंता यह है कि सच्चाई सामने आए, किसी निर्दोष के साथ अन्याय न हो और यदि किसी स्तर पर दोष अथवा लापरवाही पाई जाती है तो दोषी व्यक्ति, चाहे वह कोई भी हो, कानून से बच न सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष पूरे घटनाक्रम को क्रमवार रखना चाहता हूं। दिनांक 19 जून, 2026 को रजनी शर्मा को गर्भावस्था के कारण प्रसव हेतु क्षेत्रीय अस्पताल, कुल्लू में भर्ती करवाया गया। दिनांक 20 जून, 2026 को ऑपरेशन के माध्यम से उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। दुर्भाग्यवश अगले दिन अर्थात 21 जून, 2026 को उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु की सूचना मिलते ही पुलिस सहायता कक्ष, क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू से थाना कुल्लू को सूचित किया गया और पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मृतका के पिता श्री प्रेम चंद तथा ससुर श्री टेक चंद के बयान बाकायदा दर्ज

31.08.2026/1440/AT/AG /02

किए गए और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। उस समय दोनों परिजनों ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें मृत्यु को लेकर किसी प्रकार का संदेह नहीं है तथा वे पोस्टमार्टम अथवा किसी कानूनी कार्रवाई की मांग नहीं कर रहे हैं। यह तथ्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि पुलिस ने घटना को न तो छिपाया, न किसी शिकायत को दबाया और न ही प्रारम्भिक स्तर पर किसी प्रकार की कार्रवाई से पीछे हटी।

पुलिस मौके पर पहुंची, परिजनों के बयान दर्ज किए और उनका वीडियो रिकॉर्ड भी सुरक्षित किया। यह रिकॉर्ड मैं पहले देना चाहता था, लेकिन उस समय शोकोद्गार था, इसलिए दे नहीं पाया। मैं आपको इसलिए पूरी डिटेल देना चाह रहा हूं।

इसके पश्चात दिनांक 25 जून, 2026 को मृतका के पति श्री सतीश शर्मा द्वारा पुलिस अधीक्षक, कुल्लू को ई-मेल के माध्यम से शिकायत दी गई। यदि मृत्यु के संबंध में हत्या या किसी प्रकार की लापरवाही हुई होती, तो वह व्यक्ति भी उस समय शिकायत करने के लिए सामने आ सकता था। मेरी उनसे भी बात हुई। जिसकी मृत्यु हुई, उसके पति से भी मेरी बात हुई और मैंने उनसे इस बारे में पूछा। उस समय उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने उनसे कहा कि हमारी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और हमने तत्काल प्रभाव से संबंधित डॉक्टर को स्थानांतरित कर दिया।

इसमें डॉ. विवेक, डॉ. अनु तथा ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्सों पर चिकित्सकीय लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए गए। शिकायत में उच्च रक्तचाप एवं प्रसव संबंधी जटिलताओं के बावजूद समय पर उचित उपचार एवं चिकित्सकीय निर्णय न लेने, सीजेरियन ऑपरेशन में कथित देरी, रक्तचाप की पर्याप्त निगरानी न करने, आवश्यक दवाइयों, ऑक्सीजन एवं रक्त की व्यवस्था में कमी तथा वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा उचित पर्यवेक्षण न किए जाने जैसे आरोप लगाए गए। सरकार ने इस शिकायत को हल्के में नहीं लिया। शिकायत प्राप्त होते ही इसे आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रभारी थाना कुल्लू को भेजा गया। साथ ही यह भी ध्यान में रखा गया कि चिकित्सा लापरवाही का प्रश्न केवल पुलिस अधिकारी की व्यक्तिगत धारणा के आधार पर तय नहीं किया जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Jacob Mathew बनाम State of Punjab & Another में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार ऐसे मामलों में सक्षम एवं स्वतंत्र चिकित्सकीय राय अत्यन्त

31.08.2026/1440/AT/AG /03

महत्वपूर्ण होती है। इसी कारण क्षेत्रीय अस्पताल, कुल्लू से पूरा उपचार रिकॉर्ड प्राप्त किया गया और अस्पताल प्रशासन द्वारा गठित पांच चिकित्सकों की समिति ने उपलब्ध मेडिकल रिकॉर्ड, उपचार संबंधी दस्तावेज, ड्यूटी रिकॉर्ड तथा संबंधित डॉक्टरों एवं कर्मचारियों के

कथनों का परीक्षण किया। उपलब्ध रिकॉर्ड एवं जांच के आधार पर यह सामने आया कि मृतका की मृत्यु ऑपरेशन तथा बच्ची को जन्म देने के उपरांत हुए अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुई। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने केवल अस्पताल की अपनी आंतरिक समिति की रिपोर्ट पर ही मामला समाप्त नहीं कर दिया।

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी.....

30.08.2026/1445/av/ag/1

प्रश्न संख्या : 4552 क्रमागत------मुख्य मंत्री जारी------

मृतका के पति तथा पिता द्वारा दिनांक 03 जुलाई, 2026 को पुनः शिकायत प्रस्तुत किए जाने पर मामले को फिर गंभीरता से लिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कुल्लू के अनुरोध पर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हिमाचल प्रदेश को दिनांक 07 जुलाई, 2026 को पत्र लिखकर एक स्वतंत्र चिकित्सा विशेषज्ञ बोर्ड गठित करने तथा यह स्पष्ट राय देने को कहा गया कि क्या इस मामले में किसी चिकित्सक अथवा चिकित्सा कर्मी की ओर से ऐसी लापरवाही हुई है जिसका मृतका की मृत्यु से संबंध हो सकता है।

उस स्वतंत्र विशेषज्ञ चिकित्सा राय की प्रतीक्षा की जा रही है। रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात तथ्यों, मेडिकल रिकॉर्ड तथा विशेषज्ञ निष्कर्षों के आधार पर कानून के अनुसार जो भी कार्रवाई बनती होगी; बिना किसी दबाव, पक्षपात अथवा संरक्षण के की जाएगी।

माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने विरोध प्रदर्शन के संदर्भ में भी बात कही है। अध्यक्ष महोदय, इस मामले का एक दूसरा पहलू भी है जिसे तथ्यों के साथ समझना आवश्यक है। दिनांक 29 जून, 2026 को फेसबुक पर की गई अपीलों के माध्यम से लगभग 2,000 से 2,500 व्यक्ति क्षेत्रीय अस्पताल, कुल्लू में एकत्रित हो गए। वे अस्पताल परिसर में प्रवेश कर गए और नारेबाजी करते हुए संबंधित डॉक्टर तथा स्टाफ नर्स को सेवा से हटाने की मांग करने लगे।

लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को अपनी बात कहने, शिकायत करने और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध व्यक्त करने का अधिकार है। यह सरकार उस अधिकार का सम्मान करती है।

लेकिन किसी अस्पताल के भीतर ऐसा प्रदर्शन जिससे मरीजों का उपचार बाधित हो अथवा उनकी सुरक्षा खतरे में पड़े, किसी भी जिम्मेदार सरकार द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोई मरीज ऑपरेशन वाला बैठा है और बिल्कुल

30.08.2026/1445/av/ag/2

शांति चाहता है, परंतु वे प्रदर्शनकारी हर वॉर्ड में गए। उन्होंने हर वॉर्ड में जाकर डॉक्टर्ज व अन्य स्टाफ को धमकाया। ...(व्यवधान) मैं सदन के समक्ष सच्चाई रख रहा हूं। ...(व्यवधान) आप सुन लीजिए। उस समय क्षेत्रीय अस्पताल में 218 मरीज भर्ती थे और 11 मरीज आपातकालीन सेवाओं में उपचाराधीन थे। प्रदर्शनकारी अस्पताल के महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील रोगी-उपचार क्षेत्रों से भी होकर गुजरे। ऐसी स्थिति में भर्ती मरीजों, गंभीर रोगियों, चिकित्सकों, नर्सों तथा अस्पताल की आपातकालीन व्यवस्था की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन और पुलिस का वैधानिक दायित्व था। हमारी सरकार को जनता ने चुनकर भेजा है। हम जहां एक तरफ जांच करवा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में जो गरीब आदमी अपना ऑपरेशन इत्यादि करवाने आते हैं; उसकी जिम्मेवारी भी सरकार की होती है। हमारी सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती और हम तो किसी को जानते भी नहीं हैं।

इस घटना के संबंध में दिनांक 01 जुलाई, 2026 को एफ0आई0आर0 न0. 101/2026, धारा 132, 189 (1) एवं 191(2), भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत बंटी सुराजी, संजय चौहान एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस थाना कुल्लू में दर्ज की गई। अस्पताल में हुड़दंगबाजी रोकना और शांति बनाए रखना भी सरकार का दायित्व है।

लेकिन यहां भी सरकार ने पुलिस की प्रारम्भिक कार्रवाई को अंतिम सत्य मानकर आंखें बंद नहीं कीं। मामले की निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (SIT) गठित किया गया। जांच के दौरान उपलब्ध तथ्यों तथा चिकित्सकों के बयानों के आधार पर धारा 132 बी0एन0एस0 को मामले से हटा दिया गया है और शेष मामले में जांच कानून के अनुसार जारी है।

सरकार का पक्ष बिल्कुल स्पष्ट है और मैं सदन को स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस सरकार का उद्देश्य न डॉक्टर्ज को बचाना है, न प्रदर्शनकारियों को प्रताड़ित करना और न किसी परिवार की पीड़ा को दबाना है। यदि स्वतंत्र

टी सी द्वारा जारी

31.08.2026/1450/टी0सी0वी0/ए0एस0-1

प्रश्न संख्या : 4552. क्रमागत------मुख्य मंत्री ... जारी

या कोई अन्य व्यक्ति, सरकार किसी को संरक्षण नहीं देगी। उसी प्रकार यदि किसी विरोध प्रदर्शन के दौरान कानून का उल्लंघन हुआ है तो उसकी जांच भी निष्पक्षता से होगी लेकिन केवल विरोध करने के कारण किसी निर्दोष व्यक्ति को नहीं फंसाया जाएगा। इसी उद्देश्य से एस0आई0टी0 बनाई गई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के माननीय नेताओं से भी निवेदन करना चाहता हूं कि 23 वर्षीय बेटी की मृत्यु और एक नवजात बच्ची के सिर से मां का साया उठ जाने जैसी पीड़ादायक घटना को राजनीतिक लाभ-हानि के चश्मे से न देखा जाए। यदि विपक्ष के किसी माननीय सदस्य के पास इस मामले से संबंधित कोई तथ्य, मेडिकल रिकॉर्ड अथवा अन्य विश्वसनीय सामग्री है तो वह सरकार अथवा जांच एजेंसी को उपलब्ध करवाएं। हर तथ्य की जांच होगी और सरकार को सत्य से कोई भय नहीं है लेकिन बिना विशेषज्ञ चिकित्सा राय के सदन के भीतर ही किसी डॉक्टर को अपराधी घोषित कर देना भी न्याय नहीं होगा और दूसरी ओर पीड़ित परिवार की शिकायत को बिना निष्पक्ष जांच के खारिज कर देना भी न्याय नहीं होगा। हम दोनों में से कोई गलती नहीं करेंगे। रजनी शर्मा अब वापस तो नहीं आ सकती लेकिन उनके परिवार को यह विश्वास अवश्य होना चाहिए कि उनकी बेटी की मृत्यु के वास्तविक कारण की निष्पक्ष जांच हुई है। प्रदेश के डॉक्टरों तथा स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी यह विश्वास होना चाहिए कि बिना प्रमाण और विशेषज्ञ राय के

उन्हें अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। यही कानून का शासन है और यही निष्पक्षता तथा सरकार की जिम्मेदारी है ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : बहुत-बहुत हो गया, this question has taken more than half an hour. ...(Interruption) नहीं ठाकुर साहब, please bear with me now. This question has taken more than half an hour time. ...(व्यवधान) हो गया। डिटेल्ड रिप्लाई दे दिया है। आप अभी भी संतुष्ट नहीं हैं तो नियम- 61 में पूछ लेना। ...(व्यवधान) जांच जल्दी कर देंगे।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जांच कब तक होगी?

31.08.2026/1450/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच बहुत जल्दी होगी। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : चलिए-चलिए सर, please, this is Question Hour, so don't waste time. Please ...(Interruption) नहीं-नहीं, Hon'ble Leader of Opposition, please, you bear with me. इस प्रश्न को आधा घंटा हो गया है और यह चर्चा हो गई है। इतनी तो रेजोल्यूशन पर भी चर्चा नहीं होती जितनी प्रश्न पर हो गई है। ...(व्यवधान)

31.08.2026/1450/टी0सी0वी0/ए0एस0-3

प्रश्न संख्या : 4553

श्री संजय अवस्थी : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ है लेकिन उत्तर में लिखा गया है कि यह आयुर्वेदिक औषधालय लगभग सात वर्ष से चल रहा है और फंक्शनल है तथा बिना स्टाफ के है। जब स्टाफ के पद सृजित होंगे तभी वहां नियुक्ति की जा सकती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से आयुष मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वहां जो स्टाफ रिक्वायर्ड है उनके पद सृजित किए जाएं और उनकी रेगुलर अपॉइंटमैंट की जाए।

आयुष मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह इनके ही विधान सभा क्षेत्र का ऐसा मसला नहीं है। पूरे हिमाचल प्रदेश में जब पिछली कांग्रेस सरकार का 2012 से 2017 तक का कार्यकाल था तब ऐसी 21 डिस्पेंसरीज पूरे प्रदेश में थीं जिनमें स्टाफ के पद सृजित नहीं हुए थे। इस संबंध में हमने कार्रवाई की है और जल्द ही आयुष विभाग में रेशनलाइजेशन कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में ऐसी 21 डिस्पेंसरीज हैं जहां पद सृजित नहीं हुए हैं, वहां ओ0पी0डी0 की संख्या का भी आंकलन किया जा रहा है। जहां तक नई पोस्ट क्रिएशन की बात है उस पर सरकार और विभाग विचार कर रहा है तथा **यह विषय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में भी है। हमने लगभग 15 डॉक्टर्स का रेशनलाइजेशन किया है और जैसे ही मुख्य मंत्री जी से उसकी स्वीकृति मिलेगी वैसे ही इन खाली डिस्पेंसरीज के लिए पद सृजित कर दिए जाएंगे।**

एन0एस0 द्वारा ....जारी

31-8-2026/1455/NS-AS/1

प्रश्न संख्या : 4553-----क्रमागत

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है लेकिन मैं कुछेक बातें कहना चाहता हूं। कई स्थानों पर दो डिस्पेंसरीज हैं वहां एलोपैथिक भी है और आयुर्वेदिक भी है। हम सबका रैशनेलाइजेशन करेंगे और आयुर्वेदिक में जितनी पोस्टों की स्वीकृति रैशनेलाइजेशन के तहत होगी, जैसे कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मर्जर है, रैशनलाइजेशन है या जो भी होगा उसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर की भी नियुक्ति करेंगे। रैशनेलाइजेशन के तहत जहां आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है वहां एलोपैथिक डिस्पेंसरी नहीं होगी। **एलोपैथिक डिस्पेंसरी को दूसरी पंचायत में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस ढंग से पूरी रैशनलाइजेशन करके आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट को स्टाफ की जितनी जरूरत होगी हमारी सरकार उसको पूरा करेगी। आयुर्वेदिक डॉक्टर, फीमेल हैल्थ वर्कर और मेल हैल्थ**

31-8-2026/1455/NS-AS/2

प्रश्न संख्या : 4554

श्री राकेश जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नक्षत्र वाटिका, स्वरोजगार धाम यह एक ही कार्य है। इसके लिए पैसा सैंक्शन हुआ और टेंडर नहीं करवाए गए बल्कि कोटेशन ली गई। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह एक ही कार्य है, जिसे स्प्लिट किया गया और छोटे-छोटे टुकड़े करके फिर कोटेशन ली गई। एक कार्य ऐसा है जो 3,78,000/- रुपये का है, इसमें भी कोटेशन ली गई। इसके क्या कारण हैं? वहां पर सिविल विंग यूनिवर्सिटी में है। सिविल विंग होने के बाद एक्सिअन, एस0डी0ओ0, जे0ई0 सारी फौज होने के बावजूद आप कोटेशन क्यों ले रहे हैं, टेंडर क्यों नहीं कर रहे हैं?

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह वाटिका जो है, यह राज्यपाल महोदय, जो इस यूनिवर्सिटी के कुलपति भी हैं, इसकी परिकल्पना एवं शिलान्यास उनके द्वारा किया गया है। इसमें 7 लाख रुपये का कुल बजट है तो छोटा-सा काम था तो कोटेशन कौन-सी गलत है? इसको करने के लिए कोटेशन भी तो एक तरीका है । उसमें अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो आप बताइए ।

श्री राकेश जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। गड़बड़ी का प्रश्न नहीं है। जल शक्ति विभाग और पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग में सवा लाख, डेढ़ लाख, दो लाख, अढ़ाई लाख और तीन लाख रुपये के टेंडर होते हैं। जब वहां आपके पास सिविल विंग है तो उनसे काम क्यों नहीं करवा रहे हैं? यह ठीक है कि राज्यपाल महोदय ने इसका शिलान्यास किया। इसका मतलब क्या यह है कि राज्यपाल महोदय ने यह कहा कि आप कोटेशन लीजिए, टेंडर मत कीजिए? यह छोटा मामला नहीं है। वहां पर लगभग 10 लाख रुपये या 9 लाख रुपये का निर्माण कार्य हो रहा है। वहां आपके पास एक्सिअन, एस0डी0ओ0 और जे0ई0 है। आप टेंडर क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है, मंशा क्या है, मैं यह जानना चाहता हूं? अगर उसमें गड़बड़ी हुई हो तो वह बाद का विषय है। जब हमारे पास सिविल विंग वहां

पर है तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि टेंडर न करके कोटेशन मांगने की क्या मंशा है?

31-8-2026/1455/NS-AS/2

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को पूरी जानकारी दे दी गई है। कोटेशन में कितने लोग थे, किसने सबसे कम भरा है, उसमें ऐसा करने का यह भी एक तरीका है। सबसे कम समय में यह काम होना था तो इसको कर लिया गया है।

अध्यक्ष : चलिए, चलिए, ...(व्यवधान) बस हो गया राकेश जी, हो गया, हो गया। वह 7 लाख रुपये का काम है,...(व्यवधान) अगर आप उसमें कोई गड़बड़ी देखते हैं तो बताओ इसकी इन्क्वायरी हो जाएगी। श्री राकेश जम्वाल जी अब आपकी अंतिम सप्लीमेंटरी है।

श्री राकेश जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि 3,78,000/- रुपये का कोई एक कार्य और उसके बाद एक 56,000/- रुपये का काम और ये सारे काम एक ही हैं। नक्षत्र वाटिका, जल निकाय/फव्वारा, प्रवेश द्वार, रैंप और जल निकाय, ये सारे एक ही नक्षत्र वाटिका के काम हैं। उनको स्प्लिट करके छोटे-छोटे कार्यों में बांटकर कोटेशन ली गई है। यहां पर मुख्य मंत्री जी बैठे हैं तो क्या पी0डब्ल्यू0डी0 और जल शक्ति विभाग में भी इसी प्रकार से होता है?

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये जो काम हैं, वहां कोई छोटे-छोटे द्वार हैं, कोई वाटिका है तो इसको तेजी से करने के लिए हमने यह प्रक्रिया अपनाई है। इसमें अगर कहीं गड़बड़ी है तो आप बताइए। मुझे तो यह लगता है कि इनका कोई आदमी रह गया, जिसको टेंडर नहीं मिला, आप उसका भी नाम बता दें।

अगला प्रश्न ----आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

31.08.2026/1500/RKS/DC-1

प्रश्न संख्याः 4555

श्री नीरज नैय्यर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री के समक्ष एक मांग रखना चाहता हूं और एक प्रश्न भी पूछना चाहता हूं। हाल ही में चंबा मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ है और वहां अभी केवल तीन ओ0पी0डी0 शुरू की गई हैं। फर्नीचर एवं फिक्स्चर के लिए शीघ्र ही टैंडर होने जा रहा है। जब यह संस्थान पूर्ण रूप से नए भवन में शिफ्ट होकर फंक्शनल होगा तब लगभग डेढ़ सौ से दो सौ पदों को भरना आवश्यक होगा। इनमें सिक्योरिटी गार्ड, प्लंबर, सफाई कर्मचारी और पी0एस0ए0 प्लांट सहित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारी शामिल हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा और जब आप चम्बा दौरे पर आए थे तो उस समय हमने यह मांग रखी थी कि आप इन पदों को आउटसोर्स आधार पर अति शीघ्र स्वीकृति करने की कृपा करें ताकि मेडिकल कॉलेज अगले एक-दो माह में सुचारू रूप से संचालित हो सके।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का प्रयास है कि आई0जी0एम0सी0, चमियाणा मेडिकल कॉलेज और अन्य सभी मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़ किया जाए। इस विषय पर विभिन्न स्थानों पर हमारी इंटरैक्शन हुई है और अंतिम इंटरैक्शन चंबा मेडिकल कॉलेज में हुई थी जिस समय आप भी उपस्थित थे। माननीय सदस्य लगभग 200 पदों को भरने की मांग कर रहे हैं जबकि हमने 311 पद स्वीकृत किए हैं। चंबा एक दूरस्थ क्षेत्र है इसलिए चंबा मेडिकल कॉलेज को प्रभावी ढंग से कैसे संचालित किया जाए यह सोचने की बात है। आज स्थिति यह है कि हम डॉक्टरों को 5 लाख रुपये तक देने के लिए तैयार हैं फिर भी वहां डॉक्टर नहीं जा रहे हैं। अनेक पदों के लिए विज्ञापन जारी किए जाते हैं किंतु वे पद भर नहीं पाते। इसलिए चंबा के लिए हमें अलग से सोचना पड़ेगा। इस संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ भी चर्चा हुई है। आपने भी कहा था कि चंबा के लिए अलग से पद सृजित किए जाएं और विशेष प्रोत्साहन दिया जाए। मेडिकल हैल्थ सैक्टर को सुदृढ़ करने के लिए हम एक ऐसी योजना पर कार्य करेंगे जिसमें आपकी राय भी ली जाएगी। हम यह भी विचार करेंगे कि चंबा के लिए अलग से पद कैसे सृजित किए जाएं। गाइनेकोलोजिस्ट, डायग्नॉस्टिक तथा अन्य महत्वपूर्ण विभागों को मजबूत करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अन्य बीमारियों के उपचार से संबंधित विभागों को भी सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।लगभग 5-6 विभागों एवं फैकल्टी को विशेष रूप से मजबूत करने पर हमारी सरकार ध्यान केंद्रित

31.08.2026/1500/RKS/DC-2

कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि वर्तमान में हमारे प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में आई0जी0एम0सी0 और टांडा मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। टांडा कॉलेज को भी सुदृढ़ बनाने में हमें काफी समय लगा है। लगभग 40 वर्षों से ऐसी स्थिति रही है कि अनेक स्थानों पर फैकल्टी की पूर्ण उपलब्धता नहीं है। आज हम प्रोफैसरों को 5 लाख रुपये दे रहे हैं किंतु वे भी वहां जाने के लिए तैयार नहीं हैं। कई प्रोफैसर दुबई चले जाते हैं लेकिन जब हम उन्हें 5 लाख रुपये देने की बात कर हमीरपुर या नेरचौक मेडिकल कॉलेज जाने का आग्रह करते हैं तो वे वहां जाने के लिए तैयार नहीं होते। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार कार्य कर रही है और हम इस विषय पर शीघ्र निर्णय लेकर माननीय सदस्य को भी अवगत करवाएंगे। सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए एक समग्र नीति तैयार करने पर कार्य चल रहा है ताकि आम लोगों व समाज के सभी वर्गों को लाभ मिल सके। हमने उस नीति पर कार्य करना शुरू कर दिया है।

अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त। अब शून्य काल होगा। शून्य काल में अनेक विषय लिए जाने हैं क्योंकि पिछले कई दिनों से कई मामले लंबित हैं। मैं इन सभी विषयों को एक-एक करके लूंगा। आज भी मेरे पास लगभग 14 विषय सूचीबद्ध हैं। यदि सभी माननीय सदस्य सहयोग करेंगे तो सभी 14 विषय आज ही डिस्कस हो जाएंगे। आप एक निश्चित एवं सीमित समय के भीतर अपना विषय रखें। मैं माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि वे अपना विषय रखें।

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न भोरंज विधान सभा क्षेत्र से संबंधित है। भोरंज विधान सभा क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से कई महत्वपूर्ण बस रूट बंद पड़े हैं। विशेषकर कोरोना काल के दौरान इन रूटों को बंद किया गया था लेकिन आज तक उन्हें पुनः बहाल नहीं किया गया है। इससे जहां आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वहीं स्कूलों एवं कॉलेजों के बच्चों और कर्मचारियों को भी आवागमन में भारी परेशानी हो रही है।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

31.08.2026/1505/बी.एस./डी.सी.-1

शून्य काल जारी...श्री सुरेश कुमार जारी...

मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में एक बस हमीरपुर-जाहू-भोरंज होकर जाती थी। एक बस हमीरपुर-शिमला वाया भोरंज जाती थी और एक बस हमीरपुर-चंद्रुही वाया चबोह जाती है। ये तीनों बसें पिछले कई दिनों से बंद पड़ी हैं।

इसी तरह से हमारे यहां ग्रामीण क्षेत्रों में गांव दिम्मी, भजवाड़, कलेड़ा, रियाड़ा धमरोल, सारमी, भोंखर, लझाणी, दसमल, झाड़तू, भरेड़ी और डाडू आदि जो गांव हैं वे पूरी तरह से इन बसों के ऊपर निर्भर थे। इन बसों के बंद होने से वहां लोगों को भारी परेशानी हो रही है।

मेरा मंत्री जी से और सरकार से निवेदन रहेगा कि इन बस रूटों को शीघ्र चलाया जाए और जहां-जहां भी ये पुराने रूट थे वहां इलैक्ट्रिक बसों का प्रावधान किया गया है। यही मेरा प्रश्न था। मेरा मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि इन बस रूटों को जल्दी बहाल किया जाए, धन्यवाद।

31.08.2026/1505/बी.एस./डी.सी.-2

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बसों से जुड़ा मसला यहां उठाया है और हाल ही में 35 न्यू बसें हमीरपुर पहुंच गई हैं। माननीय सदस्य वहां जो हमारा लोकल प्रबंधन है उनसे बात करके इसका हल निकाल सकते हैं क्योंकि मुख्य मंत्री जी उसी जिला से आते हैं और बसें वहां ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं, धन्यवाद।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार जी ने जो अभी बसों से संबंधित बात कही है उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि हमारी जो इलैक्ट्रिक बसें हैं उन्हें हम कुछ ही दिनों में आपके इन क्षेत्रों में चलाएंगे। मैं उप-मुख्य मंत्री जी से भी कहूंगा कि इनको वहां से स्टार्ट करवा दीजिए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी, अनुपस्थित नहीं। अगला विषय माननीय श्री बलबीर सिंह वर्मा जी।

31.08.2026/1505/बी.एस./डी.सी.-3

नेरवा बस डिपो को बहाल करने एवं नेरवा में 12 बसें खराब होने के कारण उत्पन्न स्थिति के बारे

श्री बलबीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं उप-मुख्य मंत्री महोदय से यह विनती करना चाहता हूं कि जो हमारा नेरवा का ट्रांसपोर्ट डिपो है उसका संचालन तारा देवी से हो रहा है। पहले इसका संचालन नेरवा से हो रहा था। मेरी आपसे विनती है कि वह डिपों वापस नेरवा से संचालित हो।

सर, हमारी अभी 12 बसें जो पुरानी हो चुकी हैं और खराब खड़ी हैं। इसके साथ ही आपको मैं पिछले दो दिन की बात बता रहा हूं, नेरवा से लेकर सैंज के बीच में मुझे रास्ते में तीन बसें खड़ी मिली हैं। हमारे नेरवा डिपो में 12 पुरानी बसें खड़ी कर दी हैं जिस कारण मेरे 22 रूट बंद कर दिए गए हैं।

इस डिपो में तीन मैकेनिक थे उनमें से दो मैकेनिक छुट्टी पर चले गए। वे रिटायरमैंट पर हैं और वे चार महीने से छुट्टी पर हैं। एक मैकेनिक बचा था उसको रामपुर ट्रांसफर कर दिया। इस वक्त वहां पर कोई भी मैकेनिक नहीं है।

मेरी आपसे विनती है कि जो ये 22 रूट बंद किए हैं उनमें कुछ-न-कुछ बस रूट हमारे जल्दी-से-जल्दी शुरू किए जाएं। चौपाल एक बहुत दूरदराज का क्षेत्र है और बच्चों को स्कूल आने-जाने में बहुत दिक्कत हो रही है सर, मेरी आपसे विनती है कि कुछ-न-कुछ बस रूट जल्दी-से-जल्दी शुरू करने की कृपा करें और नेरवा डिपों का जो संचालन शिमला, तारा देवी से हो रहा है वह नेरवा से ही हो।

31.08.2026/1505/बी.एस./डी.सी.-4

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में हम 3,000 बसें चलाते हैं और बसें जो हैं वे आसमान के तले ही खड़ी होनी हैं। कौन-सी बस कहां खड़ी है? इसको लेकर आजकल यही लगा हुआ है कि यह बस यहां खड़ी है, बस ने कहीं-न-कहीं तो खड़ी होना है।

प्रदेश में जब हम बसें चलाते हैं तो हर बस किसी गैरेज में थोड़ी जाएगी। बसें कहीं-न-कहीं तो खड़ी होंगी। जो बसें कंडम हो गई हैं उनकी फोटो खींचकर लगा देते हैं और सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और कहते हैं कि इस बस का टायर नहीं है।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

31.08.2026/1510/DT/HK-1

शून्य काल जारी...

उप-मुख्य मंत्री जारी...

जो बसें कंडम हो गई हैं उनकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दी जाती हैं। जो बसें कंडम हो गई हैं और साइड में खड़ी हैं उनके संबंध में एक नया ट्रेंड और एक नया फैशन शुरू हो गया है कि खराब बसों को भी दिखाते रहें। चार-पांच बसें किसी जगह पर खड़ी हुई हैं जहां उन्हें साइड में खड़ा किया जाता है। उनमें बैटरी नहीं है तो कहा जाता है कि इनमें बैटरी नहीं है। किसी बस का टायर पंचर हो जाता है तो कहा जाता है कि देखो इसका टायर पंचर हो गया। यह नया फैशन शुरू हो गया है। ऐसा नहीं हैं कि वे बसें वर्कशॉप में जाने वाली नहीं हैं। वे बसें खत्म हो गई हैं और साइड में खड़ी हैं। उनकी नीलामी होनी है तथा उन्हें कबाड़ में ले जाना है।

अध्यक्ष महोदय, अभी नई बसें आई हैं। तीन सौ नई बसें जहां-जहां चल सकती हैं वहां उनको हम भेज रहे हैं। जो बसें इलेक्ट्रिक हैं उस स्थान से जहां से डीजल की बसें हटेंगी वहां पर इलेक्ट्रिक बसों को भेजा जायेगा। डीजल की बसें डिपो खड़ी नही करनी उन्हें भी चलाना है। अब यह भी हो गया है कि इलेक्ट्रिक बस भी लेनी है तथा डीजल की बस भी नहीं देनी है। ऐसा है कि जहां इलेक्ट्रिक बसें नहीं जाएंगी वहां डीजल की बसें जाएंगी। जहां इलेक्ट्रिक बसें गई हैं वहां से डीजल की बसें रिप्लेस उन क्षेत्रों में भेजा जायेगा जहां इलेक्ल्ट्रिक बसें नहीं चल सकती। जहां इलेक्ट्रिक बसें पहुंच गई हैं वहां से डीजल की बसें

निकालकर आपके यहां भेज देंगे ताकि वहां बसों का संचालन हो सके। एक-एक बस को गिनना बंद करो कि वहां तीन बसें खराब खड़ी हैं, वहां ऐसा हो रहा। न जाने आपको कौन ये सूचनाएं देता है। आखिर जब तीन हजार बसों का फ्लीट चल रहा है तो कुछ न कुछ तो दिखाई देगा। कई बार तो की प्राइवेट कार में ही दिक्कत आ ही जाती है। इसलिए क्योंकि माननीय सदस्य के क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बसें नहीं चल सकती इसलिए हम वहां डीजल की बसें भेजेंगे। जिन डिपो में इलेक्ट्रिक बसें पहुंच गई हैं वहां से डीजल की बसें निकालकर माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र में भेजेंगे ताकि इनके क्षेत्र में बसों को रूट चलते रहें। नहीं तो फिर आप कह देंगे कि यहां इलेक्ट्रिक बस चल रही है और यह जमीन के साथ लग गई है तथा यह अपने यहां चार्जिंग स्टेशन तक भी नहीं पहुंच पा रही है।

31.08.2026/1510/DT/HK-2

इसलिए आपकी जो भी रिक्वायरमैंट है उसको हम डिमांड के हिसाब से पूरा कर देंगे। मैं माननीय सदस्य को यह कहता हूं कि मेहरबानी रखोगे। जो बसें कंडम हो गई हैं जो बसें खराब हो गई हैं और जो बसें साइड में लगाकर रखी हैं उनकी गिनतियां करना बंद कर दो।

अध्यक्ष : माननीय बलबीर सिंह वर्मा जी कृपया बैठ जाइए। अगला विषय श्री सुधीर शर्मा जी उठाएंगे।

श्री सुधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश में बी0पी0एल0 परिवारों के चयन हेतु भूमिहीन होने की श्रेणी में तीन बिस्वा भूमि से कम धारकों को पात्रता में रखा गया है तथा पूर्णतः भूमिहीन व्यक्तियों को भी इसमें रखा गया है। पूर्णतः भूमिहीन व्यक्ति जो प्रदेश में हैं अगर वे हिमाचली हैं तो उनके लिए हिमाचली नागरिकता के कौन-कौन से दस्तावेज देना जरूरी होता है? अगर एग्रीकल्चरिस्ट है तो तब होगा जब भूमि होगी। पूर्णतः भूमिहीन व्यक्ति जो इस प्रदेश में हैं उनको क्या-क्या दस्तावेज देना जरूरी है? क्या इसके लिए सरकार द्वारा कोई सूची बनाई गई है कि उनका चयन किस प्रकार से होगा?ऐसा तो नहीं है कि इसके आड़ में प्रवासी लोग या बाहर के लोग हैं वे भी इस सूची में

शामिल हो रहे हैं? इसके ऊपर सरकार किस तरह से कार्य कर रही है तथा सरकार ने इस चयन के लिए क्या नियम बनाए हैं; यह मैं जानना चाहता हूं?

अध्यक्ष : Nobody wants to intervene. Hon'ble Member you have brought a very important issue to the notice of this House, and we have taken cognizance of this issue. We will take up this issue with the Government, and with the respective departments, and whatever reply, response that Vidhan Sabha Secretariat receives, we will be informing you also, and we will direct the department to respond to this proposition. धन्यवाद। अब माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल जी।

31.08.2026/1510/DT/HK-3

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जीरो आवर में यह विषय ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। आए दिन काफी लंबे कट लगते हैं। जब बिजली नहीं होती है तो पीने के पानी की जो हमारी स्कीम्स हैं वे भी नहीं चलती हैं। जब स्कीम्स नहीं चलेंगी तो पानी की सप्लाई भी बाधित होगी। बिजली की समस्या से आजकल प्रत्येक घर में चाहे पंखा हो चाहे मोबाइल चार्जिंग का काम हो चाहे वॉशिंग मशीन हो सब कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

श्री एन0जी0द्वारा जारी...

31.08.2026/1515/एच.के.-एन.जी./1

श्री त्रिलोक जम्वाल......... जारी

बिजली की समस्या आजकल प्रत्येक घर में है और चाहे पंखा हो, मोबाइल चार्जिंग हो या वॉशिंग मशीन हो, आज हर चीज बिजली पर निर्भर है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे बिलासपुर सदर विधान सभा क्षेत्र में चाहे कुटहेड़ा का क्षेत्र हो, वहां पर पूरा-पूरा दिन बिजली नहीं आती। इसके अलावा बलस्वाय-हवाण का एरिया हो, माखड़ी-मरकंड का एरिया हो या धार का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में एक तो लो-वोल्टेज की समस्या है और दूसरी बिजली के बार-बार कट लगने की समस्या है। ये दोनों समस्याएं बहुत गंभीर हैं क्योंकि आजकल बच्चों की पढ़ाई और कोचिंग भी अधिकतर ऑनलाइन ही होती है। अगर बिजली नहीं होगी, तो इन सभी समस्याओं का सीधा संबंध आपस में जुड़ जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से प्रदेश सरकार से यही विनती है कि आर0डी0एस0एस0 (RDSS) योजना के माध्यम से तथा विश्व बैंक की जो परियोजनाएं चल रही हैं, उनके जिन कार्यों के टेंडर हो चुके हैं, उन्हें तेजी से और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, ताकि मेरे बिलासपुर विधान सभा क्षेत्र के लोगों को लो-वोल्टेज और बिजली कटौती की समस्या से निजात मिल सके। यही मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

Speaker : Again we have taken a cognizance of this important issue and we will be writing to the HPSEBL also and to the concerned Hon'ble Minister. The response we get that we will apprise you also and we will see to it that the problem which you have raised that is taken care of.

अब माननीय सदस्य, श्री सुदर्शन सिंह बबलू जी अपना विषय उठाएंगे।

31.08.2026/1515/एच.के.-एन.जी./2

(माननीय सदस्य, श्री सुदर्शन सिंह बबलू द्वारा शून्य काल के दौरान माता चिन्तपुरनी मन्दिर न्यास के माध्यम से सामाजिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले फंड को पुनः बहाल करने के संदर्भ में उठाया गया मामला।)

श्री सुदर्शन सिंह बबलू : अध्यक्ष महोदय, मेरा विषय मेरे चिन्तपुरनी विधान सभा क्षेत्र के एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर, माता चिन्तपुरनी जी के मंदिर से संबंधित है। अध्यक्ष महोदय, पहले मंदिर के फंड से हम अपने स्थानीय गरीब लोगों तथा आसपास की कुछ पंचायतों के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए और सामाजिक कार्यों के लिए कुछ धनराशि उपलब्ध करवाते थे। लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा इस पर रोक लगा दी गई है कि मंदिर का पैसा सामाजिक कार्यों के लिए खर्च नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि माता चिन्तपुरनी जी के यहां जो मेले आयोजित होते हैं, उनमें स्थानीय लोगों को क्या मिलता है? वहां इतने लंगर लगते हैं और लंगर लगने के बाद इतनी गंदगी फैल जाती है कि अगर समय पर बारिश न हो तो महामारी फैलने का भी खतरा रहता है। इसके बाद भी स्थानीय लोग वहां की इस गंदगी को झेलते हैं। मंदिर के आसपास जितना भी कूड़ा-कचरा होता है, उसे भी स्थानीय लोगों को ही सहन करना पड़ता है। स्थानीय लोगों को क्या मिलता है? उन्हें गंदगी मिलती है, प्रदूषण मिलता है। यहां तक कि बाहर से आने वाले कुछ लोगों में ऐसे लोग भी होते हैं जो नशे व ड्रग्स का कारोबार करते हैं। मेले के समय जब बाहर से लोग आते हैं, तो उसका भार भी स्थानीय लोगों को झेलना पड़ता है। तो क्या इन स्थानीय लोगों के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? हमारे वहां की जो स्थानीय गरीब जनता है, उनके सामाजिक कार्यों, शिक्षा और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए अगर मंदिर के फंड से कुछ पैसा खर्च किया जाए, तो इसमें क्या बुराई है?

31.08.2026/1515/एच.के.-एन.जी./3

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस मामले का जल्द-से-जल्द समाधान किया जाए और मंदिर के फंड से स्थानीय लोगों के हित में किए जाने वाले सामाजिक कार्यों पर लगी रोक को हटाने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। धन्यवाद।

Speaker : I think Hon'ble Deputy Chief Minister wants to intervene.

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और यहां पर चप्पे-चप्पे पर मंदिर हैं। हिमाचल प्रदेश के कुछ मंदिर प्रदेश सरकार के अधीन भी हैं। लगभग तीन दर्जन मंदिर ऐसे हैं, जिनमें से कुछ बड़े मंदिर हैं—माता चिन्तपुरनी जी का मंदिर, माता ज्वाला जी का मंदिर, माता नैना देवी जी का मंदिर, बाबा बालक नाथ जी का मंदिर, माता चामुंडा जी का मंदिर और कांगड़ा माता का मंदिर आदि। ये सभी बड़े मंदिर हैं और इनमें काफी चढ़ावा आता है। इन मंदिरों के माध्यम से पहले सामाजिक कार्यों के लिए भी धनराशि दी जाती थी। पिछले दिनों माननीय हाई कोर्ट का एक फैसला आया, जिसमें कुछ बंदिशें लगाई गई हैं। पहले मंदिरों से अखबारों को विज्ञापन दिए जाते थे, उन्हें बंद किया गया। फिर गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी लगाई गई। डिप्टी कमिश्नरों और दूसरे अधिकारियों को मंदिरों के माध्यम से गाड़ियां उपलब्ध करवाई जाती थीं, उन पर भी रोक लगाई गई। अभी कुछ और पाबंदियां भी माननीय हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई हैं। हम इस मामले की कानूनी रूप से जांच करवा रहे हैं। कानून विभाग से राय लेने के बाद हम माननीय हाई कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दायर कर उनके संज्ञान में यह बात लाना चाहते हैं कि पहले हम मंदिरों से लोगों के इलाज के लिए पैसा खर्च करते थे और बच्चों की फीस के लिए

पी0बी0 द्वारा......जारी

31.08.2026/1520/YK/PB/1

शून्य काल जारी

उप-मुख्य मंत्री ...जारी

दिया जाता है, ऐसे सोशल कॉज़िस के लिए खर्च की जाने वाली राशि को एग्जैम्प्ट किया जाए। इस विषय पर विचार करने के बाद हम दोबारा अदालत में जाएंगे। वैसे हमने इस

मामले को एग्जामिन करवाया है और डिप्टी कमिश्नर्ज को यह कहा है कि जब तक हमारी दोबारा परमिशन नहीं आती है तब तक कम-से-कम इन कॉज़िस पर संज्ञान लेते हुए बच्चों की फीस देने या इलाज करवाने के लिए लोगों की मदद करें। हमारे साथ शुरुआती बातचीत में कानून विभाग ने कहा है कि यह किया जा सकता है। हम आपको लिखित में सूचना देंगे और अदालत में भी इसका पक्ष रखेंगे।

31.08.2026/1520/YK/PB/2

Speaker : Next issue is from Hon'ble Member Shri Satpal Singh Satti.

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र के किसानों की एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में पॉपलर, सफेदा इत्यादि के पेड़ों को कैश क्रॉप माना जाता है। इसमें पहले ऐसी ज्यादा अड़चनें नहीं थी लेकिन वर्तमान सरकार ने कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं, जिनकी ओर मैं मुख्य मंत्री जी जिनके पास वन विभाग भी हैं, का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, पहले पॉपलर या सफेदे का पेड़ काटने के लिए पटवारी, पंचायत, गार्ड, बी0ओ0 या रेंजर की सामान्य अनुमति ली जाती थी और इन्हें काटकर बेचा जाता था। लेकिन वर्तमान सरकार ने अब जो व्यवस्था की है, उसमें पंचायत, पटवारी, गार्ड, बी0ओ0 और रेंजर आदि की प्रक्रिया पूरी करने के बाद पटवारी के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है और मामला रेंजर के माध्यम से डी0एफ0ओ0 के पास भेजा जाता है। डी0एफ0ओ0 के माध्यम से मामला आगे जाने में काफी दिन लग जाते हैं। यदि डी0एफ0ओ0 कहीं बाहर है या दफ्तर में नहीं है या बीच में कोई छुट्टी आ गई और किसान ने फसल काटकर गाड़ी में लाद दी तो डी0एफ0ओ0 के उपलब्ध न होने के कारण यह सारी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में गाड़ी खड़ी रहती है और उसका अतिरिक्त किराया देना पड़ता है।

दूसरी बात यह है कि पहले गाड़ी/ट्रक की कोई फोटो नहीं ली जाती थी। अब व्यवस्था यह कर दी गई है कि पहले गार्ड को ट्रक की फोटो लेनी है, फिर ड्राइवर और ड्राइविंग लाइसेंस आदि की भी फोटो लेनी है। उसके बाद ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करके

500 रुपये प्रति ट्रक भी जमा करवाने पड़ते हैं, जबकि पहले कोई पैसा जमा नहीं करवाना होता था। इसके बाद केस-फाइल आर0ओ0 के माध्यम से डी0एफ0ओ0 के पास ऑनलाइन जाती है और इसमें भी एक-दो दिन लग जाते हैं। ऐसा कई बार ध्यान में आया है कि इसके कारण फसल सूख जाती है। गर्मी का मौसम होने के कारण यदि फसल सूख जाएगी तो उसका मूल्य कम मिलेगा, क्योंकि यह क्विंटल और टनों के हिसाब से बेची जाती है।

31.08.2026/1520/YK/PB/3

तीसरी बात यह है कि इसके लिए पहले कोई फीस जमा नहीं होती थी लेकिन अब प्रति पेड़ 90 रुपये की नई फीस लगा दी गई है। इसके साथ एक और मुद्दा यह है कि फायर सीजन के दौरान पूरे हिमाचल प्रदेश में पेड़ों के कटान पर बैन लग जाता है। यह बैन ठीक है क्योंकि यदि पेड़ों का कटान होगा, चाहे वह किसी भी पेड़ का हो, चाहे ईंधन लकड़ी का हो या खैर इत्यादि का हो तो उससे जंगलों में आग लगने की संभावना रहती है। लेकिन पॉपलर और सफेदा खेतों में होते हैं और खेतों में आग लगने की ज्यादा संभावनाएं नहीं होती है। इन्हीं दिनों गाड़ियां और ट्रक खेतों में जा सकते हैं क्योंकि उस समय फसल कटी होती है और खेत की जमीन सूखने के कारण पक्की हो जाती है। यदि आजकल मानसून में कोई गाड़ी को खेत ले जाने की परमिशन दे भी देगा तो गाड़ी वहां नहीं जाएगी और यदि जाएगी तो किसी खेत में फंस जाएगी। इसलिए फायर सीजन में भी इसके कटान और परिवहन को खुला रखा जाना चाहिए।

इसके साथ-साथ यदि हम कुल खर्च जोड़ें तो इसमें 90 रुपये प्रति पेड़ का खर्च है और 500 रुपये प्रति गाड़ी का खर्च है। फिर किसान को फोटो खिंचवानी पड़ती है। फोटो खिंचवाने के बाद फोटो को अपलोड करना पड़ता है। अब किसान कहां फोटो खिंचवाएगा और कहां उसे अपलोड करेगा? इसके साथ-साथ मैंने जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम गिनवाए हैं, उनका भी अपना एक खर्च है। जब फोटो खिंचवानी है तो खर्च तो लगेगा ही। उन्हें खेत में ले जाना पड़ता है और उनके लिए भी पैसा खर्च करना पड़ता है।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी

31.08.2026/1525/एच0के0/ए0पी0-01

शून्य काल जारी .....श्री सतपाल सिंह सत्ती जारी .....

कुल मिलाकर एक ट्रक का 3,000 रुपये खर्चा आ रहा है। मेरा आदरणीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि यह एक कैश क्रॉप है और पंजाब के अंदर इसके लिए कोई रूल-रेगुलेशन नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं(कृषि मंत्री जी की ओर इशार करते हुए।) इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि इसके ऊपर कोई ऐसा प्रावधान किया जाए। इसमें चोरी का भी कोई लफड़ा नहीं है। जंगल में तो चोरी हो जाती है और पता नहीं लगता, लेकिन मेरा खेत है, मेरे खेत से कौन चुरा कर ले जाएगा? मालिक जो है, वह तुरंत पकड़ लेगा। इसलिए मुझे लगता है कि पोंटा साहब से लेकर नालागढ़ और नूरपुर तक के क्षेत्र में जो यह सारी फसल होती है, उसमें किसानों को राहत दी जाए। अन्यथा किसानों की फसल ओवरडेट हो रही है। सात-से-आठ साल हो गए हैं, जबकि हमारी फसल पांच-छः साल में कट जाती है। अब बीच में पेड़ों में खोल पड़ना शुरू हो गया है और आंधी-तूफान में पेड़ गिर भी गए हैं। इतनी अधिक फसल होने के कारण जो पंजाब से लोग इसे लेने आते हैं, उन्होंने तो इन्हें लेने से भी इनकार कर दिया है। हमारे दो किसानों के तो पैसे भी वापस कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि भाई, हमारे पैसे वापस दे दो, ट्रक यहां खड़ा है और दो दिन में माल सूख भी गया है। मेरा लगभग दो टन माल सूख गया है इसलिए मेरा तो नुकसान हो गया है। मैं अभी डिटेल में नहीं जाना चाहता। आपके ध्यान में यह विषय आ गया होगा और सरकार के ध्यान में भी यह विषय आ गया होगा। इसलिए इसमें राहत दी जाए, ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके, धन्यवाद।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी यहां नहीं हैं, लेकिन यह विषय महत्वपूर्ण है और आपने विधान सभा के संज्ञान में यह विषय लाया है। हम सरकार को इस विषय के बारे में अवगत करवाएंगे और आपकी जो भावनाएं हैं, वे भी सरकार को भेजेंगे। इस विषय पर सरकार का जो जवाब होगा वह भी विधान सभा सचिवालय और आप तक पहुंचाएंगे।

31.08.2026/1525/एच0के0/ए0पी0-02

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री आशीष शर्मा जी।

श्री आशीष शर्मा : अनुपस्थित।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री इंद्र दत्त लखनपाल।

जातीय प्रमाण पत्रों के संबंध में

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल : अध्यक्ष महोदय, हमारे बड़सर विधान सभा क्षेत्र में एक फलेड़ा जाति है और वे अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। समस्या यह है कि पहले उन्हें अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट, यानी प्रमाणपत्र मिलते थे। राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम आज भी फलेड़ा ही हैं, लेकिन कंप्यूटर में उनका नाम फरेरा लिखा हुआ है। अब फरेरा और फलेड़ा नाम में अंतर होने की वजह से उनके अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं। यह प्रश्न मैंने पहले भी लगाया था लेकिन उसके ऊपर अभी तक सरकार की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। बहुत सारे लोग अपने प्रमाणपत्र लेने से वंचित रह गए हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि कंप्यूटर में फरेरा की जगह फलेड़ा लिख दिया जाए ताकि उन्हें इसका लाभ मिल सके, धन्यवाद।

अध्यक्ष : आपके विषय का संज्ञान विधान सभा सचिवालय में लिया गया है। इसको हम संबंधित विभाग को लिखेंगे और की गई कार्रवाई से आपको तथा माननीय सदन को भी अवगत करवाएंगे।

31.08.2026/1525/एच0के0/ए0पी0-03

ऊपरी बल्ह क्षेत्र में पुलिस थाना खोलने तथा नशे की रोकथाम के लिए पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध करवाने बारे।

अध्यक्ष : अब अगला इश्यू, माननीय सदस्य श्री इंद्र सिंह।

श्री इन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका तथा माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र के ऊपरी बल्ह क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं, जहां थाना दिया गया था। क्राइम को देखते हुए वहां चौकी इंचार्ज के साथ केवल चार-पांच व्यक्ति होते हैं, लेकिन क्राइम को देखते हुए रोज वहां पर नई घटनाएं होती हैं। आज चिट्टा (नशे) का जो प्रचलन

चल रहा है, उसे देखते हुए चौकी इंचार्ज और पांच लोग पर्याप्त रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने जो थाना खोला था, उसको दोबारा अधिसूचित किया जाए ताकि लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके। यह क्षेत्र 25 पंचायतों का हब है और इन पंचायतों में पहाड़ी क्षेत्र भी है। उस पहाड़ी क्षेत्र में पांच पुलिस कर्मचारियों से पर्याप्त रूप से काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस नशे को दूर करने के लिए पुलिस विभाग की पर्याप्त व्यवस्था दी जाए, धन्यवाद।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

31.08.2026/1530/AT/AG/01

Speaker: Again, you have brought a very important issue before the House. We have taken a cognizance of this issue. We will take up this issue with the respective department. We will see to it that action is taken. Whatever action is taken, we will inform you and the Vidhan Sabha Secretariat also.

शून्यकाल समाप्त

साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री जी, सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाएंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं जो कि इस प्रकार हैः-

सोमवार, 31 अगस्त, 2026 शासकीय/विधायी कार्य।

मंगलवार, 01 सितम्बर, 2026 शासकीय/विधायी कार्य।

बुधवार, 02 सितम्बर, 2026 शासकीय/विधायी कार्य।

वीरवार , 03 सितम्बर, 2026 शासकीय/विधायी कार्य।

31.08.2026/1530/AT/AG/02

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक की प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

i) हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 10 के साथ पठित धारा 13 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के यात्रा भत्ता (संशोधन) नियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्याः जी.ए.डी.-सी-डी (6)-6/2025, दिनांक द्वारा 27.06.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में प्रकाशित; और

(ii) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 28 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2025-26 (01.04.2025 से 31.03.2026 तक)।

सदन की समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब सदन की समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाएगा। श्री मोहन लाल ब्राक्टा, सभापति, कल्याण समिति, कल्याण समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, कल्याण समिति (वर्ष 2026-27), का 37वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) पर बना समिति के 42वें कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2021-22) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित "अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण" तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित "मुख्यमन्त्री आदर्श ग्राम योजना" से सम्बन्धित की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

31.08.2026/1530/AT/AG/03

नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्षः अब श्री भवानी सिंह पठानिया माननीय सदस्य, अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय कृषि मंत्री महोदय चर्चा का उत्तर देंगे। अगर माननीय भवानी सिंह पठानिया चाहें तो if not satisfied with the reply, you can seek clarification with the permission of the Chair.

श्री भवानी सिंह पठानियाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि "to call the attention of the House regarding the farmers being forced to buy **"Nano Urea Plus"** along with normal urea bag by depot holders".इसके बारे में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक से अधिक मंत्रालय शामिल हैं। कृषि विभाग के साथ-साथ सहकारी समितियां और संबंधित मंत्रालय भी इसमें शामिल हैं। इसमें काफी ज्यादा लोग और संस्थाएं शामिल हैं। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का भी इस विषय की ओर थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

सर, इस समस्या के तीन भाग हैं। पहला, प्रमुख समस्या क्या है। दूसरा, इस समस्या की शुरुआत कहां से हुई। और तीसरा, इसका समाधान हम क्या निकाल सकते हैं।

सर, पहली बात यह है कि अगर आप आज किसी सहकारी समिति में जाकर यूरिया का एक बैग या दो बैग खरीदना चाहेंगे, तो उसके साथ आपको जबरदस्ती नैनो यूरिया प्लस की बोतल या डी0ए0पी0 की लिक्विड बोतल भी लेनी पड़ती है। इसका प्रभाव यह है कि हम एक तरफ कहते हैं कि किसानों की आय बढ़ानी है और दूसरी तरफ हम

उन्हें वह उत्पाद बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जो उन्होंने न कभी मांगा है और न ही उन्हें उसकी आवश्यकता है।

सर, इसकी आर्थिक स्थिति आप देखिए। यूरिया का एक कट्टा लगभग 270 रुपये का है। 270 रुपये के दो बैग 540 रुपये के पड़ते हैं। नैनो यूरिया की एक बोतल 225 रुपये की है। यानी जहां 540 रुपये में किसान का काम हो जाना था, अब उसे लगभग 700 रुपये देकर डिपो या सोसायटी होल्डर से सामान लेना पड़ रहा है। इसमें लगभग 30 प्रतिशत की

31.08.2026/1530/AT/AG/04

वृद्धि हो गई है। यह नैनो यूरिया प्लस किसानों के किसी काम का नहीं है। कम से कम लोअर हिमाचल में जो किसान हैं, वे पता नहीं कितनी बार इसे पूरी तरह अस्वीकार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जबरदस्ती इसे खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

क्योंकि ये किसान हैं, इसलिए आज तक यह मुद्दा इतना कभी प्रमुखता से सामने नहीं आया। आप कल्पना कीजिए कि अगर आप राशन की दुकान पर जाते हैं और दो पैकेट दूध खरीदते हैं और दूधवाला आपको बोलता है जब तक आप यह एपिगैमिया का ग्रीक योगर्ट साथ में नहीं खरीदेंगे और यह आपको खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि यह आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, तब तक मैं आपको दो पैकेट दूध नहीं दूंगा और यह पिछले दो-तीन साल से लगातार चला आ रहा है। इसके पीछे, अगर आप देखें, तो मैंने समस्या का पता करने की कोशिश की कि यह समस्या कहां से शुरू हुई।

सर, इसके पीछे मूल रूप से केंद्र सरकार की जो आवंटन प्रक्रिया है, उसका भी एक बहुत बड़ा हाथ है और इसमें अगर आप देखें तो एक कंपनी है, जो एक सहकारी संस्था है, जिसका नाम आई0एफ0एफ0सी0ओ0 (IFFCO) है। इस समय यह सारी की सारी गुंडागर्दी लगभग आई0एफ0एफ0सी0ओ0 की तरफ से हो रही है। आई0एफ0एफ0सी0ओ0 रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आती है और आई0एफ0एफ0सी0ओ0 क्या करती है कि जब

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी.....

31.08.2026/1535/av/ag/1

श्री भवानी सिंह पठानिया-------जारी

इफ्फको कैमिकल एण्ड फटिलाइजर मिनिस्ट्री के अंदर आती है। इसमें हर हफ्ते कंट्रोल प्राइस की आइटम्ज जैसे यूरिया और फर्टिलाइजर इत्यादि का कोटा तय होता है। मान लो हमारी स्टेट का कोटा 'एक्स' मीट्रिक टन अलॉट हुआ। उसमें नैनो यूरिया प्लस और नैना डी0ए0पी0 इत्यादि को स्टेट को जबरदस्ती एलोकेट किया जाता है। यह एलोकेशन हिमफैड को जाती है और हिमफैड को यूरिया के साथ-साथ नैनो यूरिया प्लस और बाकी सारा सामान भी जबरदस्ती उठाना पड़ता है। उसके बाद हिमफैड उस सामान को सोसाइटीज को देता है और सोसाइटी वाले उस सामान को जबरदस्ती किसान को बेचते हैं। किसान यूरिया को तो यूज़ कर लेते हैं परंतु नैनो की बोतल को सजाकर शैल्फ पर रख लिया जाता है। हमारे छोटे-छोटे किसान की कोई सुनने वाला नहीं है इसलिए ऐसे मुद्दे रेज़ नहीं हो पाते। लेकिन आज से लगभग एक महीना पहले एक किसान ने हमारे समक्ष यह मुद्दा रखा। मैं सोसाइटी के अंदर गया जहां पर सोसाइटी होल्डर ने मुझे एक सर्कुलर दिखाया और कहा कि हमें इस प्रकार के आदेश हैं कि आपको यह सामान बेचना ही है। वह सर्कुलर केंद्रीय सरकार के कृषि मंत्रालय से संबंधित अधिकारी का था। जिसके ऊपर केवल यह लिखा हुआ था कि नैनो यूरिया प्लस को आपको केवल प्रमोट करना है। उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको यह किसानों को जबरदस्ती बेचना है। इस पूरी प्रक्रिया के अंदर मैंने जैसे कहा इफ्फको, इण्डियन पोटाश लिमिटेड, एन0एफ0एल0 इत्यादि मैनुफैक्चरर्ज हैं। हिमाचल प्रदेश को जो कोटा दिया जाता है उसमें इन चीजों को बेचने के

बारे में जबरदस्ती कहा जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका असर न तो इफ्फको को पड़ेगा और न ही हिमफैड और सोसाइटीज को पड़ेगा। इसका फर्क केवल हमारे गरीब किसान को पड़ेगा जिसको यह सामान जबरदस्ती बेचा जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल को केंद्र सरकार में हिमाचल प्रदेश से मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा हैड किया जाता है। मैं यह बताना चाहता हूं कि (***)

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

31.08.2026/1535/av/ag/2

हमारे छोटे-छोटे एक बीघा, दो बीघा या एक एकड़ वाला किसान इसको कहां से अफोर्ड कर पाएगा? इसलिए मेरी दो मांगें हैं। इसमें मेरी पहली मांग यह है कि इसमें प्लेयर को ढूंढा जाए क्योंकि इसमें हमारी केंद्र सरकार एजेंसी है जिसके अंतर्गत इफ्फको और एन0एफ0एल0 इत्यादि सारे हैं। इसमें इनके अधिकारी इंवॉल्व्ड हैं। हो सकता है कि इसमें हमारे हिमाचल प्रदेश की हिमफैड इत्यादि संस्थाएं भी इंवॉल्व हों। इसमें यदि हमें कोई जांच या सुधार करने हैं तो उसको हम विभागीय जांच के आधार पर नहीं कर पाएंगे क्योंकि we need powers which are bigger than perhaps a department. इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप सदन की कमेटी का गठन कीजिए और उसको निर्देश दीजिए कि अगले तीन-चार महीनों के अंदर-अंदर इसकी पूरी जांच की जाए ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। इसके अतिरिक्त इसमें किस प्रकार से सुधार लाकर अपने किसानों का शोषण रोक सकते हैं। उसमें किसानी से संबंधित लोग चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों या कांग्रेस पार्टी से संबंधित हों; उनको शामिल कीजिए तथा एक समयावधि सुनिश्चित करके इस कमेटी का गठन करके उसको रिपोर्ट सब्मिट करने को बोलिए। वरना इफ्फको जैसी कंपनीज का कुछ नहीं बिगड़ेगा परंतु हमारे छोटे-छोटे किसानों को बहुत नुकसान पहुंचेगा। अतः हिमाचल के किसानों के हित में इस कमेटी का गठन होना बहुत जरूरी है और कोशिश करनी चाहिए कि इसकी रिपोर्ट को हम अगले विंटर सेशन के दौरान ले करें।

इसके अतिरिक्त मेरी दूसरी मांग यह है कि अभी तक जिस भी किसान को यह माल जबरदस्ती बेचा गया है, इसकी न तो रसीद मिली है और न ही कोई बिल दिया गया है।

लेकिन सबको पता है कि यूरिया किसने खरीदी है और दो बोरी यूरिया के ऊपर नैनो यूरिया की एक बोतल जो जबरदस्ती खरीदनी पड़ी है; उसको रिफण्ड करवाना हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है। किसानों को उनका पैसा वापिस मिलना चाहिए क्योंकि 540 रुपये के दो कट्टों के ऊपर 225 रुपये की एक नैनो यूरिया की बोतल जिसकी लागत लगभग 30 प्रतिशत बनती है। हम एक तरफ तो किसानों की आय बढ़ाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम किसानों को दे रहे किसान सम्मान निधि को किश्तों में वापिस ले रहे हैं। मैं इसी मुद्दे को सदन के अंदर रखना चाहता था और जैसे मैंने कहा कि it's a multi-ministry issue. **टी सी द्वारा जारी**

31.08.2026/1540/टी0सी0वी0/ए0एस0-1
श्री भवानी सिंह पठानिया... जारी

मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सदन की कमेटी को पावर्स देकर आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री भवानी सिंह पठानिया ने नियम 62 के अंतर्गत एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय इस माननीय सदन में उठाया है और उन्होंने मुख्य रूप से नैनो यूरिया के बारे में विस्तार से बात की है। मैं कई बार रेडियो और टी0वी0 पर नैनो यूरिया के एडवर्टाइजमैंट सुनता हूं। हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नैनो यूरिया का एडवर्टाइजमैंट करते हैं कि किसानों को नैनो यूरिया का उपयोग करना चाहिए क्योंकि यह फसलों के लिए बहुत अच्छी है। इस संदर्भ में रेडियो और टी0वी0 पर काफी लंबी-चौड़ी एडवर्टाइजमैंट आती रहती है। जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इसका एडवर्टाइजमैंट करते होंगे तो किसानों पर उसका क्या प्रभाव होता होगा? कोई किसान सुनता होगा तो वह यही कहेगा कि यह तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, जो किसानों के हितैषी हैं और इसका उपयोग करना चाहिए तथा हम इसका विरोध नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सदन को आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि फर्टिलाइज़र एग्रीकल्चर का इंपोर्टैंट हिस्सा है और अगर फर्टिलाइज़र नहीं होगा तो प्रोडक्शन भी बहुत कम होगी। यह फर्टिलाइज़र एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट के नियंत्रण में नहीं है। इसे भारत सरकार की एजेंसियां और ऑर्गनाइजेशन्स नियंत्रित करती हैं जिसमें इफको (IFFCO) भी शामिल है। इसी तरह हिमफैड को यह बाहर से मिलता है और आगे जाकर हम इसे अपनी एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज को देते हैं जो विभिन्न गांवों में हैं तथा उनके सेल्समैन इसे आगे बेचकर किसानों को देते हैं। किसान जो फर्टिलाइज़र लेता है उसमें 12-32,16, यूरिया, एन0पी0के0 और डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइज़र होते हैं जिन्हें हम अपने डिपो के माध्यम से बेचते हैं। उसके साथ सेल्समैन यूरिया की बोतल भी देते है और कहते हैं कि यह यूरिया की एक बोरी के बराबर है। इस प्रकार की एडवर्टाइजमैंट के माध्यम से किसानों को इसका प्रयोग करने के लिए कहा जाता है।

31.08.2026/1540/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

इसके अच्छे रिजल्ट्स भी हैं क्योंकि किसान यह देखता है कि बोरी में यूरिया लेकर जाए और खेत में डालकर अपना काम पूरा कर दे लेकिन नैनो यूनिया लिक्विड फॉम में है इसलिए इसका बाकायदा स्प्रे करना पड़ेगा। इसके लिए किसानों को स्प्रे पंप चाहिए और एक-एक खेत में जाकर उनको इस लिक्विड का स्प्रे करना पड़ेगा। इसलिए किसान यह सोचता है कि बोरी में यूरिया लेकर जाते हैं और उसको डाल देते हैं तथा हमारा काम पूरा हो जाएगा। लेकिन जब लिक्विड को स्प्रे करेंगे तो उसमें ज्यादा समय लगेगा। स्प्रे करने से हमारी फसल को फायदा तो होता है लेकिन कई बार किसान सोचता है कि एक बोतल को लेकर कौन इतना समय लगाए।

अध्यक्ष महोदय, हमने अपनी तरफ से किसानों और सोसाइटीज को पत्र व्यवहार के माध्यम से अवगत करवाया है कि इस प्रकार की कुछ डायरेक्शन्ज़ पत्र के माध्यम से दी गई हैं। जब श्री भवानी सिंह पठानिया जी का पत्र आया था तब हमारे डायरेक्टर जसरोटिया जी ने भी इन्हें इस विषय से अवगत करवाया था कि यह मैंडेटरी नहीं है और यह किसानों पर निर्भर करता है कि वे इसे लें या न लें। इसी तरह भारत सरकार का

एन0एस0 द्वारा ….जारी

31-8-2026/1545/NS-AS/1

कृषि मंत्री ------जारी

भी एक पत्र Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited यानी इफको ने भी एक चिट्ठी लिखी है। The Department of Agriculture, Himachal Pradesh, vide its communication No. 1-3/2024 Agr-I, dated 28.07.2026, has brought to our notice an allegation regarding the compulsory tagging of Nano Urea with the sale of other fertilizers in the Fatehpur Assembly Constituency. The Department has clearly stated that such practices, if found to be true, are against the prescribed guidelines and are not permissible.

In view of the above, all Field Officers are hereby directed to ensure that no such practice of compulsory tagging, bundling or conditional sale of Nano Urea with any other fertilizer is carried out anywhere in Himachal Pradesh.

Farmers must be allowed to purchase fertilizers strictly according to their requirement and choice, without any form of coercion, pressure or conditional sale. All Field Officers shall accordingly communicate these instructions to the concerned dealers/retailers and ensure that the same are followed in letter and spirit.

It is further directed that Field Officers should maintain strict supervision over the sales practices of dealers/retailers under their respective jurisdictions and immediately report any complaint or instance of compulsory tagging/bundling of Nano Urea to the undersigned.

It may be noted that the Department has specifically warned that if any complaint or report regarding forced tagging of Nano Urea with other fertilizers is received in future and is found to be substantiated, stern action shall be initiated against the concerned agency/dealer.

Accordingly, all Field Officers are advised to exercise utmost caution and ensure that no practice contrary to the prescribed guidelines takes place in their respective areas. The reputation of IFFCO and the trust of farmers must be protected at all times.

31-8-2026/1545/NS-AS/2

This may be treated as Most Urgent and compliance may be ensured with immediate effect. यह इफको की चिट्ठी (सभा में पत्र दिखाते हुए) है। इस इफको की चिट्ठी से मैं यह भी अवगत करवाना चाहता हूं कि जितने भी हमारे सेल्स डिपो हैं उनको वाकायदा यह डायरेक्शन्स देंगे कि as per the direction of IFFCO, you can't force the farmers that they should purchase this Nano Urea. हम उनको डायरेक्शन्स दे देंगे क्योंकि यह सारा कोऑपरेटिव सिस्टम है और इस फर्टिलाइजर को कंट्रोल करने का काम एजेंसियां करती हैं। वे एजेंसियां हमें देती हैं और हम आगे जाकर सेल्स मैन को कहते हैं कि आप इसको अपने डिपो के ऊपर बेचिए। **इसको हम एन्श्योर करेंगे कि हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे कि आप इसको लीजिए।** मैं इसके बारे में आपको अवगत करवाना चाहता हूं। धन्यवाद।

Speaker : Hon'ble Member Shri Bhawani Singh Pathania jee, you want to seek clarification?

31-8-2026/1545/NS-AS/3

श्री भवानी सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, एक तो यह है कि इसको सोसाइटी होल्डर आगे फोर्सफुली नहीं देगा। प्रॉब्लम शुरू तब होती है जब एलोकेशन के टाइम हिमफैड को या बाकी स्टेट गवर्नमैंट को इफको जबरदस्ती माल देती है। अब जिस चीज की डिमांड होगी वह अपने आप बिकेगी। जिस चीज की डिमांड नहीं होगी उसको जबरदस्ती चिपकाना पड़ेगा। अगर इफको अपने एलोकेशन में यानी यूरिया के एलोकेशन के साथ अगर मैंडेटरी कंडीशन बताती है कि हिमफैड को इतना नैनो यूरिया उठाना पड़ेगा तो वे

कहां बेचेंगे? तो यह प्रॉब्लम जो है this will not get resolved by IFFCO's statement. This has to be resolved कि इफको हमें बोले कि जो माल आपने उठाना है उसे अपनी मर्जी से उठाइए। जितनी डिमांड है आप उतना उठाइए। जब डिमांड ही नहीं है और आप जबरदस्ती जब हिमफैड को देंगे तो वह सोसाइटीज को देगा और वे आगे फॉर्मर्स को देंगे। That is where the key question stands and this is guided by the Ministry of Chemical & Fertilizer. तो मैं इस माननीय सदन और अपने विपक्ष के माननीय सदस्यों के माध्यम से रिक्वैस्ट करूंगा कि आप सब एक बार माननीय नड्डा जी को बोलिए कि हिमाचल हित में अगर कुछ कर सकते हैं, किसानों के हित में कुछ कर सकते हैं तो इफको को डायरेक्शन दीजिए कि हिमाचल प्रदेश की सोसायटीज को जबरदस्ती माल न चिपकाया जाए। धन्यवाद।

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये जो इफको का पत्र मैंने इनको पढ़कर सुनाया है, यह Indian Farmers Fertilizers Cooperative Society है। यह कोऑपरेटिव सोसायटी पूरे देश में सारे फर्टिलाइजर्स देती है। इफको के साथ ही गवर्नमैंट की अंडरटेकिंग है

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

31.08.2026/1550/RKS/DC-1

कृषि मंत्री जारी....

जब इन्होंने पत्र जारी कर दिया है कि कोई भी सेल्समैन इसे खरीदने के लिए force नहीं करेगा तो स्वाभाविक रूप से IFFCO वाले उर्वरक नहीं भेजेंगे। इन्होंने इस विषय के संबंध में ऑलरेडी चिट्ठी लिख दी है। IFFCO भी कोऑपरेटिव संस्था है और इसका कार्य किसानों को उर्वरक उपलब्ध करवाना है। उन्होंने पत्र जारी कर दिया है कि किसी भी किसान पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। नैनो यूरिया लेना या न लेना पूरी तरह से किसान की इच्छा पर निर्भर करेगा। यह केवल एक विकल्प है और इसे किसी पर भी अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया जाएगा। जहां तक इसका संबंध है हम अपने विभाग की ओर से भी इस विषय पर आवश्यक पत्र जारी कर देंगे। 'इफको' की गाइडलाइन्स के अनुसार आवश्यक निर्देश सर्कुलेट कर दिए जाएंगे।

Speaker: HIMFED should be further directed that it should not buy this liquid forcibly. …(Interruption). माननीय सुधीर शर्मा जी आप क्या कहना चाहते हैं?

Shri Sudhir Sharma: Speaker, Sir, I very much agree with the Call Attention Motion put forward by Hon'ble Member Shri Bhawani Singh Pathania. Sir, as the reply has come from the Hon'ble Agriculture Minister; the concern is who are the authorities who are involved enforcing such idea. जो किसान यूरिया का बैग खरीदेंगे वे नैनो यूरिया की बोतल भी अनिवार्य रूप से खरीदें और यह प्रदेश में हो रहा है। माननीय मंत्री जी के जवाब से यह बात स्पष्ट है कि केंद्र सरकार की ओर से ऐसी कोई अधिसूचना या निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह भी कहा है कि प्रधान मंत्री जी इसकी advertisement करते हैं। मैंने किसी भी राष्ट्र के प्रधान मंत्री को किसी भी प्रोडक्ट की advertisement करते हुए नहीं देखा है और हमारे प्रधान मंत्री की बात तो दूर की है। जो विभाग के उत्पाद होते हैं उनकी advertisement नहीं की जाती उनकी लोगों में अवेयरनेस लाई जाती है। दूसरा, श्री भवानी सिंह पठानिया जी ने कहा कि "14 वर्ष के बाद किसानों को लगा कि नड्डा जी बने हैं तो प्रभू श्री राम आ गए"। अध्यक्ष महोदय, जिसने प्रभू श्री राम के आने पर दीया नहीं जलाया होगा उसे अंधेरे में लगा होगा कि राम नहीं रावण ही आए होंगे। लेकिन प्रदेश सरकार को इस मामले पर एक एस0आई0टी0 का गठन करना चाहिए ताकि यह जांच की जा सके कि इसमें कौन-

31.08.2026/1550/RKS/DC-2

कौन लोग संलिप्त हैं। यह बहुत बड़ा स्कैम है। मैं मांग करता हूं with all the expertise of the present Government, Special Investing Team (SIT) should be constituted on various issues. अध्यक्ष महोदय, आप एक डायरेक्शन दें कि ताकि इसके ऊपर एक एस0आई0टी0 का गठन किया जाए। वे कौन लोग हैं जो प्रदेश के भीतर इस प्रकार का माफिया चला रहे हैं?

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य श्री सुधीर शर्मा जी शायद रेडियो कम सुनते हैं क्योंकि ये ज्यादातर समय मोबाइल ही देखते रहते हैं। ...(व्यवधान) मैं 24 घंटे

रेडियो सुनता हूं और उसमें कई बार प्रधान मंत्री द्वारा नैनो यूरिया के उपयोग संबंधी संदेश प्रसारित किए जाते हैं। हिन्दुस्तान का प्रधान मंत्री नैनो यूरिया का विज्ञापन दे रहा है। टेलीविजन पर भी नैनो यूरिया के उपयोग को लेकर प्रधान मंत्री का विज्ञापन आ रहा है। जब हिन्दुस्तान का प्रधान मंत्री नैनो यूरिया का विज्ञापन करता है तो स्वाभाविक रूप से किसान ऐसे संदेशों को सुनकर यह मानते हैं कि यह उर्वरक उनके लिए सोना उगलेगा। अब 'इफको' ने स्वयं एक पत्र जारी करके स्पष्ट कर दिया है कि नैनो यूरिया लेना या न लेना किसान की अपनी मर्जी है। आप किसी भी व्यक्ति को कोई चीज़ ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते। क्योंकि 'इफको' किसानों की सहकारी संस्था है और यही संस्था आगे हमारे डिपुओं तक उर्वरकों की आपूर्ति करती है। हिमफैड को भी 'इफको' द्वारा उर्वरक सप्लाई किए जाते हैं। जैसा मैंने कहा कि 12:32:16, यूरिया और एन0पी0के0 सहित अनेक प्रकार के उर्वरक सप्लाई किए जाते हैं। इन उर्वरकों को बढ़ावा देने तथा किसानों को उपलब्ध करवाने का कार्य मुख्य रूप से हमारी सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है और उन्हीं के द्वारा किसानों को इनका विक्रय किया जाता है। जहां तक इसके संबंध में एस0आई0टी0 गठित करने या किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन करवाने की बात है तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन किस बात की करनी है?

श्री बी0एस0द्वारा जारी

31.08.2026/1555/बी.एस./ डी.सी.-1

कृषि मंत्री जारी...

इसके ऊपर कोई एस0आई0टी0 बैठे या कोई इन्वेस्टिगेशन पॉलिसी बैठे। वह तो किसानों की मर्जी है कि उसको लेना है या नहीं लेना है। किसान अगर चाहता है कि मैं लिक्विड फॉर्म में नहीं लूंगा और दूसरे फॉर्म में लूंगा तो वह दूसरे फॉर्म में ले ले और लिक्विड फॉर्म में न ले।

लेकिन मैं माननीय सदस्यों को यह अवगत करवाना चाहता हूं कि आप रेडियो सुनिए और जो हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री इसके एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं इसे मैं तो सुनता हूं और मैं तो हंसता भी हूं कि यह प्रधान मंत्री का काम नहीं है कि प्रधान मंत्री इनकी

प्रमोशन करे। हिमफेड को भी हम कहते हैं कि किस प्रकार की चिट्ठी लगे और डिपार्टमैंट को भी लेटर एड्रेस करके भेजा जाएगा, धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब श्री रणधीर शर्मा माननीय सदस्य अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा लोक निर्माण मंत्री महोदय चर्चा का उत्तर देंगे।...(व्यवधान)।

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह कार्य जबरदस्ती हो रहा है, यह तो स्कैंडल है। ...(व्यवधान)

Speaker: You resort to the different rules. माननीय सदस्य, नियम-62 में इसका इतना ही स्कोप है। ....(Interruption).Please order in the House. Hon'ble Member Shri Bikram Thakur ji, it is not permitted under this Rule. You resort to other Rules. ....(Interruption). We will consider it under other Rules. Please take your seats. माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी कृपया अपना विषय रखें। ....(Interruption). नियम -62 में इसका इतना ही स्कोप है। अब उत्तर से नए विषय पैदा हो रहे हैं तो आपके पास नियम बहुत हैं। आप किसी भी नियम का प्रयोग करते हुए कोई भी मोशन लाएंगे तो विधान सभा सचिवालय उसका संज्ञान लेगा लेकिन फिर से इसी इश्यू के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हो जाए that is not provided in this Rules. वैसे भी नियम-62 का मतलब यह नहीं है। There is difference between Rule -62 and Rule -130. Since this is very important issue and pertaining to the agriculturist of the Himachal Pradesh. That is why I have allowed this issue to be raised in the House and this has

31.08.2026/1555/बी.एस./ डी.सी.-2

been discussed under Rule -62 thoroughly. Whatever the directions were required to be issued that has been assured by the Hon'ble Minister. In any case if the Hon'ble Minister will not carry with those instructions; certainly the Vidhan Sabha Secretariat has a prerogative to take action against the Minister also. माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी कृपया अपनी बात रखें।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं अपने विषय पर आऊं,

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपने विषय पर ही आना है। इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया है।

श्री रणधीर शर्मा : सर, मैंने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर मांगा था। ...(व्यवधान) मेरी एक लाइन की बात है।

Speaker : So you are not raising your issue under Rule -62. ...(Interruption). You are raising Point of Order? ...(Interruption).

श्री रणधीर शर्मा : अगर भारत सरकार की कोई नोटिफिकेशन है तो ठीक है, नहीं तो जो इन्होंने केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के बारे में एस0एच0ओ0 का चुटकुला सुनाते हुए कहा है वह सारी बातें एक्सपंज होनी चाहिए।

(**दोनो पक्ष के माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर बहस करने लगे**)

Speaker : We will examine the record and anything ...(Interruption). I will examine the record. ...(Interruption). Please be seated. ...(Interruption). Please be calm and no cross talks. I am not permitting it. ...(Interruption). Please take your seats. आपने जो विषय उठाया है, मैं रिकॉर्ड को peruse करूंगा। I will peruse the record और जो भी अनडिजायरेबल होगा उसको रिकॉर्ड से निकाल दिया जाएगा। जो रेफरेंसिज अनडिजायरेबल होंगे उनको रिकार्ड से निकाल दिया जाएगा।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

31.08.2026/1600/DT/HK-1

अध्यक्ष जारी....

This I will assure. I will perused the record and in any case, if anything which is undesirable as per the... ...(व्यवधान) मैंने बोल दिया। मैंने बोल दिया। ...(व्यवधान)

एक मिनट बैठिए न आप। ...(Interruption) Please take your seats. Please take your seats, ...(Interruption) नेता प्रतिपक्ष कृप्या बैठिए। ...(व्यवधान) Please, please, please, please. ...(व्यवधान) इस तरह का वातावरण ठीक नहीं है। Please take your seats. ...(Interruption) बैठिए।

श्री रणधीर शर्मा जी ने विषय उठाया है, ...(व्यवधान) मैं बोल रहा हूं न मुझे बोलने तो दो ...(व्यवधान). नहीं-नहीं पहले ...(व्यवधान) Please take your seats. आप जो चाहा रहे हैं वह मुझे करने दो। ...(व्यवधान) कोई रिकॉर्ड पर नहीं आया । जो रिकॉर्ड पर आया होगा मैं उसे हटा दूंगा। Please, take your seats. **Whatever is undesirable which is against the purview of Rule 62, will be removed from the record, this I assure**. Okay, thank you. ...(Interruption) I have said it. Please, please take your seats. ...(Interruption) I have assured the House continuously. ...(Interruption) Please take your seats.

अब माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय लोक निर्माण मंत्री महोदय उसकी चर्चा का उत्तर देंगे। माननीय श्री रणधीर शर्मा जी।

इस विषय से रिलेटेड कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी तो you can seek it with the permission of the Chair.

31.08.2026/1600/DT/HK-2

Shri Randhir Sharma :Thank you, Sir. अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से श्री नैना देवी जी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली संपर्क सड़कों की स्थिति व सुधार बारे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री नैना देवी जी विधान सभा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से बड़ा फैला हुआ क्षेत्र है, गांव दूर-दूर हैं और गांवों में भी घर भी दूर-दूर हैं और सड़कों का घनत्व उस विधान सभा क्षेत्र में कम है। परंतु इस सरकार की अनदेखी के

कारण तथा इस सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये के कारण हमारे विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की समस्या इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी बहुत ही दिक्कत महसूस कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय, एक तो हालांकि इस बार बारिशें भी कम हुई हैं फिर भी हमारी लगभग हर सड़क टूटी हुई है और हर सड़क की हालत दयनीय हुई है। इसका कारण यह है कि लोक निर्माण विभाग ने समय रहते न तो नालियां निकालीं और न ही पिछले साल आपदा के दौरान जो लैंडस्लाइड हुए थे उन पर डंगे लगाए गए और न प्रोटेक्शंस वॉल और न ही रिटेनिंग वॉल लगाई गई। जिसके कारण पिछले साल जो स्लाइड आए थे और जिन्हें ठीक किया गया था वे इस बार पहली ही बारिश में वे स्लाइड फिर चले गये। सड़क के किनारे नालियां न होने के कारण सारा पानी लोगों की जमीनों में तथा नीचे घरों में आना शुरू हो गया। जिसके कारण लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आई है।

अध्यक्ष महोदय, जब हम अधिकारियों से बात करते हैं तो वहां पर अधिकारी यही कहते हैं कि नालियां जे0सी0बी0 से निकलेंगी। हमारी जे0सी0बी0 दो महीने से खड़ी है और उसके टायर रिपेयर करवाने तथा टायर बदलने के लिए पैसे नहीं हैं। अधिकारियो को बोलो सड़क टूटी है तो पैच वर्क करवाने के लिए कहा जाता है। पैच वर्क के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। इसलिए सरकार की तरफ से नई सड़क तो दूर की बात है सड़कों की रिपेयर मेंटेनेंस यहां तक कि गड्ढे भरने और पैच लगाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। यही इस सरकार की हालत है। परंतु मेरा कंसर्न इससे भी ज्यादा इस बात से है कि वर्ष 2023 से वर्ष 2025 के दौरान आपदा हुई और पूरे प्रदेश में सड़कों तथा घरों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। लोग भी प्रभावित हुए। उस नुकसान की चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूं। परंतु मैं यहां यह जरूर कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के द्वारा पिछले साल जहां

31.08.2026/1600/DT/HK-3

सड़क टूटी है वहां पैच वर्क करवाने के लिए कहा जाता है, लेकिन पैच वर्क के लिए राज्य सरकार के पास पैसे नहीं हैं। इसलिए सरकार की तरफ से नई सड़क तो दूर की बात है

सड़कों की रिपेयर, मेंटेनेंस यहां तक कि गड्ढे भरने और पैच लगाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। यही इस सरकार की हालत है।

परंतु अध्यक्ष महोदय मेरा कंसर्न इससे भी ज्यादा इस बात से है कि वर्ष 2023 और वर्ष 2025 के दौरान प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई और पूरे प्रदेश में सड़कों तथा घरों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। मकानों को भी नुकसान हुआ जिससे लोग भी प्रभावित हुए। उस नुकसान की चर्चा मैं करना नहीं चाहता हूं। परंतु मैं यहां यह जरूर कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने पिछले साल

श्री एन0जी0द्वारा जारी..

31.08.2026/1605/एच.के.-एन.जी./1

श्री रणधीर शर्मा......... जारी

दिनांक 18 जून, 2025 को पी0डी0एन0ए0 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को 2,006 करोड़ रुपये का पैकेज दिया था और दिनांक 28 दिसंबर, 2025 को उसकी पहली किस्त 600 करोड़ रुपये के रूप में हिमाचल प्रदेश को मिली थी। उस पैसे को इन्होंने कैसे डिवाइड किया, मैं उसकी भी चर्चा नहीं करना चाहता। हालांकि, 600 करोड़ रुपये को 12 जिलों में बांटें तो 50 करोड़ रुपये से ऊपर लगभग हर जिला को आना चाहिए था। परंतु हमारे डिवीजन व हमारे विधान सभा क्षेत्र में मात्र 11 करोड़ 11 लाख 13 हजार रुपये आए। यह धनराशि हमारे बिलासपुर डिवीजन नंबर-2 में दिसंबर 2025 में पहुंच गई थी।

अध्यक्ष महोदय, चिंता की बात यह है कि अभी तक वह पैसा खर्च नहीं हुआ है। दिसंबर में पैसा आया और वर्ष 2026 के जनवरी से जून तक छह महीने निकल गए हैं। बरसात से पहले के छह महीने में भी हमारे डिवीजन के अधिकारी हमारे विधान सभा क्षेत्र में आए हुए 11 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाए। आज हालात ये हैं कि 11 करोड़ रुपये में से मात्र 1 करोड़ 47 लाख रुपये खर्च हुए हैं और इससे केवल चार कार्य हुए हैं। इसके अलावा

तीन कार्यों के लिए 30 लाख 82 हजार रुपये के टेंडर अवॉर्ड हुए हैं, लेकिन उन पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, आप हैरान होंगे कि मेरे पास शेष कार्यों की भी सूची है। शेष 9 करोड़ 32 लाख रुपयों के 99 कार्यों के न तो टेण्डर अवॉर्ड हुए हैं और न ही उन पर काम शुरू हुआ है। ये सभी छोटे-छोटे कार्य थे—कहीं लैंडस्लाइड के बाद डंगा लगना था, कहीं ड्रेन बननी थी, कहीं प्रोटेक्शन वर्क होना था और कहीं रिटेनिंग वॉल लगनी थी। जब ये काम नहीं हुए तो इस वर्ष कम बारिश के बावजूद भी हमारी सड़कों को काफी नुकसान हुआ है।

31.08.2026/1605/एच.के.-एन.जी./2

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय लोक निर्माण मंत्री, जोकि यहां सदन में बैठे हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है? पी0डी0एन0ए0 का पैसा दिसंबर 2025 में आ गया था, फिर बरसात से पहले वह पैसा खर्च क्यों नहीं किया गया? क्या उन अधिकारियों के खिलाफ विभाग कोई कार्रवाई करेगा, जिन्होंने इस मामले में लापरवाही बरती? उन अधिकारियों की लापरवाही के कारण ही आज इसका परिणाम हमारे क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अगर हम किसी से बात भी करें तो लोग कहते हैं कि बारिश तो कम हुई है। परंतु जब कोई प्रोटेक्शन वर्क नहीं हुआ था, जब आपदा को रोकने के लिए विभाग के पास अपना पर्याप्त फंड नहीं था और केंद्र से आया हुआ पैसा भी खर्च नहीं किया गया, तब जाकर हालात इतने गंभीर हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बात माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार की लापरवाही के लिए विभाग क्या कार्रवाई करेगा? अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी माननीय लोक निर्माण मंत्री इस सदन में प्रस्तुत करें।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-3 में भी पांच सड़कें बन रही हैं। इसके अलावा एक नागौण-बैरी सड़क सी0आर0आई0एफ0 के अंतर्गत 80 करोड़ रुपये की लागत से अपग्रेड हो रही है। इस सड़क का काम चल रहा है और 80 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से आए हैं। लेकिन सड़क का इतना बुरा हाल है कि आज वहां चलना बहुत मुश्किल हो गया है। सड़क में जगह-जगह गड्ढे पड़ गए हैं और जगह-जगह कीचड़ आ जाता है। पैदल चलना भी मुश्किल है, गाड़ियों का चलना तो और भी कठिन है। इसके दो कारण हैं। एक तो अधिकारियों की ठेकेदार पर कोई लगाम नहीं है। उन्होंने 14 किलोमीटर सड़क की एक ही बार में पूरी कटिंग कर दी। सड़क की जो टारिंग पहले से थी, उसे भी उखाड़ दिया और पूरी सड़क को वैसे ही छोड़ दिया। उसके ऊपर बरसात आ गई।

31.08.2026/1605/एच.के.-एन.जी./3

अभी हालत यह है कि सड़क पर इतने गड्ढे हैं कि पता ही नहीं लगता कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। जबकि आवश्यकता यह थी कि एक-दो किलोमीटर सड़क की कटिंग की जाती, उस हिस्से को ठीक किया जाता और उसके बाद आगे बढ़ा जाता। परंतु उस ओर विभाग ने ध्यान नहीं दिया। मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि अभी तो कटिंग हो चुकी है, लेकिन आगे इस तरह के काम जब भी हों, तो उनमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। दूसरा, उस सड़क पर जो गड्ढे पड़े हैं, उन्हें कम-से-कम ठेकेदार से भरवाया तो जाए और सड़क की रिपेयर करवाई जाए, ताकि यदि बरसात में काम बंद भी रहता है तो लोगों को आने-जाने में दिक्कत न हो। ये निर्देश तो माननीय मंत्री जी

पी0बी0 द्वारा......जारी

31.08.2026/1610/YK/PB/1

श्री रणधीर शर्मा ...जारी.

आज ही इस संबंध में आवश्यक निर्देश दें।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा विषय यह है कि मैंने आपको पीडीएनए में सड़क मरम्मत के जो 99 कार्य बताए हैं, उनमें मुझे यह गड़बड़ी लग रही है कि 82 कार्य तो अन्य सड़कों के हैं और 17 कार्य नवगांव-बैरी सड़क के हैं। जब इस सड़क के लिए 80 करोड़ रुपये सेंट्रल रोड फंड से प्राप्त हुए हैं, ठेकेदार को टेंडर अवार्ड हो चुका है और काम चल रहा है तो वहां विभाग मरम्मत क्यों करवाएगा? वहां भूस्खलन सड़क की कटिंग के कारण हुआ है। कटिंग ठेकेदार ने की है और सड़क को ठेकेदार ने उखाड़ा है। ऐसी स्थिति में उस सड़क की मरम्मत के लिए विभाग द्वारा 17 कार्यों पर 1.74 करोड़ रुपये क्यों खर्च किए जा रहे हैं? क्या यह ठेकेदार को बेनिफिट दिया जा रहा है? क्या यह कार्य आपकी स्वीकृति के बाद किया जा रहा है? अन्यथा जिस सड़क पर 80 करोड़ रुपये का टेंडर हुआ हो और काम चल रहा हो, उस सड़क की मरम्मत के लिए पी0डी0एन0ए0 का पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। इसलिए मंत्री महोदय इस विषय पर अवश्य स्थिति स्पष्ट करें और जिन अधिकारियों ने ऐसा किया है उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का आश्वासन भी दें।

अध्यक्ष महोदय, इसी सड़क पर बीच में 4 किलोमीटर का खारसी से रानीकोटला तक एक पोर्शन आता है। वहां बागा में पहले जे0पी0 की सीमेंट फैक्टरी थी और अब अल्ट्राटेक की सीमेंट फैक्टरी है। उस सड़क का निर्माण उनके द्वारा किया जाता है परंतु उन्होंने वह सड़क ठीक प्रकार से नहीं बनाई है। हमने पिछले सत्र में भी निवेदन किया था कि 80 करोड़ रुपये के बजट में सेविंग का प्रावधान है उसमें लगभग 20 करोड़ रुपये की सेविंग है। इसलिए बीच में छोड़े गए 4 किलोमीटर के पोर्शन को भी कवर किया जाए और उसे भी सी0आर0एफ0 के अंतर्गत अपग्रेड किया जाए। आज मैं यह मांग इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से करना चाहता हूं।

रानीकोटला से आगे जब्बलपुल तक अल्ट्राटेक कंपनी ने सीमेंट की सड़क बनाई है। सीमेंट की सड़क के कारण गाड़ी के टायर अधिक घिसते हैं और धूल भी अधिक होती है जिससे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अल्ट्राटेक सीमेंट

31.08.2026/1610/YK/PB/2

कंपनी का जो माइनिंग का पैसा, डी0एम0एफ0टी0 का पैसा है वह सारा-का-सारा सोलन चला जाता है। (***)। डी0एम0एफ0टी0 माइनिंग एक्ट के अनुसार जहां फैक्टरी है वहां से 25 किलोमीटर के रेडियस में यह पैसा खर्च होना है। हमारे विधान सभा क्षेत्र में फैक्टरी से शुरू होकर ट्रक गुजरते हैं। चाहे ट्रक उनके विधान सभा क्षेत्र के हों या हमारे विधान सभा क्षेत्र के हों, धूल तो हम लोगों को ही खानी पड़ती है। इसलिए डी0एम0एफ0टी0 का पैसा हमारे क्षेत्र में भी खर्च किया जाए और कम-से-कम इस सड़क पर ही वह पैसा खर्च कर दिया जाए ताकि जो सड़क खराब हुई है उसका काम हो सके। इस सड़क को जे0पी0 सीमेंट कंपनी ने ठीक प्रकार से नहीं बनाया है और अब अल्ट्राटेक उसकी मेंटेनेंस नहीं कर रहा है। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस सड़क का काम करवाया जाए।

अध्यक्ष : माननीस सदस्य आप नियम-62 के तहत अपनी बात संक्षिप्त में और स्पैसिफिक इशू पर ही रख सकते हैं। आप इसके तहत चर्चा नहीं कर सकते। आपके 12 मिनट हो गए हैं और आपका स्पैसिफिक इशू आ गया है।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अभी तो बहुत कुछ कहना है। मुझे चार-पांच मिनट का समय दीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे साथ क्या-क्या हो रहा है।

अध्यक्ष : उसके लिए अन्य नियम है। आप नियम-62 के तहत चर्चा नहीं कर सकते।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय आप हमारे संरक्षक है लेकिन आप हमें बोलने से रोक रहे हैं।

अध्यक्ष : मैं आपको बोलने से नहीं रोक रहा हूं बल्कि नियम-62 से अवगत करवा रहा हूं। मेरे पास आपको रोकने का कोई कारण नहीं है। आप वरिष्ठ सदास्य हैं आपको नियम-62 के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप अपने विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों पर भी चर्चा कर रहे हैं।

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

31.08.2026/1610/YK/PB/3

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विषय पर ही बोल रहा हूं। हमने विधायक प्राथमिकता के अंतर्गत सड़कों की डी0पी0आर0 दी हैं। उन सड़कों में से चार सड़कें हमारी नाबार्ड में

पहुंच चुकी हैं। इस सरकार के समय उनमें से एक भी सड़क को नाबार्ड से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है। हमारी स्वान-क्रीड़ा-पंघवाना सड़क की डी0पी0आर0 वर्ष 2019 में दी गई थी। उसके बाद वह डी0पी0आर0 मिसप्लेस हो गई और उसके बाद फिर से डी0पी0आर0 भेजी गई है। इस सड़क के लिए 12 करोड़ 18 लाख रुपये की धनराशि लंबित है और अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है। इसी प्रकार घसोड़-लोअर भौली विद ब्रिज सड़क 11 करोड़ रुपये की है और वर्ष 2023 से नाबार्ड में स्वीकृति हेतु लंबित है।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

31.08.2026/1615/एच0के0/ए0पी0-01

श्री रणधीर शर्मा जारी .....

मेरी एक रोड वर्ष- 2023 से नाबार्ड में है। नाबार्ड से साई कनैता-साई ब्राह्मणा वाली सड़क वर्ष-2024 से नाबार्ड में है। एक डेहनी-खड्ड ब्रिज है, यह वर्ष-2025 से नाबार्ड में है। हमारे पास अभी 22-23 करोड़ रुपये की किट्टी भी बची हैं। उसके बावजूद हमारी सड़कें स्वीकृत

नहीं हो रही हैं। क्योंकि जब नाबार्ड की प्राथमिकता होती है और मुख्यमंत्री जी री-प्रायोरिटाइज़ेशन का कोई लेटर लिखते हैं, उसमें उनके जो खास लोग हैं, उन्हीं के विधान सभा क्षेत्रों की सड़कें होती हैं। उसी तरह से चयन होता है। जो सड़कें हमने विधायक प्राथमिकता में दी हैं ...(व्यवधान) जो हमने विधायक प्राथमिकता में सड़कें दी है। मैं यह मानता हूं कि जहां जमीन उपलब्ध न हो, वहां विभाग कुछ नहीं कर पाता। लेकिन जिन सड़कों के लिए हमने लोगों से गिफ्ट-डीड दिलवा दी है और साल-साल हो गया है, उनकी भी डी0पी0आर0 नहीं बन रही है, हम कहां जाएं? ...(व्यवधान)

Speaker : Again you are making an aspersion to the Chair, not once but for many times you have made it and I am cautioning you, this is not proper. ...(Interruption) This is not proper. Despite my best efforts. ...(Interruption) I am allowing you, all issues to be raised and you are causing this aspersion. This will not be part of the record. ...(Interruption) एक मिनट, Let him complete. ...(Interruption)

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आप बोलने नहीं देते, ये सुनते नहीं हैं, हम कहां जाएं? यह एक बट्टू सड़क है, एक चांदपुर-बाग-चिममयाणा सड़क है, चांदपुर-सोलदा सड़क, सरनी-थाना वाली सड़क है, ये सभी सड़कें प्राथमिकता में हैं। इन सड़कों की डी0पी0आर0 बनाई जाए। यह मेरा मंत्री जी से आग्रह है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-3 में हमारे विधान सभा क्षेत्र की 25 सड़कें आई हैं। इनमें 15 सड़कें एक ब्लॉक की और 10 दूसरे ब्लॉक की हैं। इन 25 सड़कों के लिए क्राइटेरिया ढाई-सौ आबादी से ऊपर का है। इन 25 सड़कों में से कम-से-कम 12 सड़कों की गिफ्ट-डीड हो चुकी है। उसके बावजूद भी डी0पी0आर0 नहीं बन रही है। यह हैरानी वाली बात है। चाहे किसी भी सड़क की बात करें, सलोहा गांव की संपर्क सड़क की बात करें, नेरी-बाड़नू की सड़क अब स्वीकृत हो गई है।

31.08.2026/1615/एच0के0/ए0पी0-02

इसके अलावा ट्यून की सड़क, जनेड़ की सड़क, बाकलां की सड़क, साई लोढ़वां-सोरी की सड़क, साई ब्राह्मणा या साई कनैता की सड़क, बलवाड़ गांव की सड़क, गोरी गांव की

सड़क और पगवाना की सड़क है। इनमें अधिकतर की गिफ्ट-डीड हो चुकी है। सलोहा गांव की सड़क है, गलूआ-सुवाणा की सड़क है, बटेटू-कनफारा, आगे पंचपाड़ा-टू-वाया दक्षिणी - इनकी गिफ्ट-डीड हुए एक साल से अधिक समय हो गया है। काथला की सड़क, खेरिया की सड़क, अपर ट्यून की सड़क और कटीरड़ की सड़क है। इसी तरह सरनी की सड़क, हमारे नाल गांव की सड़क, भड़ारण की सड़क, भारसरा की सड़क और पंगा गांव की सड़क है और उससे बड़ी बात, एक खाल टिब्ब के पास सड़क है। वर्ष - 2007 में विधायक प्राथमिकता में दिया था और इसकी एक बार डी0पी0आर0 भी बन गई थी, लेकिन एफ0सी0ए0 नहीं हुआ। यह 11 किलोमीटर लंबी सड़क है। मैं इस सड़क एफ0सी0ए0 करवाने के लिए दिल्ली दो बार गया और केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी से बात भी की है। इसकी एफ0सी0ए0 की क्लियरेंस भी मैंने करवा दी। उसको भी एक साल हो गया है। अध्यक्ष महोदय, उसकी डी0पी0आर0 भी नाबार्ड को नहीं भेज रहे हैं। हमने विभाग से यह भी कहा कि अगर आप इसे नाबार्ड को नहीं भेजना चाहते तो इसे पी0एम0जी0एस0वाई00 फेज-3 के लिए भेजें। उसमें भी यह क्राइटेरिया में आती है। लेकिन पता नहीं डी0पी0आर0 कहां भेजते हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से कहना है कि वर्तमान सरकार का हमारे विधान सभा क्षेत्र के प्रति जो भेदभावपूर्ण रवैया है, उसे दूर किया जाए। जो सड़कें विधायक प्राथमिकता में हैं और जिनकी गिफ्ट-डीड हो गई है, उनकी तुरंत डी0पी0आर0 बनाई जाए। जो सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-3 में आई हैं और जिनकी जमीन की गिफ्ट-डीड हो गई है, उनकी एफ0सी0ए0 की एन0ओ0सी0 के लिए उन्हें आगे बढ़ाया जाए और जो पी0डी0एन0ए0 का 9 करोड़ 32 लाख रुपये का पैसा खर्च नहीं हुआ है, उसे खर्च तो करें ही। लेकिन जिन अधिकारियों की लापरवाही से वह पैसा अभी तक खर्च नहीं हुआ और जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा उन पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया जाए। यही निवेदन आपके माध्यम से करता हुआ मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

31.08.2026/1615/एच0के0/ए0पी0-03

अध्यक्ष : आपका जो रेफरेंस आया है माननीय सदस्य श्री संजय अवस्थी जी को बोलते हुए। That will not be part of the record. (Interruption) माननीय लोक निर्माण मंत्री जी।

लोक निर्माण मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज नियमः-2 के अंतर्गत माननीय विधायक श्री रणधीर शर्मा जी ने सदन के भीतर श्री नैना देवी जी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली संपर्क

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

31.08.2026/1620/AT/AG/01

लोक निर्माण मंत्री जारी....

सड़कों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए जो मसले आज यहां उठाए गए हैं, माननीय विधायक जी, मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं और सिर्फ विश्वास ही नहीं दिलाना चाहता, बल्कि हर उस विषय और हर उस कार्य को, जो आपने आज यहां सदन के भीतर रखा है, हमने पूरी गंभीरता से सुना है और उन पर कार्रवाई भी होगी। जो कार्य पहले से चले हुए हैं, उनको निरंतर रूप से और मजबूती के साथ आगे ले जाने का हम प्रयास करेंगे।

श्री नैना देवी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 132 सड़कें हैं, जिनमें 3 मुख्य जिला मार्ग (MDR) तथा 129 ग्राम सड़कें शामिल हैं। इन सड़कों की कुल लंबाई लगभग 519 किलोमीटर है, जिसमें से 449 किलोमीटर सड़कें पक्की हैं और लगभग 70 किलोमीटर सड़कें कच्ची हैं। गत तीन वर्षों में, जिसके बारे में आपने आज यहां पर काफी लंबा विवरण दिया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक जी को कहना चाहूंगा कि गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र नैना देवी में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सड़क निर्माण, सुधार एवं उन्नयन यानी अपग्रेडेशन के कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 18.83 किलोमीटर ROFD (Removal of Formation Deficiency) तथा 52.10

किलोमीटर सड़कों को पक्का करवाया गया है। नाबार्ड के अंतर्गत 4.24 किलोमीटर Formation Cutting, 9.74 किलोमीटर Cross Drainage Works, 3.81 किलोमीटर ROFD (Removal of Formation Deficiency) तथा 18.135 किलोमीटर सड़क को पक्का करवाया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगा कि ग्रामीण सड़कों में 9.840 किलोमीटर Formation Cutting, 12.165 किलोमीटर Cross Drainage Works एवं 9.310 किलोमीटर सड़कों को पक्का किया गया है। CRF का इन्होंने अभी यहां पर जिक्र किया और CRF में निश्चित तौर पर नवगांव-बैरी सड़क सड़क का माननीय सदस्य

31.08.2026/1620/AT/AG/02

जिक्र कर रहे थे। उसमें 12.9 किलोमीटर Removal of Formation Deficiency तथा 5 किलोमीटर Cross Drainage का कार्य पूर्ण हो चुका है।

इन्होंने यहां पर एक महत्वपूर्ण बात कही है कि PDNA के तहत कुछ कार्य इस स्ट्रेच में करवाए गए हैं, जो CRF के अंतर्गत allocated हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें जब आप पूरे रोड की लंबाई लेते हैं और जो इसमें sanctioned amount होता है and the work that has been put to tender, it is not necessary that it is done for the entire stretch of that land, जो sanctions आती हैं, वे लगातार अलग-अलग हिस्सों के लिए आती हैं, जैसे 10 से 20 किलोमीटर, 20 से 30 किलोमीटर या 30 से 40 किलोमीटर तक। अभी मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। **I will seek information about that from the department, but there can be a situation where this work of PDNA has been done on the area which has not been sanctioned under CRF.** मगर फिर भी आपकी जो आशंकाएं हैं, उनको हम स्वीकार करते हैं और I will consult the department about this. अगर ऐसा हुआ है कि एक ही जगह पर double work हुआ है, तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई करवाई जाएगी। इसका भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत किए गए विभिन्न कार्यों पर कुल 100 करोड़ रुपये की धनराशि नैना देवी विधान सभा क्षेत्र के अंदर तीन साल के दौरान

खर्च करवाई गई है। इसके अतिरिक्त, श्री नैना देवी विधान सभा क्षेत्र में AMP यानी Annual Maintenance Plan के तहत भी 62 किलोमीटर सड़कों की टायरिंग का कार्य किया गया है। इसके साथ-साथ सड़कों के patch work, drainage की सफाई, मरम्मत, क्षतिग्रस्त भागों की बहाली एवं अन्य आवश्यक कार्य बजट की उपलब्धता के अनुसार करवाए जा रहे हैं। इस विधान सभा क्षेत्र का अधिकांश भू-भाग पहाड़ी क्षेत्र है, जिसमें भारी वर्षा, भूस्खलन और flash flood जैसी अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण समय-समय पर सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इस विधान सभा क्षेत्र में गत तीन वर्षों में, दिनांक 23-08-2026 तक, लगभग 53 करोड़ रुपये की क्षति का आंकलन किया गया है। क्षतिग्रस्त सड़कों की बहाली हेतु विभिन्न आपदा राहत एवं पुनर्स्थापना व्यवस्थाओं के अंतर्गत SDRF में 2.15 करोड़ रुपये ,NDRF 2.20 करोड़ रुपये

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी.....

31.08.2026/1625/av/ag/1

लोक निर्माण मंत्री -------जारी

तथा पी0डी0एन0ए0 के अंतर्गत 09.91 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

अध्यक्ष महोदय, यहां जैसे माननीय विधायक ने कहा कि यह पैसा अनस्पैंट हैं तो मैंने इसके बारे में विभाग से जानकारी प्राप्त की है और ऐसा नहीं है। इसमें चाहे कोई डंगे लगे हैं या क्रॉस ड्रेनेज या फिर अन्य कार्य हुए हैं; हो सकता है कि उसका यू0सी0 अभी तक नहीं दिया गया हो जिसकी वजह से वह काम कम्पलीट नहीं दिखा रहा है। मगर as far as the department is concerned, all these works have been put to tender. They have been awarded and the concerned contractors in various areas are executing the work. लेकिन फिर भी इसमें यदि किसी भी प्रकार की डैफिशिएंसी होगी तो उसके बारे में मैं विभाग से पूर्ण जानकारी प्राप्त करूंगा और अगर कहीं कोई कमी पाई जाएगी तो उसको **निश्चित रूप से पूरा करने का हरसम्भव प्रयास किया जाएगा।** नैना देवीजी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बटेड़-कनफाड़ा सड़क तथा नेरी-बड़ून सड़क हेतु अभी जो हिमाचल प्रदेश को पी0एम0जी0एस0वाई0-iv की

सैंक्शन आई है। जिसमें मैंने पहले भी कहा था कि 2300 किलोमीटर्ज सड़कें और लगभग 1500 करोड़ रुपये हिमाचल प्रदेश को मिले हैं; उसमें हमने रिकॉर्ड समय में, in spite of the Model Code of Conduct that was in place previously because of the Panchayati Raj Elections, मगर फिर भी हमने एक समन्वय बनाकर ये सारे काम अवार्ड कर दिए हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर थोड़े से कार्य रह गए हैं because of litigation in the Hon'ble High Court and the Hon'ble Supreme Court जिसकी वजह से वे कार्य अभी अवार्ड नहीं हो पाए हैं। मगर नैना देवीजी विधान सभा क्षेत्र में केवल दो ही कार्य अवार्ड हुए हैं और ये दोनों ही कार्य 6-6 करोड़ रुपये के हैं। ये कार्य दिनांक 21.04.2026 को आबंटित हो चुके हैं और इनका कार्य प्रगति पर हैं।

इसके अतिरिक्त नैना देवीजी सड़क से खाल टिब्बा सड़क को पी0एम0जी0एस0वाई0-iv बैच के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है। इस बारे में माननीय विधायक ने अपनी बात रखी है। मैं बताना चाहूंगा कि हमारी डी0पी0आर0 बनकर तैयार हैं और उनको हम आने वाले

31.08.2026/1625/av/ag/2

समय में सैंक्शन करवाना चाहते हैं। उसमें गिफ्ट डीड्ज हो चुकी हैं। इन्होंने इसमें एफ0सी0ए0 का भी जिक्र किया है! इसलिए मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने अभी एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजैक्ट पी0एम0जी0एस0वाई0-iv बैच टू जो हमारा आ रहा है; उसके अंतर्गत न केवल नैना देवीजी विधान सभा क्षेत्र अपितु पूरे प्रदेश में हम प्रयास कर रहे हैं कि हमें इसमें मैक्सिमम सड़कें स्वीकृत हों। उसके लिए जहां पर भी एफ0सी0ए0 के कार्य होने हैं; उसके लिए हम कंसर्न्ड पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ-साथ संबंधित स्थानीय विधायकों से भी वार्तालाप कर रहे हैं। हालांकि आप जानते हैं कि इसमें एक गांव में 250 हैबिटेशन की एक लिमिटेशन है, तभी इसकी सैंक्शन होती है। इसमें दूसरी समस्या यह है कि यदि किसी हैबिटेशन की एक साइड से कनेक्टिविटी दिखा रहा है क्योंकि इसमें जियो टैगिंग के माध्यम से सड़कों की एलोकेशन होती है। कभी-कभी हम किसी सड़क की अपनी ओर से डी0पी0आर0 बनाकर भेज भी देते हैं परंतु जब उसको जियो टैगिंग से देखा

जाता है तो दूसरी तरफ से कनेक्टिड होने के कारण वह सड़क ड्रोप हो जाती है। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी मैक्सिमम सड़कें पी0एम0जी0एस0वाई0-iv के सैकिण्ड बैच में आएं। हम यह प्रयास भी करेंगे कि नैना देवीजी विधान सभा क्षेत्र के जो खासकर पहाड़ी क्षेत्र हैं, क्योंकि अगर आप इसमें एलोकेशन्ज देखेंगे जो हमें मिली हैं; तो जो ओल्ड हिमाचल या जिसको हम ऊपरला हिमाचल कहते हैं जैसे चम्बा, मण्डी या कुल्लू इत्यादि क्षेत्रों के लिए ज्यादा सैंक्शन्ज आई हैं। हमारे हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना इत्यादि में पहले से ही मैक्सिमम हैबिटेशन्ज कनेक्ट हो चुकी हैं इसलिए इन एरियाज के लिए कम सैंक्शन्ज आई हैं। मगर फिर भी हमारा यह प्रयास रहेगा कि इसमें जो भी इलाके छूट गए हैं; **उनके लिए ज्यादा-से-ज्यादा डी0पी0आर्ज0 बनाई जाए और उसको हम करेंगे।**

इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने नाबार्ड की स्वीकृतियों के बारे में भी सदन में बात रखी है। यहां पर जैसे इन्होंने कहा कि यह विषय प्लानिंग

टी सी द्वारा जारी

z

31.08.2026/1630/टी0सी0वी0/ए0एस0-1
लोक निर्माण मंत्री ... जारी

डिपार्टमैंट के माध्यम से करवाया जाता है, निश्चित तौर पर हम इस विषय को उठाएंगे। सदन के नेता, मुख्य मंत्री जी भी यहीं हैं इसलिए आप उनसे भी इस विषय में बात करें कि जब भी प्लानिंग की मीटिंग होती है and otherwise also इसको एक्सपीडाइट करवाया जाए। हम तो डी0पी0आर0 विभाग की ओर से बनवाकर भेज देते हैं लेकिन प्लानिंग डिपार्टमैंट से आगे जब यह नाबार्ड में जानी होती है तो that is the role of the Planning Department so they have to take a call that how these roads have to be prioritized. So the role of public works is very limited in that sphere. इसलिए इस विषय पर मुख्य मंत्री जी से चर्चा कर लेंगे और जो भी इनकी सड़कें बची हुई हैं उनको आने वाले समय में निश्चित तौर से आगे ले जाया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं एक बार फिर से माननीय विधायक महोदय को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसा इन्होंने कहा है कि हमारे इलाके के साथ बंदर बांट हुई है ऐसा नहीं है। हम equitable distribution of resources, equitable distribution of wealth and holistic development of Himachal Pradesh में विश्वास रखते हैं। मैंने आंकड़ों सहित हर विधान सभा क्षेत्र व आपके विधान सभा क्षेत्र के अंदर अलग-अलग हैड में, अलग-अलग स्कीम में कितना पैसा वितरित किया जा रहा है इसकी जानकारी माननीय सदन को दी है। मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि जो हमारे ट्राइबल एरियाज और डिफिकल्ट एरियाज हैं वहां निश्चित तौर पर एलोकेशन ऑफ फंड्स ज्यादा हो सकता है but that is because of the hilly terrain, because of the difficult an inaccessible terrain के कारण है। इसलिए उन एरिया में एलोकेशन ऑफ फंड्स स्वाभाविक रूप से ज्यादा होगा। मगर अगर हम होलिस्टिक व्यू से देखें तो हम पूरे प्रदेश को एक समान देखते हैं।

मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितने भी प्रोजैक्ट्स यहां नाबार्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0 और सी0आर0एफ0 के माध्यम से चल रहे हैं उनको गति दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। **इन्होंने जो आशंकाएं यहां जताई हैं उनके बारे में मैं अपने विभाग से चर्चा करूंगा और उनको जल्द-से-जल्द सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया जाएगा।** धन्यवाद।

31.08.2026/1630/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी, वैसे तो माननीय मंत्री जी ने कम्प्लीट एश्योरेंस दे दी है।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जानकारी दी है उसमें जो सड़कों के काम चले हैं, वे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और सी0आर0एफ0 के ही हैं। लेकिन मैं उसके बारे में बोल नहीं पाया। एक विषय यह भी है कि आपने जो कहा कि रिपेयर का काम और मेंटेनेंस का काम स्टेट हैड्स से हुआ है तो जिन ठेकेदारों ने यह काम किया है उनको पेमैंट नहीं हो रही है और उसके कारण वे दोबारा टेंडर नहीं भरते हैं।

पी0डी0एन0ए0 का जो पैसा खर्च नहीं हो रहा है, यह भी इसका एक कारण है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले पौने चार वर्षों में ठेकेदारों ने जो काम किए हैं उनकी पेमैंट कब तक क्लीयर कर दी जाएगी?

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारी स्टेट की चाहे जो पेमैंट्स हैं, चाहे पी0डी0एन0ए0 की हैं, चाहे सी0आर0एफ0 की हैं और चाहे पी0एम0जी0एस0वाई0 की हैं उनको चरणबद्ध तरीके से हर जगह दिया जा रहा है। **स्टेट की जो पेमैंट्स हैं उनके लिए हमने अपने विभाग के सेक्रेटरी और फाइनांस सेक्रेटरी से भी चर्चा की है और जल्द ही इनको पैमेंट्स दे दी जाएगी।**

31.08.2026/1630/टी0सी0वी0/ए0एस0-3

नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब नियम 130 के अंतर्गत प्रस्ताव पर चर्चा होगी । अब माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी नियम 130 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। इस विषय पर माननीय सदस्य श्री सुधीर शर्मा, श्री राकेश जम्वाल, डॉ0 हंस राज और श्री जीत राम कटवाल जी के प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। वे भी चर्चा में भाग ले सकते हैं। अब मैं माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा से आग्रह करूंगा कि वे अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि "युवाओं लिए रोजगार संदर्भित गारंटी के कार्यान्वयन बारे यह सदन विचार करे।"

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "युवाओं लिए रोजगार संदर्भित गारंटी के कार्यान्वयन बारे यह सदन विचार करे।" वैसे इसके लिए कोई निर्धारित समय नहीं है मगर अधिक-से-अधिक दो घंटे का समय है। इस पर कोई मतदान नहीं होगा। माननीय उद्योग मंत्री जी इसका उत्तर देंगे और उसी के साथ चर्चा समाप्त हो जाएगी। अब मैं माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वे विस्तृत रूप में अपना प्रस्ताव इस माननीय सदन में रखें।

एन0एस0 द्वारा ....जारी

31-8-2026/1635/NS-AS/1

अध्यक्ष------जारी

आज सदन 7.00 बजे तक चलेगा और अभी तो 04.30 बजे हैं। मैं तो आप सबसे रिक्वैस्ट ही कर सकता हूं। अभी तक मेरे पास कोई लिस्ट नहीं आई है, न सत्ता पक्ष की तरफ से और न ही विपक्ष की तरफ से तो कृपया लिस्ट भेज दें। माननीय रणधीर शर्मा जी आप बोलिए।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है। युवा ही देश का भविष्य है और युवाओं का भविष्य जितना उज्ज्वल होगा, उतना ही देश का भविष्य उज्ज्वल होगा। परंतु दुःख का विषय है कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार ने देश के भविष्य यानी इस युवा शक्ति को गुमराह करने का काम किया, इस युवा शक्ति को धोखा देने का काम किया और इस युवा शक्ति को ठगने का काम किया।

(श्री संजय रत्न, सभापति महोदय पदासीन हुए)

पिछले विधान सभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता को जो गारंटियां दीं और प्रदेश की जनता से जो वायदे किए तो सत्ता में आने के बाद ये उन गारंटियों को भी भूल गए और वायदे भी याद नहीं हैं। युवाओं से किए गए वायदों पर इस सरकार का नकारात्मक रवैया बहुत ही चिंता का विषय है।

सभापति महोदय, मैं नियम-130 के अंतर्गत लाए गए इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार के ध्यान में वे सारी गारंटियां और वायदे लाना चाहता हूं जो इन्होंने चुनाव के समय युवाओं से किए थे और सत्ता में आने के बाद भूल गए। सभापति महोदय, प्रमुख वायदा जो इन्होंने प्रदेश की युवा शक्ति से किया था, वह यही था कि हम सरकार में आएंगे और पहली ही कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां स्वीकृत करके पहले ही महीने में

उनको भरेंगे। ...(व्यवधान) ऐसा है, मैं आपका घोषणा पत्र साथ लाया हूं, आपने नहीं पढ़ा होगा, मुझसे लेकर पढ़ लेना।

सभापति महोदय, युवाओं से पहला वायदा यह किया था कि पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और एक महीने में उसका पूरा प्रोसीजर हो जाएगा। आज 45 महीने हो गए हैं और 45 महीने में 1 लाख तो दूर यह सरकार 1000

31-8-2026/1635/NS-AS/2

रेगुलर नौकरियां भी नहीं दे पाई है। जो आंकड़ा माननीय मुख्य मंत्री जी प्रैस वार्ताओं और जनसभाओं में देते हैं वह अलग हो सकता है परंतु सदन के अंदर और अभी एक मामले में माननीय उच्च न्यायालय में दिया हुआ आंकड़ा लगभग 23,000 का है। मैं कहना चाहता हूं कि उन 23,000 में आउटसोर्स भी हैं, उसमें वन मित्र भी हैं जिनको आपने कह दिया कि रेगुलर नहीं होंगे। उसमें जॉब ट्रेनीज भी हैं और उसमें पार्ट-टाइम भी हैं जो 10 साल बाद रेगुलर होंगे। उसमें डेली वेज की नौकरियां भी शामिल हैं। जबकि आपने कहा था कि हम तो पक्की नौकरी देंगे, 58 साल वाली देंगे और पेंशन वाली देंगे। उप-मुख्य मंत्री महोदय की वह वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने बड़े जोश के साथ बोला था कि 58 साल नौकरी वाली देंगे, पक्की नौकरी देंगे, पेंशन वाली देंगे। आज वे सदन में नहीं हैं और मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि ऐसी कितनी नौकरियां दी हैं जो नौकरी देते समय ही पक्की थीं और पेंशन वाली थीं? माननीय उद्योग मंत्री जी, आप जवाब देंगे, आप जरूर बताएं कि

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

31.08.2026/1640/RKS/DC-1

श्री रणधीर शर्मा... जारी

इन चार वर्षों में आपने 58 वर्ष वाली पक्की और पेंशन वाली कितनी नौकरियां दी हैं? मेरा आपसे निवेदन है कि यह जानकारी सदन में अवश्य दें ताकि प्रदेश की जनता भी जान सके कि आपने युवाओं से जो वायदा किया था उसे कितना पूरा किया है। सभापति

महोदय, इसके बाद इन्होंने अनेक तरह की बातें कहीं लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि सरकारी नौकरियां देने की बजाय इन्होंने लोगों को नौकरियों से निकालने का काम किया है। इस दौरान 943 कर्मचारियों को सरकारी नौकरी से बाहर किया गया और नौकरियां देने की बजाय लगभग 2500 सरकारी पद समाप्त कर दिए गए। चाहे वे पद विभागों के हों या बोर्ड-निगमों के लेकिन इन्होंने नौकरियां देने की बजाय कर्मचारियों को नौकरियों से निकालने का काम किया है। इन्होंने नए रोजगार के अवसर पैदा करने की बजाय सरकारी पदों को समाप्त करने का काम किया है। आज प्रदेश में जो स्थिति है उसकी जानकारी विधान सभा में भी दी गई है। लगभग एक लाख सरकारी पद अलग-अलग विभागों, बोर्डों और निगमों में खाली पड़े हैं लेकिन सरकार इन पदों को भरने के लिए गंभीर नहीं दिखाई देती। हम यह चर्चा किसी राजनीतिक दृष्टि से नहीं कर रहे हैं। हम केवल इतना चाहते हैं कि आपने युवाओं से जो वायदा किया था उसे पूरा किया जाए। आप इन सभी खाली पदों को एक वर्ष के भीतर भरें तब प्रदेश का युवा समझेगा कि सरकार ने उसके साथ किया हुआ वायदा पूरा किया है। लेकिन इसके लिए आपको कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और तीव्र गति से काम करना होगा। इसके अलावा इन्होंने प्रदेश के लगभग हर व्यक्ति पर किसी-न-किसी रूप में टैक्स लगाकर आर्थिक बोझ डालने का काम किया है और उसमें युवाओं को भी नहीं छोड़ा है। जो युवा सरकारी नौकरी के लिए राज्य चयन आयोग में आवेदन करते थे उनकी परीक्षा फीस 360 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर दी है। यानी परीक्षा शुल्क में लगभग 60 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई। युवाओं पर यह अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया है। हमारी सरकार के समय यदि कोई युवा इंटरव्यू देने जाता था तो उससे बस का किराया तक नहीं लिया जाता था। दूसरी तरफ आपकी सरकार है जो युवाओं से लोक-लुभावने वायदे करके उनके ऊपर परीक्षा शुल्क बढ़ाने का बोझ डालती है। यही आपकी सरकार का काम है। इसके अलावा इन्होंने यह भी वायदा किया था कि हर विभाग की भर्ती या तो राज्य चयन आयोग के माध्यम से होगी या लोक सेवा आयोग

31.08.2026/1640/RKS/DC-2

के माध्यम से की जाएगी। इन्होंने कहा था कि अब न तो विभागों के माध्यम से भर्तियां की जाएंगी और न ही आउटसोर्स के माध्यम से भर्तियां होगी लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत।राज्य चयन आयोग के माध्यम से भर्तियां करवाने की बजाय अब भर्तियां ही बंद हो

गई हैं। जो भर्तियां की गई उनमें भी आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से नियुक्तियां करने का रास्ता अपनाया गया। यह सरकार वैसे तो मित्रों की सरकार है। उप-मुख्य मंत्री जी जब विपक्ष में थे तो 58 साल वाली पक्की और पेंशन वाली नौकरी देने की बात करते थे। एक दिन मैंने उनका इंटरव्यू सुना। उसमें आप कह रहे थे कि 'क्या करें, जरूरी नहीं है कि कैबिनेट में जो निर्णय होते हैं उनसे हम सहमत हों।' उस समय तो आप बड़े असहाय दिखाई दे रहे थे। आपका व्यक्तित्व इतना असहाय कभी नहीं था। पता नहीं सत्ता में आने के बाद आप इतने असहाय क्यों हो गए? यह सत्ता का नशा है या पता नहीं क्या है अन्यथा ऐसा व्यक्ति तो ऐसी कुर्सी को ठोकर मारकर चला गया होता जहां उसकी बात ही न सुनी जाए। प्रदेश में यह कहावत चली हुई है कि वर्तमान सरकार 'आउटसोर्स भर्तियों और मित्रों की सरकार है'। इस सरकार को मंत्रिमण्डल नहीं चला रहा बल्कि मित्र मंडली चला रही है। मुख्य मंत्री जी के कुछ मित्र चेयरमैन और कुछ वाइस चेयरमैन बन गए तथा उनके मानदेय की पूरी चिंता की जा रही है। मैं भी वाइस चेयरमैन था। उस समय मुझे 15,000 रुपये मानदेय मिलता था और वर्ष 2007 में यह राशि बढ़कर 30,000 रुपये हुई थी। अब यह राशि सवा-सवा लाख रुपये हो गई है। जो मित्र चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बने हैं उनको आउटसोर्स एजेंसियां दे दी गई हैं। उन्होंने अपनी आउटसोर्स एजेंसियां खोल ली हैं।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

31.08.2026/1645/बी.एस./ डी.सी.-1

श्री रणधीर शर्मा जारी...

और उनको कहा कि भर्ती करो। अब वे भर्ती कर रहे हैं और उसमें कमीशन खा रहे हैं और पैसे खा रहे हैं। पैसे खाने का आउटसोर्स भर्तियों में घोटाला हो रहा है और उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है।

मैं तो बड़ा हैरान था अभी तीन दिन पहले की बात है। मुख्य मंत्री जी में कितनी गंभीरता है? हमारा तो आरोप है कि आउटसोर्स भर्तियां गलत हैं न इसमें मेरिट है न इसमें रिजर्वेशन का रोस्टर लग रहा है।

मुख्य मंत्री जी के उस बयान ने जब आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी आउटसोर्स एजेंसी का नाम ले रहे थे और बात कर रहे थे कि नर्सिंज की भर्ती में उन्होंने पैसे लिए तो मुख्य मंत्री जी ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि वह आपका प्रतिद्वंद्वी है और वह आपके विधान सभा क्षेत्र का है इसलिए आप बोलते हैं, मैं उसको कहूंगा कि वह 5-7 लोग आपके भी रख ले।

एक मुख्य मंत्री ऐसा कह रहा है इसका मतलब क्या है? सारे लोग ऐसे ही रखे जाते हैं? वह किसी विधायक, मंत्री या मित्र के कहने पर ऐसे ही रखे जाते हैं? विधान सभा में ऑन रिकॉर्ड प्रदेश का मुख्य मंत्री बोले कि आपके भी 5-7 लोग रख लिए जाएंगे।

सभापति महोदय, यह सरकार की गंभीरता दिखाता है कि सरकार नौकरियां देने में कितनी गंभीर है। किस तरह मेरिट को, योग्यता को और आरक्षण को इग्नोर करके अपने चहेतों को और अपने भाई-भतीजों को भरने का काम करती है तथा भ्रष्टाचार को अंजाम देती है। यही इस सरकार की करनी है और दूसरा सभापति महोदय, पहले सिस्टम था, व्यवस्था थी कि कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होती थी और दो साल बाद रेग्युलर होते थे। आपने कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दिया और अब जॉब ट्रेनिज शुरू कर दिये। अब यह जॉब ट्रेनिज क्या है? सभापति महोदय, आप हैरान होंगे इस सरकार में डॉक्टर भी जॉब ट्रेनी भर्ती हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री महोदय बैठे हैं। चमियाना में पी0जी0 करके आया हुआ डॉक्टर को आप जॉब ट्रेनी की नौकरी दे रहे हो और तनख्वाह 34,000 रुपये दे रहे हैं।

31.08.2026/1645/बी.एस./ डी.सी.-2

आपके पास डॉक्टर क्यों आएंगे, नौकरी क्यों करेंगे? पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर बनने में कितना खर्चा होता है? पूरी जवानी खपती है और आप नौकरी दे रहे हो 34,000 रुपये यानी क्लास फोर से भी कम।

कोई तो नीति बनाइए, कोई तो पॉलिसी बनाइए किसी को तो छोड़ो। स्टाफ नर्सिज को आउटसोर्स पर भर्ती करें। डॉक्टरों को जॉब ट्रेनिज पर भर्ती कर रहे हैं फिर कह रहे हैं कि स्वास्थ्य में तो क्रांति आ गई। कौन-सी क्रांति और कैसी क्रांति आ रही है?

आप डॉक्टरों की पोस्टिंग करते हैं और वह ज्वाइन ही नहीं करते क्योंकि उन्हें जॉब ट्रेनिंज का लेटर मिलता है। जॉब ट्रेनी कोई डॉक्टर नहीं आएगा। उसने इंटर्नशिप भी की है उसने रजिस्टारशिप भी की है। वह पी0जी0 में भी सारी ट्रेनिंग करता है और पी0जी0 करने के बाद भी आप जॉब ट्रेनिंज की नौकरी देंगे तो आपके पास डॉक्टर नहीं आएंगे। फिर आपने एक नया मेथड ढूंढा। 'वन मित्र' 'पशु मित्र' और मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि 'बिजली मित्र' भी भरने हैं। मित्रों को भर्ती करने का क्या तरीका है?

हमने सोचा कि चलो मित्रों की भर्ती है तो इसमें भला होगा। हमने विधान सभा में प्रश्न लगा कर पूछा और मेरे पास जवाब भी है कि क्या ये रेग्युलर होंगे? कहते हैं कि नहीं इनको रेग्युलर करने का कोई प्रावधान नहीं है।

आपने एक वायदा किया था और यह आपके प्रतिज्ञा पत्र में था कि हम आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाएंगे और धीरे-धीरे आउटसोर्स भर्ती को बंद करके रेग्युलर भर्ती की ओर जाएंगे। आपने रेग्युलर से दस गुना ज्यादा तो आउटसोर्स भर्तियां की हैं।

जो आउटसोर्स पर रेगुलर करने की नीति बनाने की बात है उसे भी जब विधान सभा में पूछा गया तो आपने यही कहा कि आउटसोर्स भर्ती वालों को नियमित करने की कोई नीति सरकार के विचाराधीन नहीं है। नीति तो नहीं बनाई लेकिन नीति विचाराधीन भी नहीं है। यह स्पष्ट करता है कि आपने ये वादे सिर्फ वोट लेने के लिए किए थे काम करने के लिए नहीं किए थे।

31.08.2026/1645/बी.एस./ डी.सी.-3

इसके बाद आपने क्या वादा किया था? आपने पांच लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। मुख्य मंत्री जी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। कितने लोगों को रोजगार

दिया? आपने गारंटी में लिखा है कि स्टार्टअप योजना के लिए 10 करोड़ रुपये हर विधान सभा क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में 680 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

31.08.2026/1650/DT/HK-1

श्री रणधीर शर्मा जारी...

मुझे बताइए की आपने किस विभाग को और किस विधान सभा क्षेत्र वह पैसे दिए। मुझे बताइए कि 680 करोड़ रुपये कहां दिए गए हैं; आप किसको गुमराह कर रहे हैं? उस युवा शक्ति को गुमराह कर रहे हैं जो इस देश का भविष्य है। आपने कितनों को रोजगार दिए हैं, आप इसके आंकड़े बता दें। आपने अपने गारंटी पत्र में पांच लाख रोजगार देने की बात कही है। माननीय श्री संजय अवस्थी जी पांच लाख में कितने शून्य लगते हैं, यह भी देख लेना। अभी आप हमारी बात सुने। अगर आप उस पर चर्चा लेंगे तो उसका जवाब हम देंगे, लेकिन इस बात का जवाब तो आप ही देंगे। मेरा आरोप है कि सरकार ने रोजगार देने के बजाय रोजगार के अवसर बंद करने का काम किया है।

पूर्व भाजपा सरकार ने समय मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना शुरू की थी। उस समय श्री जय राम ठाकुर जी मुख्य मंत्री थे और श्री बिक्रम सिंह जी उद्योग मंत्री थे। उस समय यह योजना शुरू की गई थी। कोई भी व्यक्ति जिसके पास रोजगार का साधन नहीं था वह इस योजना के अंतर्गत 40 लाख रुपये का ऋण ले सकता था और उसमें 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती थी। यह होती है युवाओं को रोजगार देने की पॉलिसी।

श्री हर्षवर्धन जी आपने उस योजना को बंद तो नहीं किया परंतु उसके लिए बजट का प्रावधान भी नहीं किया। क्या यह भी एक नई पॉलिसी है इस सरकार की इस योजनाएं को बंद नहीं करते हैं बल्कि उस योजना में बजट का प्रावधान ही नहीं करते, फिर कहते हैं कि योजनाएं तो बंद नहीं की हैं। हिमकेयर और सहारा योजना का भी यही हाल है और मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना का भी यही हाल है। ऐसी जनहितैषी योजना ही बंद कर दी इससे पता चलता है कि सरकार कितनी गंभीर हैं? फिर इन्होंने क्या किया? बिजली की दरों में उद्योगपतियों के लिए भी 55 प्रतिशत वृद्धि करके उद्योगों का गला घोंटने का काम किया है। हिमाचल प्रदेश में उद्योग क्यों आते थे? हिमाचल प्रदेश में न रॉ मटेरियल है न मार्केटिंग है। यहां इंडस्ट्री तभी आएगी जब उसको कुछ इनसेंटिव मिलेगा, सस्ती जमीन मिलेगी, सस्ती बिजली मिलेगी और

31.08.2026/1650/DT/HK-2

कुछ टैक्स में रिबेट मिलेगी । इसलिए आदरणीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था। अधिकांश इंडस्ट्रीज उसी समय आई थीं। आपकी सरकार आई थी और आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने उसकी समय-सीमा ही कम कर दी थी। तो वह पैकेज देना तो दूर आपने बिजली की दरें बढ़ाकर उद्योगपतियों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया। उद्योगपतियों को हिमाचल छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। कहां से आएंगे उद्योग? और सभापति महोदय उद्योग आने से निवेश भी बढ़ता है। निवेश बढ़ता है तो हमारी पर-कैपिटा इनकम बढ़ती है और हमारी लोन की लिमिट बढ़ती है जिससे हम युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। परंतु आपके इस सिंगल निर्णय से आपने इस इन्वेस्टमेंट के सारे दरवाजे बंद किए और प्रदेश को बहुत भारी नुकसान किया है। उसके बाद हमारी केंद्र सरकार ने आपको मेडिकल डिवाइस पार्क दिया था। कितने युवाओं को रोजगार मिलना था? वर्तमान सरकार ने उस मेडिकल डिवाइस पार्क को शुरू से मना कर दिया। जो 100 करोड़ रुपये आए थे वह भी वापस कर दिए। क्या उद्देश्य था? क्या आपने उससे कमाया? आपने युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे बंद किए। आपने इन्वेस्टमेंट बंद करके प्रदेश को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का काम किया और फिर आप बोलते हैं कि हम युवाओं के हितैषी हैं। एक और दिया था बल्क ड्रग पार्क। और सभापति महोदय उसकी जो जमीन की क्लियरेंस थी और बाकी फॉर्मेलिटीज थीं उनको पूरा करने में तीन वर्ष लगा दिए और अभी आप उसको बनाने में बजट का दसवां हिस्सा भी खर्च नहीं कर पाए हैं। केंद्र पैसे दे रहा है और आपने खर्च करना है। आपसे वही पैसा खर्च नहीं हो रहा है। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी? आप क्या सरकार चला रहे हैं; यह हमारी समझ से परे है। आप सोचते हैं कि ये जो स्टोन क्रशर हैं केवल यही इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का काम है? इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में स्टोन क्रशर तो ऐसे ही हैं। असली काम इंडस्ट्री लाना है और इन्वेस्टमेंट लाना है। उस ओर ध्यान दीजिए। आप चार वर्ष में इन्वेस्टमेंट कहीं कर ही नहीं पाए हैं और स्टोन क्रशरों के पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए प्रदेश की युवा शक्ति आज सोचने पर मजबूर है। सभापति महोदय, आपके बारे में भी मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ भविष्य में कुछ अच्छा होने वाला है। आप अध्यक्ष नहीं तो उपाध्यक्ष के पद पर तो पक्का आसीन होंगे।

श्री0एन0जी0 द्वारा जारी...

31.08.2026/1655/एच.के.-एन.जी./1

श्री रणधीर शर्मा......... जारी

...(व्यवधान) मैं कुछ नहीं बोला। आपके साथी ही बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं बोला।

सभापति : माननीय सदस्य, आप अपना वक्तव्य कंप्लीट कीजिए।

श्री रणधीर शर्मा : सभापति महोदय, इस सरकार ने बेरोजगारी दूर करने का एक और अनूठा व नायाब तरीका ढूंढा है। अलग ही तरीका है और हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। हम तभी कहते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री गजब की सोच रखते हैं। इन्होंने सोचा कि युवा पढ़-लिख जाते हैं, डिग्रियां ले लेते हैं और फिर नौकरी व रोजगार मांगते हैं। इसलिए स्यापा ही खत्म करो और ऐसा काम करो कि नौजवान पढ़ ही न सकें। इन्होंने इस कार्यकाल में 1,300 से ज्यादा स्कूल और 18 कॉलेज बंद किए हैं ताकि युवा पढ़ न सकें। युवा पढ़ेगा ही नहीं तो नौकरी या रोजगार कहां से मांगेगा? ...(व्यवधान) सर, आपका (माननीय शिक्षा मंत्री को कहा) ही विधान सभा में दिया हुआ उत्तर है। मेरा स्वारघाट कॉलेज आपने बंद किया है। उन 18 कॉलेजों में वह भी एक है।...(व्यवधान) कब हुआ? मुझे नोटिफिकेशन दे दो।...(व्यवधान) शिक्षा मंत्री जी, आप विभाग में रहते हैं तो मुझे नोटिफिकेशन दे दो। आपने 18 कॉलेज बंद किए हैं। सरकार क्या करती है कि नौजवान पढ़े नहीं।...(व्यवधान) इनकी योजना क्या है? युवा पढ़-लिखकर नौकरी न मांगे, वे भांग की खेती करें। भांग उगाएं और उससे रोजगार प्राप्त करें। फिर ये कहते हैं कि हम चिट्टे के खिलाफ हैं। Bhang is the gateway of the drugs. जब आप भांग को वैध करोगे तो आप युवाओं को ड्रग्स की ओर बढ़ने से कैसे रोक सकते हो, मुझे फॉर्मूला बताओ? क्यों आप इस

बात पर अडिग हैं कि भांग की खेती करनी है? क्या यही एक रोजगार का साधन है? इसके अलावा प्रदेश में और क्या-क्या नहीं हो सकता?

31.08.2026/1655/एच.के.-एन.जी./2

आप काम करो, टूरिज्म को बढ़ाओ, इंडस्ट्री लाओ और उसमें रोजगार दो। क्या यह सही है कि भांग की खेती करो? उससे जो बचेगा, उसे सरकार कहती है कि लॉटरी खरीदो। लॉटरी की योजना दीपावली से शुरू होगी। युवाओं को दीपावली का तोहफा लॉटरी के रूप में दिया जाएगा। जब हमारे नेताओं ने इसका विरोध किया तो मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि "हम किसी को मजबूर थोड़ी न करेंगे, यह तो भाग्य का खेल है।" मजबूर तो आप चिट्टे के लिए भी नहीं करते। मजबूर तो आप शराब के लिए भी किसी को नहीं करते। मजबूर तो और नशों के लिए भी नहीं करते। लेकिन जब कोई चीज उपलब्ध हो जाती है, तो युवा या कोई भी व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित होकर भटक जाता है। इसलिए हमने कहा कि चिट्टा रोकना है तो पहले चिट्टे के सरगनाओं को पकड़ो। मगरमच्छों पर कार्रवाई करो। मछलियों को पकड़ कर काम नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि युवा उज्ज्वल भविष्य लेकर आगे बढ़ें और काम करें, तो यह लॉटरी व जुआ बंद करो। आपने युवाओं का मजाक बना कर रख दिया है। आदरणीय प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी ने वर्ष 2002 में इस लॉटरी को बंद किया था। कुछ सोचकर ही किया होगा। उस समय किस तरह से परिवारों के परिवार उजड़ रहे थे। यह लॉटरी वह चीज है कि जब एक बार व्यक्ति खरीदता है, उसे घाटा पड़ता है, फिर खरीदता है, फिर खरीदता है। पैसे खत्म होते हैं तो घर से चोरी करके खरीदता है। आप यह लॉटरी शुरू करके हिमाचल प्रदेश के लाखों परिवारों को तबाह करने का काम शुरू कर रहे हैं। इसलिए यह रोजगार नहीं हो सकता। मैंने पहले भी कहा, आप रोजगार देने का काम करो। वह आपका काम है, उसको आप कीजिए। लेकिन उसकी ओर आपका ध्यान नहीं है।

सभापति महोदय, इन्होंने तो महिलाओं को 1,500 रुपये देने की बात भी की थी।...(व्यवधान) हां जी बाली साहब, नमस्कार। (माननीय सदस्य श्री आर0एस0 बाली को कहा) आप तो युवाओं की चिंता करते हैं। इसलिए सरकार को जरा बोला करो कि युवाओं का कुछ ध्यान रखा करें। आपके होटल आपकी मर्जी के बिना ही बंद हो रहे हैं।

31.08.2026/1655/एच.के.-एन.जी./3

आप कह रहे हैं, हम बेचेंगे नहीं और मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि ऑक्शन करो। थोड़ा दबंग होकर रहिए।

सभापति महोदय, इन्होंने महिलाओं को 1,500 रुपये देने का वादा किया था। अब आप बोलेंगे कि यह युवाओं की चर्चा है, महिलाओं की चर्चा नहीं है। परंतु 18 से 35 साल की लड़कियां-युवतियां भी आपके इस 1,500 रुपये के लालच में आ गई थीं। उन्होंने भी आपको यही सोचकर वोट दिया था कि कांग्रेस की सरकार आएगी और जनवरी 2023 में मेरे खाते में 1,500 रुपये आ जाएंगे।

पी0बी0 द्वारा......जारी

31.08.2026/1700/YK/PB/1

श्री रणधीर शर्मा जारी...

उन्होंने आपको यही सोचकर वोट दिया था कि कांग्रेस की सरकार आएगी और जनवरी, 2023 में मेरे खाते में 1,500 रुपये आ जाएंगे। (***) यह आपकी सरकार की हालत है।...(व्यवधान)

सभापति : माननीय सदस्य द्वारा मुख्य मंत्री जी के लिए कहे गए शब्दों को एक्सपंज किया जाए। माननीय सदस्य आप रोजगार पर बोलें।

श्री रणधीर शर्मा : सभापति महोदय, मैं रोजगार पर ही बोल रहा हूं।

सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज वाइंड अप। हमारे पास केवल दो घंटे का समय शेष है और अभी काफी वक्ताओं ने इस चर्चा में भाग लेना है।

श्री रणधीर शर्मा : सभापति महोदय, मुझे केवल दो मिनट का और समय दीजिए। इन्होंने रोजगार के लिए कुछ और वादे किए थे। मैंने शुरू में कहा था कि मैं सरकार को वे वादे याद दिलाऊंगा और अब मैं उन वादों को पढ़ता हूं। मैं विधायकों से आग्रह करूंगा कि अगर ये वादे पूरे किए हैं तो आप हां बोल देना और अगर पूरे नहीं किए हैं तो न बोल देना।

सरकार ने कहा था कि एक कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां और 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे तथा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। यह बातें तो हो गई। इन्होंने यह भी कहा था कि प्रदेश के निजी उद्योगों में 80 प्रतिशत हिमाचल के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की नीति लागू की जाएगी। क्या हुआ? ...(व्यवधान) विभागों, निगमों और बोर्डों में तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अलग से नीति बनाई जाएगी। क्या नीति बनी? ...(व्यवधान) मनरेगा के तहत कार्य दिवस बढ़ाकर 150 किए जाएंगे। क्या कार्य दिवस बढ़ाए गए? ...(व्यवधान) कांग्रेस सरकार हिमाचल में युवा आयोग का गठन करेगी। क्या युवा आयोग का गठन हुआ? ...(व्यवधान) पंचायत स्तर पर प्रदेश भर में युवा क्लबों की स्थापना की जाएगी जिसमें युवा खेल-कूद के अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी अपना योगदान दे सकेंगे। क्या ये युवा क्लब बने? ...(व्यवधान) हर जिले में प्रतियोगी

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

31.08.2026/1700/YK/PB/2

परीक्षाओं के लिए सर्वसुविधायुक्त कोचिंग सैंटर स्थापित किए जाएंगे। क्या कोचिंग सैंटर खुले? ...(व्यवधान) मुख्य मंत्री जी आप भी बोलिए, आपके विधानसभा क्षेत्र में भी नहीं खुले हैं।...(व्यवधान) ग्रामीण स्तर पर क्रिकेट के साथ कबड्डी, हॉकी, वॉलीबाल तथा पारंपरिक खेलों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। कहां मिल रहा है? ...(व्यवधान) हर विधान सभा क्षेत्र में खेलों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए कोचिंग केंद्रों की स्थापना की जाएगी और वहां अनुभवी प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। क्या हुआ? ...(व्यवधान) खेलों में

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की जाएगी और उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी। कितनी नौकरियां दी गईं? ...(व्यवधान) चार साल में कितनी नौकरियां दी गई? ...(व्यवधान) आप मुझे उसकी लिस्ट दे देना।...(व्यवधान) पंचायत स्तर पर युवाओं के लिए जिम और पुस्तकालय खोले जाएंगे। कहां खुले? ...(व्यवधान) किस विधानसभा क्षेत्र में खुले? ...(व्यवधान)

सभापति महोदय, यह इनका कच्चा चिट्ठा है। अब मैं इसे काला चिट्ठा बोलूंगा तो ये कहेंगे कि यह अनपार्लियामेंटरी शब्द है। यह इनका कच्चा चिट्ठा है कि इन्होंने क्या-क्या वादे किए थे और उनमें से कितने पूरे किए हैं।

उप-मुख्य मंत्री : सरकार ने पहली कैबिनेट में ओ0पी0एस0 का वादा किया था। वह दिया कि नहीं? ...(व्यवधान)

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों से पूछिए कि ओ0पी0एस0 प्राप्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कितनी राशि मिल रही है। उससे अधिक देनदारियां मेडिकल रिम्बर्समैंट और डी0ए0 की किस्तों के रूप में कर्मचारियों की आपने कर दी हैं। वर्तमान कर्मचारियों को डी0ए0 की किस्तें न देने के कारण 20-20 हजार रुपये कम सैलरी मिल रही है। इसलिए आपकी सरकार युवा विरोधी तो है ही और कर्मचारी विरोधी भी है। यह मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने युवाओं को धोखा दिया है, उन्हें गुमराह किया है और उन्हें ठगने का काम किया है। इस सरकार का पूरा चेहरा, चाल और चरित्र युवा विरोधी है। इसलिए यही युवा शक्ति आने वाले विधान

31.08.2026/1700/YK/PB/3

सभा चुनावों में इन्हें सत्ता से बाहर करेगी और ये दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं करेंगे। यह मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति : उद्योग मंत्री जी।

उद्योग मंत्री : सभापति महोदय, श्री रणधीर शर्मा जी ने इस चर्चा की शुरुआत की और बेरोजगारों के इश्यू पर चर्चा करते हुए उन्होंने बहुत सारे अन्य इश्यूज़ भी उठाए हैं। खासकर इंडस्ट्री के मामले में उन्होंने बल्क ड्रग और मेडिसिनल डिवाइस पार्क के बारे में कहा है। यह बात ठीक है कि मेडिसिनल डिवाइस पार्क और बल्क ड्रग पार्क जब आपकी सरकार थी, तब आपने On the basis of bidding इन्हें लिया था।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

31.08.2026/1705/वाई0के0/ए0पी0-01

उद्योग मंत्री जारी .....

हमारी सरकार बनी तो हमने देखा कि कोई भी प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से वायबल है या नहीं और स्टेट के हित में है या नहीं है। जब हिमाचल को ये प्रोजेक्ट मिला था तब इन्होंने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ शिलान्यास हुआ था, न तो कागजी कार्रवाई हुई थी और न ही जमीन पर कोई कार्रवाई हुई थी। मेडिसिनल डिवाइस पार्क के लिए 1,500 बीघा लगभग 300 एकड़ जमीन, हिमाचल प्रदेश की इन्होंने एक रुपये प्रति मीटर के हिसाब से बेच दी थी। इसकी कीमत लगभग 150 करोड़ रुपये थी। साथ ही, इन्होंने उद्योगपतियों को तीन रुपये प्रति यूनिट बिजली देने की बात कही थी। अगर मेडिसिनल डिवाइस पार्क में तीन रुपये प्रति यूनिट बिजली दी जाती तो हिमाचल प्रदेश को लगभग 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ता। इस तरह 150 करोड़ रुपये का नुकसान जमीन देकर और 200 करोड़ रुपये का नुकसान बिजली देकर, यानी लगभग 350-से-400 करोड़ रुपये का नुकसान हिमाचल प्रदेश को होना था। मगर जब कैबिनेट और मुख्य मंत्री जी ने देखा कि this project is not in the interest of the State और यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से भारत सरकार से फंडेड भी नहीं है तो हमने इस पर फैसला लिया। इस प्रोजेक्ट की कुल कीमत 350 करोड़ रुपये थी। भारत सरकार को इसमें 100 करोड़ रुपये देने थे और 250 करोड़

रुपये राज्य सरकार को देने थे। जब कैबिनेट ने देखा कि मेडिसिनल डिवाइस पार्क के लिए है जो एग्रीमेंट हुआ है, it is not in the interest of the State. हिमाचल सरकार को भारत सरकार से 35 करोड़ रुपये की जो किश्त आई थी, वह हमने ब्याज सहित भारत सरकार को वापस कर दी है। मेडिसिनल डिवाइस पार्क का हमने 90 प्रतिशत काम कर दिया है। हमने यह भी फैसला किया है कि मेडिसिनल डिवाइस पार्क में जमीन के हिस्से से जो पैसा आएगा, उसमें से पहले चरण में हम 40 प्रतिशत पैसा लेंगे। जिस भी उद्योगपति को जमीन देंगे, उससे पहले ही 40 प्रतिशत पैसा लिया जाएगा और जो अधूरी चीजें हैं, उन्हें हम पूरा करेंगे। एक बात और मैं कहना चाहता हूं।

बल्क ड्रग पार्क के बारे में भी मैं जिक्र करना चाहता हूं। बल्क ड्रग पार्क, मेडिसिनल डिवाइस पार्क की तुलना में स्टेट के लिए आर्थिक रूप से वायबल प्रोजेक्ट है क्योंकि बल्क

31.08.2026/1705/वाई0के0/ए0पी0-02

ड्रग पार्क की 50 प्रतिशत फंडिंग भारत सरकार करेगी और 50 प्रतिशत राज्य सरकार करेगी। कैबिनेट ने फैसला किया था कि हम इसको पी0पी0पी0 मोड पर दे दें मगर बाद में कैबिनेट ने फैसला किया कि नहीं, इसे राज्य सरकार फंड करेगी। इसमें देरी जरूर हुई है। जब आप गए थे उस समय इसमें कुछ काम नहीं हुआ था क्योंकि पर्यावरण संबंधी क्लीयरेंस भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से लेने में समय लग गया। यह रेड जोन की इंडस्ट्री है इसलिए भारत सरकार की ओर से इसमें बहुत सारी क्वेरी आई और हार्ड एनवायरनमेंट क्लीयरेंस, प्रदूषण से संबंधित व्यवस्थाएं और जैड़0एल0डी0 प्लांट जैसी चीजें लगनी थीं। इन सब कारणों से इसमें देरी हुई है। मगर हमने 25 प्रतिशत जमीन लेवल कर दी है, सारे टेंडर कर दिए हैं। पानी मेडिसिनल डिवाइस पार्क तक पहुंच गया है और बिजली का लगभग 80 प्रतिशत काम हमने कर लिया है। अगले तीन-से-चार महीने में, इस साल के अंत तक, बल्क ड्रग पार्क में लैंड अलॉट कर देंगे और अगले साल मार्च तक इसको फंक्शनल कर लेंगे। सभापति महोदय, मुझे यह बात स्पष्ट करनी थी।

सभापति : माननीय शिक्षा मंत्री।

शिक्षा मंत्री : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी हमारे विधान सभा के बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं और बड़े वरिष्ठ सदस्य भी हैं। लेकिन कई दफा प्रखर वक्ता होने के साथ-साथ भावनाओं में भी बह जाते हैं। इन्होंने मेरे विभाग से संबंधित कुछ बातें यहां पर रखी हैं जोकि तथ्यों के विपरीत हैं। जैसे यहां पर माननीय सदस्य श्री हरदीप सिंह जी ने भी कहा, मैं इसके बारे में इनको पूरी जानकारी देना चाहूंगा। मेरे पास इस समय संबंधित कागज भी थे और इससे संबंधित प्रश्न परसों भी लगा था लेकिन बाद में इस प्रश्न का कोई सप्लीमेंट्री नहीं ले पाए थे। हिमाचल प्रदेश में आपके जो स्कूल डिमोटिफाई और डाउनग्रेड हुए हैं, उनकी कुल संख्या 1,526 बनती है। आपने 1,300 बोला था इसलिए मैं आपको अपडेट कर रहा हूं कि कुल संख्या 1,526 है। इसमें से 734 स्कूल ऐसे थे जहां एक भी बच्चा नहीं था। वहां जीरो एनरोलमेंट थी। हम कह सकते हैं कि लगभग 50 प्रतिशत ऐसे स्कूल थे जहां एक भी बच्चा या एक भी स्टूडेंट नहीं था। इसके अलावा इन 1,526 स्कूलों में कुल 1,796 स्टूडेंट थे और

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

31.08.2026/1710/AT/AG/01

शिक्षा मंत्री जारी .....

जो कुल टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ हमें यहां से मिला है, उसमें से लगभग 50 प्रतिशत तो वैसे ही आपके जीरो-एनरोलमेंट वाले स्कूल थे। चार हजार से अधिक स्कूलों में से लगभग 2,170 शिक्षक हमें मिले हैं और जो हमने पैरामीटर बनाया था, वह भी बड़ा स्पष्ट, क्रिस्प और क्लियर था कि 2 किलोमीटर के भीतर अगर आपके पास दूसरी प्राथमिक पाठशाला है, तो आपका स्कूल वहां मर्ज किया जाएगा। मिडिल स्कूलों के लिए हमने 3 किलोमीटर का क्राइटेरिया रखा था और यह केवल हिमाचल प्रदेश में ही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर आपके पास बॉर्डर स्टेट्स हैं। गत 10 वर्षों में, जब से हमारी एन0डी0ए0 सरकार है, लगभग 10-12 वर्षों में पूरे हिंदुस्तान में करीब एक लाख स्कूल डाउनग्रेड और डिनोटिफाई हुए हैं।

मैं जहां तक कॉलेज की बात करूंगा, हमारे समय में मात्र एक कॉलेज ऐसा था, जहां पर अपकी नाममात्र की एनरोलमेंट रह गई थी। दो या छह बच्चों के लिए कॉलेज नहीं खोला जाता। बाकी सभी कॉलेज आपके चले हैं। धन्यवाद।

सभापति : अब माननीय सदस्य श्री सुधीर शर्मा जी इस चर्चा में भाग लेंगे। प्लीज़, हो गया, हो गया रणधीर शर्मा जी।

श्री सुधीर शर्मा : माननीय सभापति महोदय, नियम-130 के अंतर्गत युवाओं के लिए रोजगार संबंधी गारंटी के कार्यान्वयन के संदर्भ में जो प्रस्ताव हमने रखा है, मैं उसके ऊपर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, बेरोजगारी आज हमारे प्रदेश का एक ज्वलंत मुद्दा है और यह पहले भी रहा है। मैं यह नहीं कहता कि यह आज ही पैदा हुआ है। इस सदन में इस प्रस्ताव के माध्यम से उन लाखों युवाओं की भावना को रखने के लिए मैं अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। सभापति महोदय, मैं कोई राजनीतिक आंकड़ा नहीं मांग रहा हूं। सरकार के अपने दस्तावेज हैं। इस सदन के अंदर हमारे द्वारा किए गए प्रश्नों के उत्तर आए हैं। सत्ता में आने से पहले तो मैं भी पक्ष में ही था, उस समय युवाओं के साथ बड़े-बड़े वादे किए गए थे।

31.08.2026/1710/AT/AG/02

इन वादों में कहा गया था कि पहली ही कैबिनेट की बैठक में एक लाख पक्की नौकरियां और 58 वर्ष तक की आयु की स्थायी नौकरी देने की बात की गई थी। सार्वजनिक रूप से यह भी कहा गया था कि प्रदेश में 63 हजार पद खाली हैं और 37 हजार नए पद सृजित करके एक लाख पक्की नौकरियां दी जाएंगी।

मैं सरकार को सदन के आंकड़े ही बताना चाहता हूं। सभापति महोदय, हमारे प्रश्न भी बड़े पीछे-पीछे लगते हैं। 21 अगस्त 2026 को इसी सत्र में प्रश्न संख्या-3098 के जवाब में सरकार ने विभागवार स्वीकृत भरे हुए और रिक्त पदों का विवरण दिया। इन आंकड़ों के संकलन के अनुसार 76 हजार से अधिक पद रिक्त हैं। यह हमारा लगाया हुआ कोई आरोप

नहीं है ओर न मैं इसे बनाकर लाया हूं। यह इस सदन के दस्तावेज हैं। इसमें स्कूल शिक्षा में 15,210 और उच्चतर शिक्षा में 6,961 पद रिक्त हैं। यानी केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही 22,171 पद रिक्त हैं।

सभापति महोदय, साथ ही 21 अगस्त को ही दूसरा प्रश्न था, प्रश्न संख्या-3316, जिसमें सरकार ने राज्य चयन आयोग से संबंधित आंकड़े दिए थे। उसमें सरकार के जवाब के अनुसार, 31 जुलाई 2025 तक राज्य चयन आयोग के गठन के बाद 2,977 अभ्यर्थियों की संस्तुतियां विभिन्न विभागों को भेजी गई हैं। यानी जिस प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या इतनी बड़ी है, वहां आयोग के गठन के बाद भी संस्तुतियों की संख्या केवल 2,977 पर है। इससे भी बड़ा सवाल भर्ती की प्रक्रिया को लेकर उत्पन्न हुआ है। सरकार ने जवाब में बताया कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला द्वारा पिछले तीन वर्षों में 143 अधिसूचनाएं और 107 परीक्षाएं आयोजित की गईं तथा 105 अंतिम परिणाम घोषित किए गए। राज्य चयन आयोग, हमीरपुर से संबंधित आंकड़ों में 30 पोस्ट कोड के अंतिम परिणाम घोषित होने की बात भी कही गई है।

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी.....

31.08.2026/1715/av/ag/1

श्री सुधीर शर्मा-------जारी

सभापति महोदय, आज परिस्थिति ऐसी है कि हमारे प्रदेश के युवा केवल परिणाम, परीक्षा और अधिसूचना इत्यादि का ही इंतजार कर रहे हैं कि स्थाई नौकरी का कुछ-न-कुछ तो हल निकलेगा। मैं यह नहीं कहता कि सभी को सरकारी रोज़गार या पक्की नौकरी मिल सकती है। मैं जानता हूं कि हमारी वित्तीय परिस्थिति कैसी है परंतु जितनी भी दी जाएं उसमें कम-से-कम यह सुनिश्चित किया जाए कि वे नौकरियां स्थाई आधार पर दी जाएं। प्रदेश में पहले अनुबंध आधार पर नौकरियां दी जाती थीं, उसके बाद आउटसोर्स शुरू हुआ और अब जॉब ट्रेनी की पॉलिसी आई है। यहां पर जैसे माननीय विधायक श्री रणधीर शर्मा ने कहा कि जॉब ट्रेनी के आधार पर 34,000 तो डॉक्टर्ज रखे जा रहे हैं। इस बारे में मेरा

एक प्रश्न भी लगा था परंतु जब मैं सदन के अंदर पहुंचा तो वह प्रश्न विलोप कर दिया था। उस प्रश्न के माध्यम से यह पूछा गया था कि इलैक्ट्रोनिक्स डवलपमैंट कॉरपोरेशन के माध्यम से कितनी भर्तियां हुई हैं। उसके उत्तर में कहा गया कि अभी इस बारे में केस चल रहा है और बहुत सारे लोग हाई कोर्ट चले गए हैं। इसलिए हमने हाई कोर्ट को जानकारी दी है परंतु इस सदन के अंदर नहीं दी।

सभापति महोदय, 34,000 डॉक्टर्ज जॉब ट्रेनी के आधार पर रखे जाएंगे और इलैक्ट्रोनिक्स डवलपमैंट कॉरपोरेशन के माध्यम से चण्डीगढ़ में चार हिमकेयर फेसिलिटेटर्ज 90-90 हजार रुपये पर रखे गए हैं। जबकि हिमकेयर योजना तो बंद है और ये पिछले वर्ष सितम्बर माह से रखे गए हैं जिसका जिक्र इस नोटिफिकेशन में है। आप चाहे तो मैं इसको ले कर दूंगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि वर्तमान सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के अंतर्गत रोज़गार देने का इस प्रकार का तरीका अपनाया है। रोज़गार मोडल के बारे में पूछने पर सरकार द्वारा इसी प्रश्न के जवाब के परिशिष्ट में बताया गया है कि अलग-अलग विभागों में पद नियमित, अनुबंध, पूर्व सैनिक सैल, पदोन्नति, विभागीय भर्ती तथा अन्य माध्यमों से भरे गए। इसमें कुल 7714 पद अनुबंध आधार पर भरे जाने का आंकड़ा दिखाया गया है। मैं समझता हूं कि जो जॉब ट्रेनी, अनुबंध और आउटसोर्स इत्यादि आधार पर रोज़गार देने का आधार है, यह वर्तमान सरकार ने यहां पर ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन का सीधा-सीधा नमूना पेश किया है। यह

31.08.2026/1715/av/ag/2

भी सदन के अंदर सरकार ने ही बताया है कि कम्प्यूटर आधारित परीक्षा टी0सी0एस0 के साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमैंट किया गया है। सी0बी0टी0 परीक्षाओं के लिए प्रदेश में 29 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं जिनकी क्षमता 3449 अभ्यार्थी हैं। इसकी निविदा में दो कम्पनीज ने भाग लिया और टी0सी0एस0 का चयन हुआ। जब परीक्षा केंद्र हैं और तकनीकी एजेंसी है तथा हजारों पद खाली हैं तो भर्ती में इस प्रकार से देरी क्यों हो रही है? प्रदेश का युवा यह बात पूछ रहा है कि जब सारी चीजें यानी पोस्ट्स इत्यादि सब कुछ हैं तो इस प्रकार से देरी क्यों हो रही है? इस प्रकार से जो नौकरियां दी जा रही हैं और जो आउटसोर्स भती के लिए

ठेकेदार बना दिए गए हैं। उन्होंने भी शायद लम्बा संघर्ष किया होगा, कुछ नहीं बन पाए तो आउटसोर्स एजेंसी ले ली और प्रदेश के बेरोज़गार युवा से पैंसों का दोहन करना शुरू कर दिया। यह एक तरह से धोखा है और अंग्रेजी में एक कहावत है कि if you forgive the fox for stealing your chicken, he will take your sheep, यह भी वैसा ही है। अभी विज्ञापन की बात हो रही थी कि दिखाया कुछ तथा दिया कुछ यानी पैकेट में बाहर से कुछ और दिखाया गया था परंतु खोलने पर उसमें से कुछ अलग चीज निकलती है। मेरा मतलब वर्तमान सरकार द्वारा नौकरी देने की बात की गई और अब जॉब ट्रेनी की बात की जा रही है। वर्तमान सरकार द्वारा इस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं और प्रदेश की जनता इनको देख रही हैं। हमारा युवा समझ रहा है क्योंकि आज प्रदेश का युवा पढ़ा-लिखा है। आज की पीढ़ी हमसे भी ज्यादा जानकारी रखती है। यहां पर जो 76,000 पद खाली हैं मैं उसका थोड़ा-सा ब्रेकअप देता हूं। शिक्षा विभाग में 22171, लोक निर्माण विभाग में 20772, एच0पी0एस0ई0बी0एल0 में 11610, जल शक्ति विभाग में 4414, पुलिस विभाग में 3899,

टी सी द्वारा जारी

31.08.2026/1720/टी0सी0वी0/ए0एस0-1
श्री सुधीर शर्मा ... जारी

राजस्व में 3,412, तकनीकी शिक्षा में 2,506, कृषि में 1,647 तथा ग्रामीण विकास विभाग में 1,744 पद हैं। ये सदन के दस्तावेज हैं। मैं तो उस समय था नहीं जब चार-शीट की बात चल रही थी कि हमारे पास तो सब कुछ है। मैं मानता हूं कि सरकार के पास सब कुछ होगा लेकिन यह भी सोचकर चलना चाहिए कि सामने वाले के पास भी बहुत कुछ हो सकता है। जब वह बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा तब ये सारी चीजें निकलकर जनता के सामने आएंगी।

आज प्रदेश के अंदर परिस्थिति यह हो गई है कि युवा ऐसी मानसिक स्थिति से गुजर रहा है, उसे लगता है कि किसी भी प्रकार की नौकरी मिल रही है तो मैं ले लेता हूं।

अब ये जो जॉब ट्रेनी हैं उसमें चाहे स्टाफ नर्स की भर्ती हो रही हो, जिसमें पांच वर्षों के लिए भर्ती की जा रही है तो क्या पांच वर्षों के बाद लोग बीमार होना बंद हो जाएंगे? यदि शिक्षा विभाग में भर्ती की जा रही है तो क्या पांच वर्षों के बाद लोग पढ़ना बंद कर देंगे?

मेरा मानना है कि जो रेगुलर पोस्ट्स हैं, सरकार को इनके बारे में कम-से-कम गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि एक साथ सारी पोस्टें भर दें लेकिन जब ये बाकी चीजें कर रहे हैं तो उसके साथ-साथ इन चीजों को भी ध्यान में रखें ताकि हमारा यह पूरा गवर्नेंस सिस्टम कोलैप्स न हो जाए। इसमें जवाबदेही तो उस कर्मचारी की होगी जो आपका रेगुलर एम्प्लॉयी है। जिसे आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर लाए हैं या ट्रेनी के रूप में लाएंगे अथवा किसी अन्य माध्यम से लाए हैं उसकी क्या जवाबदेही होगी? उसकी तो एक निर्धारित अवधि की जवाबदेही होगी।

सभापति महोदय, ये सरकारें किसी एक कार्यकाल के लिए नहीं होती हैं। सरकारें आती रहेंगी और जाती रहेंगी। वे किसी भी दल की हों लेकिन प्रदेश में लगातार सरकारें चलती रहेंगी। इसलिए हम ऐसी प्रथा और ऐसा सिस्टम छोड़कर न जाएं जिससे बाद में यह समस्या पैदा हो कि आगे सरकारें किस प्रकार चलाएं?

31.08.2026/1720/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

सभापति महोदय, मेरा प्रश्न था जिसमें मैंने प्रश्न संख्या 4568 के अंतर्गत पूछा था कि गत दो वर्षों में राज्य चयन आयोग द्वारा कितने पद अस्थायी आधार पर भरे गए और कितने पदों के लिए विभिन्न विभागों ने राज्य चयन आयोग को लिखा?

इसमें जो सूचना निकलकर आई है वह यह है कि एंगेजमेंट बेसिस पॉलिसी के अंतर्गत पांच वर्ष की अवधि के लिए रखा जाएगा। मुझे आज ही इस नई पॉलिसी के बारे में पता चला है। आज मैंने इस उत्तर में पढ़ा है कि इस पॉलिसी के अंतर्गत निश्चित अवधि के लिए चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को नियमितीकरण या किसी भी स्वीकृत पद पर नियुक्ति का दावा करने का अधिकार नहीं होगा। इसका मतलब ये रेगुलर नहीं होंगे और इसमें बहुत बड़ा आंकड़ा है। इस आंकड़े में सहायक स्टाफ नर्स, अंग्रेजी, गणित शिक्षक तथा शिक्षा के कई अन्य पद हैं। इसके 'ख भाग' में पूछा गया था कि किन-किन विभागों ने

राज्य चयन आयोग को लिखा था। भर्ती निदेशालय, राज्य चयन आयोग व लोकसेवा आयोग में रिक्त पदों को अस्थायी आधार पर एंगेजमेंट बेसिस पॉलिसी के अंतर्गत भरने हेतु विभिन्न विभागों से कोई मांग पत्र प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि सरकार ने अपने स्तर पर निर्णय लिया। राज्य चयन आयोग के पास अस्थायी आधार पर एंगेजमेंट बेसिस पॉलिसी के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के चार पदों को भरने हेतु मांग-पत्र गया है यानी सिर्फ एक विभाग से मांग पत्र भेजा है।

इसके अलावा यह जो सारी नीति है और जिस तरह से निर्णय हुए हैं, वे एकदम से हो गए। इसके ऊपर मैं समझता हूं कि जिस तरह से प्रदेश के युवा आज कितनी बार आवेदन करते हैं और एक पद के लिए हजारों-हजारों आवेदन आते हैं, उसमें कितने कागज लगते हैं और कितना उनका पैसा लग रहा है इन चीजों पर भी गंभीरता से विचार करने का समय है।

सभापति महोदय, यहां पर कई बातें

एन0एस0 द्वारा ....जारी

31-8-2026/1725/NS-AS/1

श्री सुधीर शर्मा ------जारी

हुई हैं। मैं उनके ज्यादा संदर्भ में नहीं जाना चाहता लेकिन फिर भी जिस प्रकार से आउटसोर्स माफिया इस प्रदेश के अंदर काम कर रहा है, उसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। यहां अभी श्री भवानी सिंह पठानिया जी जी ने केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्रालय का मुद्दा उठाया था और उस पर भी एक एस0आई0टी0 बैठनी चाहिए कि कितना पैसा सरकार से जाता है और कितना आउटसोर्स के ठेकेदार के पास रह जाता है? जैसा माननीय रणधीर शर्मा जी ने कहा कि ये सारे-के-सारे मित्र मंडली हैं और ऐसा लगा कि शायद इनको कभी मौका नहीं मिला लेकिन इस बार मौका मिला है तो सब कुछ कर लें। एक शेर जो मैंने उप-मुख्य मंत्री जी से सीखा हैः-

इधर तुम रहोगे न साथी तुम्हारे,
जब डूबेगी कश्ती तो डूबेंगे सारे।

तो यह परिस्थिति जो है, यह जल्दी आने वाली है। जहां तक व्यक्तिगत बात है, वह भी सदन के अंदर, सदन के नेता ने कहा कि भाई, ये तो भारतीय जनता पार्टी की चार्ज शीट के ऊपर मैंने सुधीर शर्मा के ऊपर ही किया है। मैं यहां कोई अपने व्यक्तिगत मुद्दे उठाने के लिए नहीं आता हूं। मुझे जनता ने चुनकर भेजा है और इसलिए चुनकर भेजा है कि मैं जनता की आवाज उठाऊं लेकिन नाम ले दिया मैंने तो नहीं कहा था। अब जब नाम ले दिया तो सभापति महोदय, यहां परसों एक प्रश्न आया और जवाब उप-मुख्य मंत्री जी को देना था। प्रश्न था कि एक भूमि जो 70 रुपये से 770 रुपये में खरीदी गई और 18 लाख रुपये में ली गई जिसे जल शक्ति विभाग ने खरीदा तो सदन के अंदर संशय पैदा हुआ। उस समय कहा गया कि यह तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर गई। लेकिन जो अधिसूचना है वह तो दिनांक 30-12-2022 की है तो उस समय मुख्य मंत्री कौन थे? सवाल उस बात का भी नहीं है। सवाल यह है कि जब भूमि का सर्कल रेट तय होता है तो वह डिप्टी कमिश्नर तय करते हैं लेकिन जब यह तय हुआ तो कहा गया कि नेगोशिएशन कमेटी ने कर दिया। एक पार्ट यह है कि उस पूरी भूमि का सर्कल रेट 18 लाख रुपये हो गया और बाकी का सर्कल रेट उतना ही है, विषय यह है। मैं यह बताना चाहता था। इसका दस्तावेज मेरे पास है और

31-8-2026/1725/NS-AS/2

सभापति महोदय, मैं इसको सभा पटल पर रख दूंगा जब अपने विचार समाप्त करूंगा। जो चार्ज शीट की बात श्री रणधीर जी ने कही तो जो उस समय की भारतीय जनता पार्टी की चार्ज शीट है उसमें मेरे ऊपर जो आरोप हैं, मैं चाहता हूं कि उसको सार्वजनिक कर दें और उसके ऊपर जो जांच है उसको भी सार्वजनिक कर दें। तब मैं मानूंगा कि मुख्य मंत्री जी पारदर्शिता से काम करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, जहां तक रोजगार का प्रश्न है तो आज प्रदेश का युवा इस सरकार से सारी उम्मीद छोड़ चुका है। उनको कोई उम्मीद नहीं है। इस प्रदेश से युवाओं

का जितना बड़ा पलायन हो रहा है तो आप देखेंगे कि इस प्रदेश का सोशल स्ट्रक्चर छोटे-बड़े शहरों के अंदर बिगड़ रहा है। वह इसलिए बिगड़ रहा है क्योंकि घरों में बुजुर्ग रह गए हैं। नौजवान प्रदेश से पलायन करके दूसरी जगह जाकर रोजगार की तलाश कर रहे हैं और वे देख रहे हैं कि इससे अच्छा ऑप्शन हमें कहां मिल सकता है? धर्मशाला में जो आई0टी0 पार्क बन रहा था और आज तक उसका उद्घाटन करने का समय नहीं मिला है। उसका एक ही भाग अभी तक बनकर तैयार हुआ है। उसमें आधी भूमि धर्मशाला की और आधी भूमि कांगड़ा की है। यहां पर श्री पवन कुमार काजल जी बैठे हैं। उस समय हम दोनों ने मिलकर उसको केंद्र से स्वीकृत करवाया था। केंद्र से पैसा आया लेकिन अब जब उसका कार्य पूरा नहीं हो रहा है तो जो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना था वह नहीं मिल पा रहा है। नौजवान घर के पास नौकरी कर सकता था जो आज गुड़गांव, हैदराबाद या अन्य जगहों पर जाकर नौकरी की तलाश कर रहा है। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जो आपके पास साधन हैं जहां आप कर सकते हैं वहां तो आप कर ही नहीं रहे हैं लेकिन जहां मित्रों को लाभ देना है वह लाभ देने के लिए आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से उनको पिछले दरवाजे से पैसा दिया जा रहा है। सभापति महोदय, इन चीजों को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि आप सबने देखा होगा कि युवाओं ने बहुत जगहों पर बड़े-बड़े बदलाव लाए हैं और हमें उनके साथ कम-से-कम स्थिति स्पष्ट रखनी चाहिए। आज चाहे आर0टी0आई0 है या अन्य माध्यम हैं तो सभी के पास हर तरह की जानकारी रहती है। हमारे यहां सदन के अंदर कई बार ऐसा हुआ

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

31.08.2026/1730/RKS/DC-1

श्री सुधीर शर्मा... जारी

है कि प्रश्नों का उत्तर नहीं आता है लेकिन जो सदस्य हैं वे आर0टी0आई0 लेकर आ जाते हैं। यह परिस्थिति इस सदन की गरिमा के लिए उचित नहीं है। कम-से-कम जो प्रश्न यहां लगते हैं यदि उनके समय पर रिप्लाई आ जाएं तो विधायक को लगता है कि मैं अपनी बात

सदन में रख पाया हूं। जो हर चीज को डिले करने, हर चीज से भागने और दूसरे पर थोपने का जो प्रयास हो रहा है उससे पता चलता है कि वर्तमान सरकार कितनी गंभीर है। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि प्रदेश का युवा सरकार द्वारा बार-बार नियम बदले जाने और बार-बार नई नोटिफिकेशन जारी करने के लिए आने वाले समय में माफ नहीं करेगा। अंत में मैं एक शेर सुनाते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। क्योंकि यहां बहुत सारी बातें बाहर भी कही गई हैं। हम बाहर की बातों का जवाब बाहर ही देंगे। शेर हैः-

"जहन में मंजिल बैठी है,
दुश्मन जेब से निकाले हैं हमने,
और हम जहर से नहीं डरते
क्योंकि सांप बहुत पाले हैं हमने।"

सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

31.08.2026/1730/RKS/DC-2

सभापति : माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री : सभापति महोदय, विपक्ष की ओर से 5 सदस्य बोलने वाले हैं। अगर आप विपक्ष की ओर से भी एक-एक करके सदस्यों को बोलने के लिए आमंत्रित करें तो अच्छा रहेगा क्योंकि हमारी ओर से जारी लिस्ट में भी 13 माननीय सदस्य चर्चा में भाग लेंगे।

सभापति : माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी विपक्ष की ओर से जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं वे सभी मूवर्स हैं और मूवर्स के बाद उनकी दूसरी लिस्ट अभी आई नहीं है। इसलिए अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी भाग लेंगे।

31.08.2026/1730/RKS/DC-3

श्री राकेश जम्वाल : सभापति महोदय, नियम-130 के अंतर्गत जो यह प्रदेश के युवाओं से जुड़ा हुआ रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण विषय लाया गया है, इस पर आपने मुझे बोलने

का समय दिया, आपका धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में विधान सभा चुनावों से पहले सत्ताधारी दल कांग्रेस पार्टी ने वोट की राजनीति के चलते अपनी दस गारंटियां दी थीं उनमें प्रमुख गारंटी पांच वर्षों में पांच लाख सरकारी नौकरियां और एक वर्ष में एक लाख 58 साल वाली पक्की नौकरी देने की बात कही गई थी। माननीय उप-मुख्य मंत्री ने भी अनेक जनसभाओं में यह बात कही थी। हमने भी उन्हें अनेक बार सुना और बड़े आक्रामक तरीके से प्रदेश के युवाओं को यह संदेश दिया गया था। शायद उस समय ऐसी उम्मीद थी कि आप प्रदेश का नेतृत्व करेंगे लेकिन यह तो आपकी पार्टी का फैसला है। प्रदेश के युवाओं को लगा था कि हिमाचल के इतिहास में पहली ऐसी सरकार आने वाली है जो युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएगी। डॉ0 वाई0 एस0 परमार, राम लाल ठाकुर, आदरणीय शांता कुमार, आदरणीय प्रोफैसर प्रेम कुमार धूमल और आदरणीय जय राम ठाकुर जी तक जितने भी मुख्य मंत्री रहे हैं, उनके कार्यकाल के बाद इस बार प्रदेश के सभी युवाओं को यह उम्मीद थी कि हिमाचल के इतिहास में ऐसी सरकार और ऐसा मुख्य मंत्री आएगा जिसके नेतृत्व में पांच लाख नौकरियां मिलेंगी और कोई बेरोजगार नहीं बचेगा। आदरणीय मुकेश जी और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी यह घोषण की थी। हमने सदन के अंदर मुख्य मंत्री जी से पूछा कि आपने एक वर्ष में एक लाख सरकारी नौकरियां देने का वायदा किया था लेकिन एक वर्ष बीत गया, दो वर्ष बीत गए लेकिन आपने युवाओं को कोई सरकारी नौकरी नहीं दी। इसी सदन के अंदर मुख्य मंत्री जी ने यह कहकर मना कर दिया कि हमने ऐसी कोई गारंटी नहीं दी थी कि पांच वर्ष में 5 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी। यह बात सदन के रिकॉर्ड में है। कांग्रेस पार्टी के जिस घोषणा पत्र में दस गारंटियों का जिक्र था हमने उसे भी सदन के सामने रखा तथा अध्यक्ष महोदय ने उसे पढ़कर भी सुनाया। लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश के मुख्य मंत्री जी यह मानने को तैयार नहीं हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसी कोई घोषणा की थी।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

31.08.2026/1735/बी.एस./ डी.सी.-1

श्री राकेश जम्वाल जारी...

सभापति महोदय, प्रदेश का युवा जानना चाहता है कि चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी जो घोषणाएं करती है वे मात्र चुनाव खत्म होने तक होती हैं या उसके बाद भी कहीं पर इम्प्लीमैंट होती हैं?

लेकिन मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि प्रदेश के युवाओं के साथ ऐसा धोखा न करें और ऐसी झूठी घोषणा न करें। सरकारें आती रहेंगी और जाती रहेंगी लेकिन प्रदेश के युवाओं को अगर हम ठगेंगे तो उसके गंभीर परिणाम हमें भोगने पड़ेंगे।

सत्ता परिवर्तन हो गया और दस गारंटियों में रोजगार प्रमुख गारंटी थी क्योंकि आज हर घर से पढ़ा-लिखा बेरोजगार हर घर में है तथा हर परिवार में है। हर परिवार को लगा कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हमारे बेटे को और हमारी बेटी को नौकरी मिलेगी लेकिन हस्र क्या हुआ?

सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद अभी नौकरियां देना शुरू नहीं की थीं लेकिन पूर्व की आदरणीय जय राम जी की भाजपा सरकार ने जिन लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए थे और किसी भी क्षेत्र में आउटसोर्स पर जो लोग तीन-चार वर्ष से अपनी सेवाएं उस संस्थान में और उस विभाग में दे रहे थे उन सब लोगों को धीरे-धीरे निकालने का काम अगर किसी ने किया तो हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने किया।

जिन्होंने एक वर्ष में एक लाख नौकरी का वायदा किया था उन्हीं नौजवानों को नौकरी से निकालने का सिलसिला शुरू हो गया। कारण यह था कि इनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौकरी मिली है इसलिए इनको निकाला जा रहा है। अनेकों बार इस सदन में हमने चर्चा की और हमने प्रश्न किया। इस बार भी प्रश्न था। मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया कि अगर आपके पास कोई नाम होगा तो बताइए उनको नौकरी दे देंगे।

कोविड जैसी महामारी में जिन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर नौकरी की और लोगों की मदद की उन लोगों को भी नौकरियों से निकाल दिया गया। कहा गया कि ये तो मात्र कोविड तक रखे थे। अब कोविड समाप्त हो गया है इसलिए अब

31.08.2026/1735/बी.एस./ डी.सी.-2

हमने निकाल दिया। लेकिन उसके बाद फिर उन्हीं नौकरियों पर जो पोस्टें थीं उन पोस्टों को आउटसोर्स किया गया और फिर उनमें अपने चहेतों को नौकरी देने का काम किया गया।

मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा कभी नहीं हुआ। सरकारें आती रहेंगी और सरकारें बदलती रहेंगी लेकिन जिन नौजवानों ने और हमारे जिन नौजवान भाई-बहनों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसमें काम किया था उन लोगों को भी सरकार ने नहीं बख्शा।

सभापति महोदय, रोजगार की बात को लेकर बहुत-सी बातों का जिक्र आदरणीय श्री रणधीर शर्मा जी और आदरणीय श्री सुधीर शर्मा जी ने यहां बड़े विस्तृत रूप से किया। लेकिन नौकरी देना तो दूर की बात है हमारी वर्तमान कांग्रेस सरकार कह रही है कि हम भांग की खेती उगाएंगे और उससे भी नौजवानों को रोजगार मिलेगा। आप कल्पना कीजिए कि हिमाचल जैसा प्रदेश देवभूमि है। यहां पर किस प्रकार से नशा बढ़ रहा है और किस प्रकार से ड्रग्ज आ रही हैं। हमारे नौजवान जिनकी आए दिन मृत्यु हो रही है और परिवारों के परिवार उजड़ गए हैं बच्चों के माता-पिता चिंतित हैं।

हमें जहां उस ड्रग्ज को रोकना चाहिए था वहां ड्रग्ज को रोकने के बजाय हम भांग की खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके द्वारा हम युवाओं को रोजगार के अवसर देंगे। यह हिमाचल की सरकार का बड़ा शर्मनाक निर्णय है।

यहां तक भी काम नहीं चला, भांग की खेती तक भी बात नहीं रुकी और सरकार ने निर्णय ले लिया कि दीपावली के दिन हम हिमाचल में लॉटरी शुरू करेंगे और लॉटरी से भी युवाओं को रोजगार मिलेगा। सभापति महोदय, यह किस प्रकार की सोच के साथ हम काम कर रहे हैं?

हिमाचल में रोजगार नहीं मिला, ड्रग्ज दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है इस नशे का कारोबार बढ़ रहा है और हम इन सारी चीजों को रोकने के बजाय आगे बढ़ रहे हैं। बजाए इसके कि हिमाचल में हम अपने युवाओं को रोजगार के अवसर दें हम एक और

31.08.2026/1735/बी.एस./ डी.सी.-3

बीमारी लगाने जा रहे हैं। वह बीमारी होगी लॉटरी। पहले ही ड्रग्ज के कारण और नशे के कारण घर तबाह हो गए हैं। उसकी चिंता नहीं है लेकिन हमें चिंता है कि मंत्री जी का भी बयान आया कि इससे हमें रेवेन्यू आएगा। हमें रेवेन्यू की चिंता है लेकिन प्रदेश के युवाओं के भविष्य की चिंता नहीं है। यह बड़े दुःख की बात है अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-ही-साथ हम पढ़े-लिखे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि हम लगभग 150 के करीब स्कूलों को अब सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से अफिलिएट करेंगे।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

31.08.2026/1740/DT/HK/1

श्री राकेश जम्वाल जारी...

वहां पर टीचर और लैक्चरर रखने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चयन आयोग ने एग्जाम कंडक्ट किया है और उसके माध्यम से भर्तियां की गई हैं। लेकिन यह भी कहा गया कि ये मात्र पांच वर्ष के लिए ही चयनित होंगे और इनको फिक्स पे के रूप में 30,000 रुपये मिलेंगे। पांच वर्ष के बाद वे नौजवान कहां जाएंगे जो प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सलैक्ट होकर नौकरी प्राप्त कर रहे हैं? आपने कहा कि यह नौकरी मात्र पांच वर्ष की होगी और सरकार से जब प्रश्न पूछते हैं तो कहा जा रहा है कि पांच वर्ष के बाद फिर से फैसला करेंगे। आज अगर फैसला हो जाता कि चयन आयोग से या पब्लिक सर्विस कमीशन से जो भर्तियां होती हैं वे कभी भी अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी भर्ती होती हैं। आप उनका कांट्रैक्ट पीरियड रख सकते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने हिमाचल प्रदेश के

नौजवानों के भविष्य के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ किया है उसके कारण आज हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी की दर देश की बेरोजगारी की दर से भी बहुत ज्यादा आगे है।

युवा आज ये सारे प्रश्न हमसे भी पूछता है। जब भी विधान सभा का सत्र चलता है तो नौजवानों के मैसेज आते हैं। करुणामूलक आधार पर जिनको नौकरियां मिलनी हैं उनके संदेश भी आते हैं, लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ बिल्कुल नहीं है। सरकार चिंतित है तो भांग की खेती के लिए और लॉटरी के लिए। इसलिए माननीय सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में स्पष्ट तौर पर कहें क्योंकि यह मामला बहुत सेंसिटिव और गंभीर है। कल सत्ता परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। हम कभी भी इस प्रकार की कोई झूठी घोषणा नहीं कर सकते। हम कभी युवाओं के प्रति इस प्रकार का भाव नहीं रख सकते कि उनको ठगें और ठगकर उनसे वोट लें, आज यह संभव नहीं है। हिमाचल प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है उसको देखते हुए प्रदेश के मुख्य मंत्री जी और प्रदेश के उप-मुख्य मंत्री जी को सदन के अंदर कह देना चाहिए कि उस समय की परिस्थितियों के मुताबिक हमने घोषणा कर दी थी। हमने अपने घोषणा पत्र में दस गारंटियों का जिक्र कर दिया था कि हम पांच लाख सरकारी नौकरी देंगे, पक्की नौकरी देंगे और 58 वर्ष की नौकरी

31.08.2026/1740/DT/HK/2

देंगे, लेकिन अब यह संभव नहीं है। नहीं तो इनको आने वाले समय में इसके बहुत गंभीर परिणाम झेलने होंगे।

कांग्रेस पार्टी और सरकार को यह समझना चाहिए कि प्रदेश का युवा आज सरकार की ओर देख रहा है। जिस प्रकार से मुख्य मंत्री जी की स्टेटमेंट आती है और इनपके नेता और मंत्री कहते हैं कि अभी तो हमारी सरकार पांच वर्ष की है आप चिंता मत करो हम दस की दस गारंटियां पूरी करेंगे। लेकिन अंतिम वर्ष में क्या आप पांच लाख युवाओं को रोजगार

दे देंगे? बार-बार सदन के अंदर भी प्रश्न किए जाते हैं लेकिन उसमें हमेशा जवाब आता है कि सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं।

माननीय सभापति महोदय हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से नई-नई आउटसोर्स एजेंसियां रजिस्टर्ड हो रही हैं,ईं उनके माध्यम से जिस प्रकार से युवाओं का शोषण हो रहा है, वह ठीक नहीं। अनेकों ऐसे मामले भी ध्यान में आते हैं कि ऐसा आउटसोर्स नौकरियों के लिए भी पैसे मांगने का प्रचलन शुरू हो गया है, लेकिन सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं है।

मैं माननीय सभापति महोदय के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है जिसपर हम चर्चा लेकर आए हैं। सरकार कितनी गंभीर है यह आज सामने आ रहा है क्यों इस सदन में न मुख्य मंत्री जी हैं और न ही अधिकतर मंत्री यहां उपस्थित हैं। यह प्रदेश के युवाओं का प्रश्न है। प्रदेश के युवाओं के रोजगार को लेकर यहां पर चर्चा हो रही है लेकिन सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूं कि प्रदेश के युवाओं में आक्रोश धीरे-धीरे बढ़ रहा है। आप युवाओं को एंगेज करने में नाकामयाब हुए हैं जिसके कारण नशे का प्रचलन बढ़ रहा है और हमारा युवा बिगड़ रहा है। सरकार को आज भी समय रहते यह स्पष्ट करना होगा कि हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते-हम हर परिवार को और हर घर को नौकरी नहीं सकते। यह बात सरकार को इस सदन में स्पष्ट करनी होगी। स्वरोजगार के अवसर हमको किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में पैदा करने होंगे, यह सरकार को देखना होगा क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि सरकारी नौकरी नहीं है। हिमाचल प्रदेश का

31.08.2026/1740/DT/HK/3

पढ़ा-लिखा युवा जानता है कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले यह संभव नहीं है। हिमाचल प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएं। यह प्रदेश की सरकार की और सदन की चिंता होनी चाहिए। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय में हमको औद्योगिक पैकेज मिला था। अनेकों उद्योग नालागढ़-बद्दी में आए जिससे

हिमाचल प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान हुए। लेकिन आज वह इंडस्ट्री भी यहां से पलायन कर रही है। आज यहां से इंडस्ट्री पलायन क्यों कर रही है? इन चार वर्षों में कितनी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो हिमाचल को छोड़कर चली गईं?

श्री एन0जी0द्वारा जारी...

31.08.2026/1745/एच.के.-एन.जी./1

श्री राकेश जम्वाल......... जारी

जिसके कारण रोजगार को लेकर भी यहां पर कई प्रकार के प्रश्न खड़े हुए हैं। जब यहां पर उद्योग नहीं आएंगे, जब हम स्वरोजगार के अवसर प्रदान नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित तौर पर युवाओं के भविष्य के ऊपर जिस प्रकार की तलवार लटकी हुई है, वह चिंता का विषय है।

सभापति महोदय, यह बड़ा गंभीर मुद्दा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार व मुख्य मंत्री जी की ओर से एक स्टेटमेंट आए कि हमने 5 लाख सरकारी नौकरियों का जो वादा किया था, वह वादा हम पूरा नहीं कर पाएंगे। हम प्रयास करेंगे कि जितने सीमित संसाधन प्रदेश के पास हैं तथा जिस प्रकार की हमारी आर्थिक स्थिति है, उसे प्रदेश की जनता के समक्ष रखते हुए युवाओं से माफी मांगनी चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि हम सरकारी नौकरी नहीं दे पाएंगे। हम रोजगार देने की बात कर सकते हैं। स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बात कर सकते हैं। लेकिन आपने तो जिन योजनाओं का जिक्र किया, स्टार्टअप का जिक्र किया, स्टार्टअप के माध्यम से भी 1,477 लोगों की एप्लीकेशन्ज़ आती हैं, उसमें से मात्र 365 लोगों को ही इस स्टार्टअप योजना में मदद दी जाती है। अगर मैं सारे आंकड़ों का जिक्र करना शुरू करूंगा तो बहुत समय लगेगा।

लेकिन सभापति महोदय, इस चर्चा में भाग लेते हुए मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा कि आज भी आप हिमाचल प्रदेश के युवाओं को स्पष्ट कर दें कि हम सरकारी नौकरी नहीं दे पाएंगे। 58 साल की पक्की नौकरी नहीं दे पाएंगे। हम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा मिले, हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री आए और ऐसी सभी संभावनाओं पर काम करते हुए हिमाचल के युवाओं

31.08.2026/1745/एच.के.-एन.जी./2

को रोजगार देने का प्रयास करें और हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को बढ़ावा देकर युवाओं का भविष्य खराब न करें। लॉटरी को लेकर भी मैं इस सदन के माध्यम से सरकार व माननीय मुख्य मंत्री से कहना चाहता हूं कि नौजवानों का भविष्य खराब मत करो। अगर आप लॉटरी शुरू करेंगे तो हमारे युवाओं का भविष्य खराब हो जाएगा। हिमाचल जैसा प्रदेश, जोकि देवभूमि है और कई प्रकार की बातें यहां पर आती हैं कि हिमाचल प्रदेश के लोग लॉटरी के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं।

सभापति महोदय, यह कितना नंबर हो सकता है? कितने लोग ऐसे हो सकते हैं जो हिमाचल प्रदेश से दूसरे प्रदेशों में लॉटरी खरीदने के लिए जा सकते हैं? लेकिन जब आप हिमाचल में ही लॉटरी शुरू कर देंगे और आपका एकमात्र ध्येय यह होगा कि पैसा कैसे आए—चाहे आप सैस लगाकर, पेट्रोल पर, डीजल पर तथा लॉटरी के माध्यम से या भांग की खेती के माध्यम से राजस्व बढ़ाएं—तो हिमाचल सरकार की आय के साधन बढ़ाने के लिए ये सब तरीके ठीक नहीं है। इससे हिमाचल प्रदेश का भविष्य खतरे में आएगा।

सभापति महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

31.08.2026/1745/एच.के.-एन.जी./3

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य, डॉ0 हंस राज भाग लेंगे।

डॉ0 हंस राज : सभापति महोदय, यह एक बड़ा ही ज्वलंत विषय है। इस विषय को हमने इस सत्र के शुरू में नियम-67 के अंतर्गत उठाया था और माननीय अध्यक्ष ने इसको नियम-130 के अंतर्गत चर्चा में लाया। इसमें मैं भी अन्य प्रस्तावकों की तरह एक प्रस्तावक के रूप में आपके सामने कुछ विषय रखूंगा। आपने बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, किसी भी प्रदेश का सामाजिक ढांचा या आर्थिक ढांचा, उसके विभिन्न सामाजिक पहलुओं पर ही आधारित होता है। ऐसा ही जब हम युवाओं के विषय में देखते हैं और उसको रोजगार के साथ जोड़ते हैं, तो कई बार हम पाते हैं कि जो सामाजिक पहलू कई बार उथल-पुथल करते हैं, उनमें युवाओं का बहुत बड़ा रोल रहता है। अभी मैं पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) के अनुसार देख रहा था। हिंदुस्तान में जहां 4.8 प्रतिशत बेरोजगारी है, वहीं हिमाचल प्रदेश में लगभग 7.2 प्रतिशत बेरोजगारी है। मतलब लोगों को, बच्चों को या युवाओं को बेरोजगारी की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। शहरों में इसकी स्थिति थोड़ी ज्यादा भयावह है और गांवों में बहनों व माताओं में यह और अधिक गंभीर है। आपने देखा होगा कि बच्चों ने बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स तथा बहुत सारे डिग्री-डिप्लोमा लिए हुए हैं। कई डिग्री व डिप्लोमा तो ऐसे हैं कि उनमें अतिशयोक्ति की स्थिति हो गई है। अगर आप देखें तो कला अध्यापक की नौकरी कभी बहुत बड़ा रोजगार का साधन

पी0बी0 द्वारा......जारी

31.08.2026/1750/पीबी/वाईके0-1

डॉ0 हंस राज.... जारी

साधन हुआ करता था। एक पी0टी0आई0 का विषय था और बी.एड. कर लेना भी अपने आप में रोजगार की गारंटी हुआ करती थी। जे0बी0टी0 करना भी अपने आप में रोजगार की गारंटी हुआ करती थी। जो नर्सिंग करते थे, चाहे जी0एन0एम0 हो या ए0एन0एम0, ऐसे कई सर्टिफिकेट कोर्सिज, डिप्लोमा कोर्सिज या डिग्रियां थी जो बच्चे लेते थे। अब स्थिति यह है कि एम0बी0बी0एस0 करने वाले बच्चों को भी कई बार वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना पड़ता है। यह बात नहीं है कि हमारे हिमाचल के युवाओं में स्वयं रोजगार जनरेट करने की क्षमता नहीं है। यह बात बिल्कुल नहीं है कि वे रोजगार की तलाश नहीं करते या बाहर जाने की कोशिश नहीं करते हैं। हां, जब हम सरकारी जॉब्स की बात करते हैं तो युवा पाते हैं कि लाइफस्टाइल को सैटल करने का सबसे सरल रास्ता सरकारी जॉब है। अगर कोई संघर्ष नहीं करना चाहता या किसी संघर्ष में नहीं जाना चाहता और अपनी लाइफ को भी वैल सैटल करना चाहता है तो हिमाचल जैसे राज्य में यह उपाय माना गया है कि आप सरकारी जॉब में चले जाएं। फिर आप वहां कुर्सी पर बैठकर काम करें या न करें लेकिन महीने के जब 30-31 दिन होंगे तो आपकी सैलरी आ जाएगी। अब व्यवस्था परिवर्तन के राज में पेंशन की भी व्यवस्था हो ही रही है तो इससे सरकारी जॉब्स की तरफ रुझान और बढ़ता है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में देखें तो हमने बहुत बड़े विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं। मैं कल भी देख रहा था जब हम लोग रोहड़ू की तरफ जा रहे थे तो कई बागवानों ने खुद ही अपना पोटैंशियल इस्तेमाल करके और दुनिया घूम-घूमकर हॉर्टिकल्चर में ऐसे-ऐसे नए आयाम स्थापित किए हैं जो यूनिवर्सिटीज को करने चाहिए थे। जो बात मैं शुरू में कह रहा था कि सिर्फ जॉब लेनी है, जॉब में अच्छी जगह पहुंचना है और उसके बाद कुछ करें या न करें लेकिन सोशल सिक्योरिटी में आपकी बन जाएगी। यह मुझे बेरोजगारी का सबसे बड़ा मानदंड लगता है। मैं कई आंकड़े देख रहा था, जिसमें हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में रोजगार जनरेट करने की हर सरकार ने समय-समय पर कोशिश की है। लेकिन जब युवाओं को विशेषकर इलेक्शन्ज के समय प्रलोभन दिए जाते हैं तो वे बिना कुछ देखे-बगैर ही दे दिए जाते हैं कि इस बार हम इतनी जॉब्स निकालेंगे जबकि हमारे पास उस तरह का सामाजिक-आर्थिक ढांचा ही नहीं है जिससे हम वह रोजगार जनरेट कर सकें।

31.08.2026/1750/पीबी/वाईके0-2

इसीलिए यहां पर हम लोगों पर बहुत बड़ा प्रेशर है कि ऐसी कौन-सी फील्ड हो जहां रोजगार जनरेट किए जा सके। मैं यहां क्रिटिसिज्म के लिए अच्छा भाषण दे सकता हूं कि आपने यह कहा था, आपने वह कहा था, आप ऐसे रोजगार देंगे, वैसे रोजगार देंगे लेकिन अब वह समय चला गया है। अब सरकार के चार साल हो गए हैं। अब आप कितनी गालियां दे देंगे, अब तो हम थोड़ा-सा सुधार की तरफ जा रहे हैं। आगे मान लीजिए जैसे ही जय राम जी सत्ता संभालेंगे तो हम कोशिश यह करें कि शुरू से ही कुछ न कुछ नया तरीका इजाद कर लें जिससे युवा किसी भी भाषण के कारण खुद को ठगा हुआ महसूस न करें। उप-मुख्य मंत्री जी भी मुस्करा रहे हैं कि मैंने भी बड़े भाषण दिए हैं। मैं यह इंगित नहीं करूंगा कि आपने क्या भाषण दिए, न ही किसी और मंत्री के भाषणों की बात करूंगा। इनकी मजबूरियां रहती हैं। चुनाव जब आते हैं तो भाषण देने पड़ते हैं। मैं इस चर्चा में सीरियस नोट में भाग ले रहा हूं और मेरा सिर्फ यह मानना है कि जो लोग स्वयं कुछ करना चाहते हैं, हम उन्हें मोटिवेट नहीं कर पाए हैं। मेरा कहना है कि हम उनके लिए उस प्रकार की अपॉर्च्युनिटी भी उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं। जैसे मैं यहां कई बार चर्चा कर चुका हूं और परसों जब हम हाइड्रोपावर के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे तो उस समय मैं एक रेफरेंस देना भूल गया था कि हमारी डॉक्टरेट का विषय भी इसी से संबंधित था कि सोशल-इकोनॉमिक इम्बैलेंस और इकोलॉजी के प्रभाव से समाज पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है। हमारा अध्ययन इसी विषय पर था कि चंबा के समाज पर इसका किस प्रकार प्रभाव पड़ा है परंतु हम लोग इस विषय पर चर्चा नहीं कर पाए। यहां पर जब मैं बहुत सारी डिटेल देख रहा था तो हमने पाया कि हिमाचल प्रदेश बहुत बड़े जीवित पोटेंशियल में रहता है। यहां पर अगर हम लोग चार सेगमेंट में बहुत अच्छा काम करें तो बेरोजगारी को रोजगार के रूप में नहीं बल्कि रोजगार देने वालों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जब हम अपर शिमला को देखते हैं तो वहां के लोगों ने बागवानी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा कई इंडस्ट्रीज़ और कुछ प्राइवेट उद्यमी भी हुए हैं जिन्होंने खुद संघर्ष करके बहुत सारे युवाओं को रोजगार दिया है। इसी प्रकार हम हिमाचल प्रदेश के युवाओं को मोटिवेट कर सकते हैं।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी

31.08.2026/1755/एच0के0/ए0पी0-01

डॉ हंस राज जारी .....

इसमें सबसे पहला क्षेत्र कृषि और बागवानी का आता है, जिसमें हमने अभी तक कोई ठोस नीति नहीं बनाई है। मैं एक उदाहरण देता हूं। हम लोग आज की डेट में चुराह विधान सभा क्षेत्र में सेब के क्षेत्र में इतना काम नहीं कर सके। इसके अलावा कुछ समय के लिए फ्लोरीकल्चर में भी गए, लेकिन उसमें कोई स्थायी प्रबंधन नहीं था। इसलिए जो किसान थे वे डाइवर्ट हो गए। फिर उनके बच्चों को हायर क्लासेस के लिए बाहर जाना पड़ा। इस तरह हम उसे रोजगार के रूप में नहीं ले सके। इसके बाद हमने देखा कि लोग अपने एफर्ट से मटर की खेती और आलू उत्पादन की तरफ चले गए। जिसमें वे खुद ही कामयाब हो रहे हैं। अब मैं एग्रीकल्चर में कई बार देखता हूं। पिछली बार भी हमने प्रश्न लगाया कि कितने लोग एग्रीकल्चर में पोस्टें संभाले हुए हैं। चंबा में लगभग सारी पोस्टें वैकेंट चली हैं। जैसे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट पूरे चुराह में ही नहीं है। अब उसका न होना भी एक समस्या है। इससे हम किसानों और बागवानों को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए वहां के बेरोजगार युवाओं को फेज वाइज, सेगमेंट वाइज और क्षेत्र वाइज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ताकि जो जिस फील्ड में कौशल रखते हैं, उन्हें उसी तरफ जाना पड़े। जैसे कौशल विकास में हमने देखा कि कई ऐसे संस्थान खुले हैं जो सिर्फ भारत सरकार या हिमाचल सरकार के फंड लेने के चक्कर में फेक क्लासेस चलाते हैं। वे कहते हैं कि हमने इतने बच्चों को बी0सी0ए0 करवा दी, इतने लोगों को टाइपिंग सिखा दी और इतने लोगों को यह कर दिया। लेकिन सीखने के बाद वे बच्चे खपेंगे कहां? इस तरह की व्यवस्था तो हम कर ही नहीं रहे हैं। इसलिए सरकारों को यह सोचना पड़ेगा। जैसे मैं एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की बात कर रहा हूं। आपको क्षेत्र और विषय विशेष को चिह्नित करके देखना पड़ेगा कि यहां एप्पल हो सकता है तो एप्पल की खेती करें या यहां किन्नू या संतरा हो सकता है तो वहां किन्नू व संतरा करें। नए युवाओं को एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटियों के

साथ क्लब करके उसी तरह की ट्रेनिंग हमें खुद देनी चाहिए ताकि भारतवर्ष में बेरोजगारी का जो आंकड़ा है, उसे थोड़ा कम कर सके। नहीं

31.08.2026/1755/एच0के0/ए0पी0-02

तो हर चुनावी भाषण में हमें यह बोलना पड़ेगा कि इस बार हम यह करेंगे। विशेषकर खाद्य सुरक्षा के तहत हमें यह भी सोचना होगा कि फूड प्रोसेसिंग या फूड ग्रेन्स को कैसे संवर्धित किया जा सकता है। इसके माध्यम से भी लोगों को रोजगार के साथ जोड़ा जा सकता है। दूसरा क्षेत्र पर्यटन है, पर्यटन में हमने देखा है कि मौसमी पर्यटन होता है। एक-दो महीने ही आपके यहां टूरिस्ट दिखाई देते हैं, चाहे मॉल पर दिखें, चाहे डलहौज़ी में दिखें या धर्मशाला में दिखें। हम परमानेंट टूरिज्म की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। परमानेंट टूरिज्म की व्यवस्था कैसे होगी? मैं कल डोडरा क्वार में था। हमने देखा कि लोगों ने डोडरा क्वार का बड़ा प्रचार किया हुआ था। चांशल वैली भी हमने घूमी और देखी। पिछली बार नई मंजिल, नई राहें में हमने देखा था कि क्या इन्वेस्टमेंट हुई और उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। वहां लोगों में एक बड़ी जबरदस्त बात मैंने देखी। वे चाहते हैं कि जो रोड उत्तराखंड के साथ कनेक्ट करती है, वह बारह महीने या कम से कम आठ-नौ महीने खुली रहे। अगर वह कनेक्ट हो जाए तो हमारे यहां बारह महीने टूरिज्म हो सकता है और ट्रेडिशनल टूरिज्म भी बढ़ सकता है। हम पांगी, किन्नौर, डोडरा क्वार या इस तरह के क्षेत्रों को देखें या कांगड़ा का बड़ा भंगाल तो वहां सिर्फ फोटो खिंचवाने या सोशल क्लिप बनाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। यहां हमें सोचना पड़ेगा कि हम साहसिक टूरिज्म कर सकते हैं, इको टूरिज्म कर सकते हैं और वेलनेस टूरिज्म भी कर सकते हैं, जैसे योग और इस तरह की क्लासेज शुरू की जा सकती हैं। अकादमिक टूरिज्म में भी धर्मशाला का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। धर्मशाला एक बड़ा हब बन रहा है। पूरे चंबा से हमारे हजारों-हजारों बच्चे धर्मशाला में हैं। ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं आप सेट करते कि गांव का फाइव स्टार जो है, वह हम नादौन में बना दें और फिर उसी तरह का दस-बीस-चालीस करोड़ रुपये वहां लगा दें ताकि दूर-दूर से बच्चे आ रहे हैं तो उन्हें हॉस्टल की व्यवस्थाएं दी जा सकें और वे आने वाले समय के लिए तैयार हो सकें। तीसरा, हम लोग होमस्टे को भी इफेक्टिव तरीके से लागू नहीं कर

पाए हैं। इसमें हमें बच्चों को ट्रेन करके होमस्टे में भेजना पड़ेगा ताकि वे वहीं एनरोल हों और अपने घरों में ही रोजगार प्राप्त कर सकें। हिमाचल प्रदेश में ऐसे कई इलाके हैं, जो वर्जिन डेस्टिनेशंस हैं। वहां सांस्कृतिक टूरिज्म, ट्रेडिशनल टूरिज्म, धार्मिक टूरिज्म यह सभी

श्री ए0टी0 द्वारा जारी ....

31.08.2026/1800/AT/AG/01

डॉ0 हंस राज जारी ...

चीजें शुरू कर सकते हैं। उससे बच्चे एंगेज हो सकते हैं और अगर एक बार मास एंगेज हो गया, तो वह खुद कमाना-खाना शुरू करेगा और सरकारों की लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। यह हो सकता है।

मैं सिर्फ आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक ब्लूप्रिंट दे रहा हूं कि अगर आपके पास एक साल है और आप ऐसा कुछ कर पाएं, तो जरूर करें।

तीसरा, औषधीय पौधे या औषधीय जड़ी-बूटियां हैं। हमारे चुनाव क्षेत्र में हमने देखा है कि धूप, कौड़, पती, सुमाख, और केसर की तरफ भी पिछली बार हमारी सरकार गई थी। हमने इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया, लेकिन इसे प्रभावी रूप से ग्रासरूट तक नहीं ले जा पाए। जैसे बी0बी0जी0 राम0 जी0 योजना में हम अलग-अलग शेल्फ बना रहे हैं, उसमें पंचायत राज विभाग भी क्लब हो सकता है। वह टूरिज्म के साथ-साथ कुछ ऐसी लैंड्स आइडेंटिफाई करें, जैसे डोगडी होती है। आपने देखा होगा, हर गांव की अपनी-अपनी डोगडी होती है। वहां पर ये औषधीय और सुगंधित पौधे तैयार किए जा सकते हैं, जिससे आप बहुत सारी मेडिसिन तैयार कर सकते हैं। दूसरा, उनसे परफ्यूम्स और अलग-अलग चीजें भी तैयार की जा सकती हैं।

जैसे भांग की बात जम्वाल जी ने की, उसका हम दूसरा रेफरेंस ले लें तो जिसके लिए हमने भांग को लीगलाइज करने की बात की है, वह कुछ और है। भांग का पूरा का पूरा प्लांट एक औषधीय पौधा है। मतलब, उसकी क्रीम न निकालकर उसको स्मैक की तरह या

उस दूसरे तरीके से न लें, बल्कि उसके पूरे प्लांट का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके पत्ते इस्तेमाल हो सकते हैं, उसकी छाल इस्तेमाल हो सकती है और यहां तक कि उस प्लांट की राख भी इस्तेमाल हो सकती है। यह हमारी अपनी स्टडी है। हमने बाहर घूम-घूम कर इसका अध्ययन किया है।

31.08.2026/1800/AT/AG/02

यह लीगलाइज हुई वह अच्छी बात है। ...(व्यवधन) नहीं-नहीं, मानेंगे, सब मानेंगे, क्योंकि हमारे यहां हर साल 200 से 400 बच्चे जेल चले जाते हैं। तीसा में तो यह भांग बहुत बड़ा अभिशाप है। हम समझाते भी रहते हैं लेकिन लोग समझ नहीं पाते कि तुम पांच-सात हजार रुपये के लिए भांग की ट्रैफिकिंग करते हो और उसमें फंस जाते हो। जो बड़े धना सेठ हैं, रोहित भाई जैसे...(व्यवधान) नहीं-नहीं, वो तो अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। वो तो अपनी जगह समझाते रहते हैं कि ऐसा न करो। ऐसे कई लोग हैं, जो इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं करते और युवा इसमें फंस जाते हैं।

तीसरा-चौथा सेगमेंट में हरित रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। जिसमें हमने कहा कि जल प्रबंधन को भी अगर सही तरीके से किया जाए, तो उससे भी रोजगार पैदा हो सकता है। आपने देखा होगा कि हॉर्टिकल्चर में ड्रिप की बहुत जरूरत पड़ती है।

दूसरा हम वनों को बचा नहीं रहे हैं। वनों को बचाना चाहिए और अगर हम वनों को बचाएंगे तो इकोलॉजी में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं, जो आपकी आर्थिकी को मजबूत कर सकते हैं। जैसे मैंने उस दिन क्वेश्चन भी लगाया कि आप हमारा कालाबंन-सतरुंडी का जंगल पूरा साफ कर रहे हो। ...(व्यवधान) वो तो मैं कर ही रहा हूं। भांग की तो पैरवी कर रहा हूं... ...(व्यवधान) करो इसको। यह गलत नहीं है, यह ठीक है। जो ठीक है, वो ठीक है। ...(व्यवधान)ओ हो, भटकाओ मत। ...(व्यवधान) बंदे मेरे अंदर हो रहे हैं। सर, हम तो वही बोल रहे हैं। चुराह में तो यह बड़ी गंभीर समस्या है।

मैं लीगली और लॉजिकली बोल रहा हूं। हम कोई यह थोड़ी बोल रहे हैं कि तुम भांग पियो या उसकी ट्रैफिकिंग करो। हम तो पत्ते और उसकी छाल पर काम करने की बात कर

रहे हैं। उससे कपड़े बनेंगे, उससे औषधियां बनेंगी, उसका अर्क निकलेगा। हम उस पर काम कर रहे हैं।

जैसे आप पंजाब या अलग-अलग स्टेटों में जाओ। ओपियम ने अपनी जगह जो काम करना होता है वह करता है तो वह कैसे इललीगल हुआ? मैं हमेशा सीधे ही बोलता हूं और बोलना भी चाहिए। इसमें कुछ गलत नहीं है? ...(व्यवधान) भटकाओ मत। ...(व्यवधान) हां-हां, और अंग्रेजों ने हमारा बेवकूफी बनाया है सारी जिंदगी। अंग्रेजों ने

31.08.2026/1800/AT/AG/03

देखा कि सिर्फ भांग भी हम पैदा करें। अंग्रेजों ने किया है, तो किया है, इसमें क्या गलत है? उन्होंने हमें दो सौ साल गुलाम रखा। उनको लगा कि मैकाले हमारे गुरुकुलों को खत्म कर सकता है तो उसने खत्म किया है। अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके तहत देश में रिफॉर्म्स हो रहे हैं और होने भी चाहिए। जो रियलिटी है, वो रियलिटी है। ये बेरोजगारी कहां से पैदा हुई? पहले हायरार्की थी, उसमें जो लोग जो काम करते थे उसी में संलिप्त हो जाते थे और लोग ऐसे ही काम करने लगे रहते थे।

अब मैं डिटेल पर जाऊंगा तो पूरी सोशलॉजी यहां से निकल आएगी, जिससे कईयों के हालात खराब हो जाएंगे। उसमें तो मैं वैदिक कुछ परंपराओं से लेकर के अंत तक जाऊंगा। मेरा मानना जो है...(व्यवधान) सर, ये खामखां मुझे डिस्टर्ब करते हैं। हम लोग इसमें सोलर ऊर्जा को भी ले सकते हैं। सोलर ऊर्जा में भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है और अगर आप अपनी

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी.....

31.08.2026/1805/av/ag/1

डॉ0 हंस राज-------जारी

घरों की छतों पर, जैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। मण्डी और अन्य शहरों में हमने देखा है कि लोगों ने अपने घरों की छतों पर ही सोलर पैनल लगाए हैं और जिसकी जितनी बड़ी

छत है उससे उतना बड़ा रोज़गार पैदा हो रहा है। हम इस प्रकार से कर सकते हैं। यहां पर हमारे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी बैठे हैं। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि हम इसमें 'ग्रामीण विकास' को शामिल करके ऐसा कर सकते हैं। ...(व्यवधान) आप आजकल मेरे फॉर्मूले नहीं मानते। आप मान लिया कीजिए, इससे आप बहुत आगे निकलेंगे। आप जानते हैं कि बाद में मूर्तियां लगती हैं, मैं आपसे ऐसा चाह रहा था। मैंने ऐसा एक बार राजा वीरभद्र सिंह जी को भी कहा था परंतु वे नाराज़ हो गए थे। लेकिन मैं सच्चाई कहता हूं। अगर हम चार सेगमैंट में काम कर लेंगे; मैंने आपको हाइड्रो, पर्यटन, कृषि और बागवानी के बारे में तो बता दिया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम इसका निचोड़ निकाले, ...(घण्टी) सभापति महोदय, अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे बोलते हुए 17.00 मिनट्स हो चुके हैं। मैं अगर सारा निचोड़ निकालूं तो हिमाचल प्रदेश अद्वितीय प्रतिभाओं से सम्पन्न और एक शिक्षित प्रदेश है। अखण्ड भारत में हमारी पढ़ाई की प्रतिशतता सबसे अच्छी है। इतनी अच्छी पढ़ाई, हुनर और गुणी युवा होने के बावजूद भी अगर हम देश में सबसे ज्यादा रोज़गार सीकिंग की तरफ जा रहे हैं कि हमें रोज़गार दीजिए, तो there is a big failure of policy. इसलिए पॉलिसी में बदलाव करने की आवश्यकता है और वह हम-आप मिलकर कर सकते हैं। वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल में 5 लाख नौकरियां देने की बात कही है और यहां पर हमारी विधायक निधि तक पूरी नहीं मिलती। इस तरह से तो बहुत मश्किल है परंतु फिर भी मैं निवेदन करता हूं कि इसको अंगीकार किया जाए और इस बारे में जब एक पॉलिसी बने तो दोनों पक्षों से 8-10 लोग जो अपने आपको एकेडमिक समझते हैं; वे बैठें और वर्तमान परिप्रेक्ष्य के मद्देनज़र एक अच्छी पॉलिसी बनाएं। प्रदेश का युवा आज सचमुच में अपने आपको ठगा-सा महसूस कर रहा है और वह यह देख रहा है कि हमारी बी0एड0 की डिग्री का कुछ नहीं हुआ। मैं खुद वर्ष 2005-06 का बी0एड0 हूं। अगर मैं एक विधायक नहीं होता तो शायद मैं भी आज एक बेरोज़गार ही होता। इसके अतिरिक्त जो जी0एन0एम0, नर्सिंग,

31.08.2026/1805/av/ag/2

पी0टी0आई0, कला अध्यापक इत्यादि अलग-अलग संस्थाओं से ट्रेनिंग करके बैठे हैं, उनके लिए हमने ऑप्शन्ज ही खत्म कर दी हैं। कुछ तो डाईंग कैडर बना दिए जोकि बहुत ही गलत तरीका शुरू किया गया है। संस्थाओं को डीनोटिफाई करना भी बहुत गलत है, इस तरह से तो भविष्य में सारे अवसर ही खत्म हो जाएंगे। हम स्थाई तौर पर ज्यादा रोज़गार नहीं दे सकते इसलिए हमें अब प्राइवेट सेक्टर, पी0पी0पी0 मोड या लोगों की सहभागिता को साथ में रखते हुए अपने बेरोज़गार युवाओं के लिए काम करना पड़ेगा, मैं ऐसा समझता हूं।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

31.08.2026/1805/av/ag/3

सभापति : अब माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल चर्चा में हिस्सा लेंगे।

श्री जीत राम कटवाल : सभापति महोदय, नियम-130 के अंतर्गत 'युवाओं के लिए रोज़गार सन्दर्भित गारंटी के कार्यान्वयन बारे यह सदन विचार करे'; पर चर्चा हो रही है। इसमें मैं भी अपने आपको शामिल करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

यह मामला वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा दी गईं दस गारंटीज से शुरू होता है। सरकार ने सत्ता में आने से पहले बड़े-बड़े वायदे किए थे कि प्रदेश की प्रत्येक महिला को 1500-1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। प्रदेश में एक लाख नौकरियां प्रति वर्ष दी जाएंगी। सरकार के पांच वर्षों में 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी। इस तरह के फैसले सरकार द्वारा सत्ता में आते ही अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में लिए जाएंगे। सरकार द्वारा इस प्रकार से दूध, बिजली इत्यादि के बारे में बहुत अच्छे-अच्छे व लोक-लुभावने वायदे किए गए थे और कहा गया था कि ये सब-कुछ खटाखट मिलेगा। प्रदेश के युवा को नौकरियां, महिलाओं को 15-15 सौ रुपये इत्यादि सब कुछ खटाखट देने की बात कही गई थी। यह सरकार खटाखट करके बहुत बड़े-बड़े काम करेगी और इस प्रदेश की गवर्नेंस को एक

नया स्वरूप देगी। सरकार के वायदों से तो ऐसा लगता था परंतु जब इन पर क्रियान्वयन शुरू हुआ

टी सी द्वारा जारी

31.08.2026/1810/टी0सी0वी0/ए0एस0-1
श्री जीत राम कटवाल... जारी

हुआ है और आज लगभग पौने चार वर्ष पूरे हो गए हैं तो इसका असली चेहरा और असली तस्वीर हम लोगों के सामने है। इसी चिंता से ग्रसित होकर विपक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को उठाया और नियम-67 में शुरू करने को लेकर काम रोको प्रस्ताव से जोड़ा। कुल मिलाकर सदन की सहमति से इसको नियम-130 में बदला गया और मैं इस पर पांचवें नंबर पर बोल रहा हूं।

इस प्रक्रिया में सबसे पहला काम संस्थानों को बंद करने का हुआ। 11 दिसंबर को सरकार शपथ ग्रहण की, माननीय मुख्य मंत्री व उप-मुख्य मंत्री जी ने शपथ ली और और 12 तारीख को 11.00 बजे अधिसूचना जारी हो गई कि 982 संस्थान बंद किए जाते हैं। इसके ऊपर न कोई विश्लेषण था, न कोई स्टडी थी, न कोई मांग थी, न कोई घोषणा थी और न ही घोषणा पत्र में इसका कोई जिक्र था। सरकार के लिए बड़ी बहादुरी का काम था लेकिन लोग बड़े दुःखी और परेशान हुए। एक-दो महीने बड़ी चर्चा हुई और लोग बहुत दुःखी हुए। इसके बाद अंततः लोग चुप बैठ गए।

इसके साथ ही नौकरियों का जो क्रम था उसकी स्थिति भी जगजाहिर है कि नौकरियां कम मिलीं, मिलीं या नहीं मिलीं। हम इधर से भी कुछ बोलेंगे और वे उधर से भी कुछ बोलेंगे परंतु हरेक इंडिकेटर आज यह दिखता है कि आज प्रदेश पहले से निम्न स्तर पर आ चुका है, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे किसी वादे की बात हो और चाहे इक्नॉमिक स्ट्रेंथ की बात हो। मैं यह अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। मेरी ज्यादातर वर्डिंग्स या मैं जो बोलता हूं वह सरकारी दस्तावेजों के अध्ययन के बाद बोलता हूं और इतना भी नहीं बोलता हूं कि किसी को निजी तौर पर चुभे। मैं वही बात बोलता हूं जो इस प्रदेश के हित में है और इस प्रदेश के हित में हम सब लोग यहां बैठे हैं चाहे इधर हों या

उधर हों। मेरे कहने का मतलब है कि संविधान में रोटी, कपड़ा और मकान का प्रावधान है। संविधान में यह भी लिखा हुआ है कि "The Indian Constitution resolves to provide equality of status and opportunity to all citizens", इस तरह से संविधान में बहुत सारे प्रावधान और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। एक अच्छी गवर्नेंस के लिए

31.08.2026/1810/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

हमें इनसे मार्गदर्शन मिलता है और क्योंकि संविधान लॉ ऑफ लैंड होता है, इसलिए उसका पालन करना या उसके अनुरूप नीतियां बनाना प्रत्येक राजनीतिक दल का कर्तव्य होता है। ऐसी नीतियां बनाई जानी चाहिए जिससे इन अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके।

सैक्शन-38 में कहा गया है कि सोशल ऑर्डर ठीक होना चाहिए और कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। सैक्शन-38 (2) में कहा गया है कि जो इनइक्वलिटीज और विषमताएं हैं वे नहीं होनी चाहिए। सभी को डिग्निटी के साथ चाहे छोटे हों या बड़े हों अपनी क्षमता के अनुसार काम और उसके काम के हिसाब से भुगतान भी होना चाहिए। इसके साथ कन्संट्रेशन ऑफ वैल्थ भी नहीं होनी चाहिए और उसके साथ Right to Work & Public Assistance and Decent Life, वह आर्टिकल-41 में यह लिखा गया है और इससे Just and human life social security रहनी चाहिए। इसमें ऐसे मुद्दे रहते हैं परंतु हमें क्या मिला? जहां तक नौकरियों की बात थी, ओ0पी0एस0 की बात थी तो आपने ओ0पी0एस0 दे दी। यह अच्छी बात है कि ओ0पी0एस0 दे दी। 1,500 रुपये को भी आप इफ्स एंड बट्स यानी किंतु-परंतु में चले गए, ऐसा कहा गया था कि 18 से 59 वर्ष तक सभी को मिलेगा लेकिन उसका कोई नामो-निशान नहीं है।

जहां तक एम्प्लॉयमैंट की बात है

एन0एस0 द्वारा ....जारी

31-8-2026/1815/NS-AS/1

श्री जीत राम कटवाल------जारी

मैं आपको बताता हूं कि आपकी सरकार का रिकॉर्ड बेरोजगारी और रोजगार के बारे में अच्छा नहीं है। इंप्लॉयमैंट रजिस्टर में 5.90 लाख नाम इंप्लॉयमैंट एक्सचेंज में दर्ज हैं। यह देखने वाली बात है और आज आपको भी पता है कि इंप्लॉयमैंट एक्सचेंज का सिस्टम प्रिमिटिव माना जाता है तथा बहुत कम आदमी इसमें नाम दर्ज करवाते हैं। नाम दर्ज कराने के बाद क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर और सरकार की व्यवस्था के अनुसार डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई छोटे-छोटे काम वाले व्यक्ति जैसे स्थानीय फिटर्ज, पंप ऑपरेटर्ज या इलेक्ट्रिशियन्स हैं वे अपना नाम जरूर दर्ज करवाते हैं ताकि उनको समय रहते पता लगे और वे अप्लाई कर सकें। मैंने पहले किसी प्रश्न में भी बेरोजगारी के बारे में थोड़ा-सा रेफरेंस दिया था। मैं वर्ष 2025-26 के इकॉनमिक सर्वे की बात कर रहा हूं जो आपकी सरकार का रिकॉर्ड है। ये आपके डॉक्यूमैंट हैं और इनके आधार पर मैं बोल रहा हूं। स्किल डवलपमैंट अलाउंस के लिए एक करोड़ रुपये का बजट दिया है। आपने एक वर्ष में 1 लाख नौकरियां देने की बात कही थी और उसके लिए एक करोड़ रुपये बजट था। 27064 व्यक्तियों को आपने स्किल डवलपमैंट अलाउंस दिया जो पार्शियल होता है। उसके बाद वर्ष 2018 की जो योजना थी उसमें 94 लोगों को 4 लाख रुपये दिए क्योंकि आप भूल गए हैं। मैं कुछ और नहीं बोलना चाहता हूं। मेरा एक ही संदेश है कि आपने जो बोला था आप उसको एकदम भूल गए। आप किसी और मोड में चले गए ताकि इस घोषणा पत्र और आपके इस बहुत बड़े वायदे की कोई चर्चा ही न हो। आप जो अनइंप्लॉयमैंट अलाउंस देते थे वह भी 3717 व्यक्तियों को दिया गया और यह मैं आंकड़ों से बोल रहा हूं। उसमें भी एक करोड़ रुपये का बजट था। मैंने आपको इंप्लॉयमैंट एक्सचेंज की फिगर्स दे दी हैं। इंप्लॉयमैंट एक्सचेंज के माध्यम से 375 लोगों को सरकारी नौकरी मिली। मैं अभी आपकी जो ओपन मार्केट या जो भी भर्ती डायरेक्ट हि0 प्र0 सर्विस कमीशन या हि0 प्र0 राज्य चयन आयोग, हमीरपुर के माध्यम से होती है, उसके ऊपर भी आऊंगा। आपका 4559 व्यक्तियों को प्राइवेट सैक्टर में जॉब देने का दावा है।

सभापति महोदय, अब मैं अपने जिले की बात करूं तो बिलासपुर जिले में 30 आदमियों को सरकारी और 321 व्यक्तियों को प्राइवेट सैक्टर में कोई छोटी जॉब मिली है।

राजीव गांधी रोजगार स्टार्टअप योजना के बारे में मैंने मुख्य मंत्री जी से भी बात की थी। मैंने कहा था कि इसमें 650 करोड़ या 680 करोड़ रुपये बजट की अपेक्षा रखी

31-8-2026/1815/NS-AS/2

थी और उसमें मात्र 56 व्यक्तियों को स्टार्टअप दिया गया है या फैसिलिटेट किया है। ये सब कुछ उस 1 लाख नौकरियों और खटाखट नौकरियों के दावे के टोटली विपरीत है। मैं यह नहीं बोलता कि आपने कम किया है । मैं यह बोलता हूं कि आप बिल्कुल भूल गए हैं और मेरा आपके ऊपर आरोप है कि आपको भूलना नहीं चाहिए था। अगर प्रयत्न किया होता तो हो सकता कि विपक्ष भी आपकी मदद करता। लेकिन उस दिशा में होते हुए आपने तो संस्थान बंद कर दिए, विपक्ष के विधायकों के लिए स्कीमें बंद कर दीं और यहां तक कि निधि जोकि हमारे पैसे थे उनको भी अपने सरकारी खजाने में वापिस ले लिया।

सभापति महोदय, मैं सबसे बड़ी बात दो-तीन बार पहले भी कह चुका हूं कि जो जिला ट्रेजरी है, वह भी शिमला से ऑपरेट होती है। वैसे तो पैसे नहीं है लेकिन अगर मुझे कभी अपनी कोई छोटी-सी निधि या छोटी-सी स्कीम के लिए पैसे डायवर्ट करने हों तो मैं वहां डिप्टी कमिश्नर को बोलता हूं तो वे कहते हैं कि स्वतः ही ट्रेजरी ऑफिसर को बिल भेज दिया गया है। जब ट्रेजरी ऑफिसर को पूछें कि बिल पास क्यों नहीं हुआ? तब कहा जाता है कि सर, शिमला चला गया है, टोकन नंबर यह है, ऑथैंटिकेशन होगी, यह भी कोई अच्छी बात नहीं है। आपने चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए बहुत ही भयानक परिस्थिति पैदा कर दी है। हम आपके समकक्ष हैं। यह वक्त की बात है कि आपमें से कोई चीफ मिनिस्टर व मंत्री हैं। यहां भी (विपक्ष) वैसे ही बैठे हुए हैं। आने वाले समय में इनमें से कोई मुख्य मंत्री होगा, कोई मंत्री होगा और सरकार में अन्य पदाधिकारी भी होंगे। सरकार को चलाना, यह वक्त की बात है और बारी-बारी चल रहा है तो इसको भी आपको देखना चाहिए। हमें छोटी-छोटी बातों में परेशान होना पड़ा और यहां तक कि छोटे-छोटे फंक्शन्ज में आपके हारे हुए व्यक्ति दनदना के जा रहे हैं। हम चुने हुए विधायक

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

31.08.2026/1820/RKS/DC-1

श्री जीत राम कटवाल..जारी

हैं और हमारी एक गरिमा है। वर्ष 2021 में पूर्व मुख्य मंत्री महोदय ने जो विधायक संस्था को सशक्त करने के लिए पहल की थी, उस विषय पर मैंने भी सदन में अपनी बात रखी थी परंतु आज परिस्थिति पूरी तरह भिन्न है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इन विसंगतियों को दूर किया जाए क्योंकि ये सीधे तौर पर आपके एटीट्यूड को दर्शाती हैं। इन विसंगतियों को करैक्ट करिए ताकि आपकी और सरकार की छवि के संबंध में हम भी जनता के बीच सकारात्मक बात कर सकें। हम कोई दुश्मनी वाली बात नहीं करते हैं, हम भी विकास की बात करते हैं। आज की डेट में जो रोजगार की स्थिति है उसमें 2,80,433 लोग कार्यरत हैं। इसमें कुछ आउटसोर्स कर्मचारी भी हैं। आउटसोर्स इम्प्लाइज के साथ-साथ जो लोग प्राइवेट सैक्टर में कार्यरत हैं उनकी कुल फिगर्स 2,42,580 की है। ये आंकड़े सरकारी रिकार्ड का ही हिस्सा हैं। अब हमारे सामने जो चैलेंजिज हैं उनमें देखने वाली बात यह है कि अभी तक लगभग 30-40 हजार नौकरियां ही दी गई हैं। इसके साथ ही नौकरियों में एट्रिशन की स्थिति भी रहती है और सेवानिवृत्ति भी होती है। कुछ पद समाप्त हुए हैं और कुछ संस्थान बंद भी हुए हैं। नौकरियों के बारे में आपका इनडिफरेंट एटीट्यूड और चुप हो जाना युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा ही नहीं है बल्कि उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण भी बना है। लोगों ने बड़े गर्व और जोश के साथ आपको सहयोग दिया था। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूं कि सभी लोगों को सरकारी नौकरी ही मिले। मैं आपको एक और बात बताता हूं कि एक ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन होती है। हिमाचल प्रदेश एक मैनेजेबल स्टेट है और इसकी पॉपुलेशन भी मैनेजेबल है। मैं आधिकारिक तौर पर यह दावे के साथ कहता हूं कि ऑल इंडिया लेवल पर कोई भी रेशो, कोई भी फिगर ऑल इंडिया एवरेज से कम नहीं होती परंतु हम पिछले तीन वर्षों में नीचे जा रहे हैं। चाहे नौकरियों का मामला हो, प्राइमरी सैक्टर हो, सेकेंडरी सैक्टर हो या टर्शरी सैक्टर हो, हमारे यहां इंडस्ट्री नाम मात्र की है। टूरिज्म हमारे पास एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया था तो उस समय कांगड़ा जिला को टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट घोषित

करने की बात की थी। मैंने भी उस चर्चा में भाग लिया था। मैंने कहा था कि केवल कांगड़ा जिला ही क्यों, हरेक जिले में कुछ-न-कुछ पोटेंशियल है।

31.08.2026/1820/RKS/DC-2

यदि सभी व्यक्तियों और सभी क्षेत्रों के युवाओं का योगदान होगा तो हम स्वतः ही पहले से अच्छा करेंगे। अगर हम इस प्रदेश के लिए सिंसियर एफर्ट के साथ लोगों की रिकॉग्निशन करते हुए उन्हें स्ट्रीमलाइन चैनलाइज करके, उनकी एनर्जी को सही दिशा में ले जाने के लिए उत्तरदायी भाव से काम करें तो यह अच्छा रहेगा लेकिन यह अभी नहीं हो पाया। अब मैं वैकेंसीज के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। मैंने तीन-चार दिन पहले 13 डिपार्टमैंट्स की वैकेंसी के बारे में सदन में बात की थी। इन विभागों में 38 प्रतिशत वैकेंसी थी और बिजली बोर्ड जैसे महकमे में भी 46 प्रतिशत वैकेंसी थी। इन 13 डिपार्टमैंट्स में 1,55,895 की सैंक्शन्ड स्ट्रेंथ थी और इनमें 57,000 पद खाली थे जो आपके इस दावे को और भी खोखला साबित करता है कि आपने युवाओं को रोजगार देने के बारे में कुछ नहीं किया और न ही कुछ सोचा। अगर हम इसे इस तरीके से देखें तो नौकरी को सोशल सिक्योरिटी माना जाता है। चाहे व्यवसाय को गिन लें, चाहे प्राइवेट सैक्टर में रोजगार को गिन लें, हम व्यक्ति के लिए रोजगार को सोशल सिक्योरिटी से जोड़कर देखते हैं। जहां तक सोशल सिक्योरिटी की बात है, जो हमारे काम करने का तरीका है उसमें आज दुनिया बदल रही है। आज विकास के नए मॉडल आ रहे हैं और हम लोगों को भी उन मॉडल्स में अपने आपको शामिल करना चाहिए। टूरिज्म और एग्रीकल्चर में हमारे पास काफी संभावनाएं हैं। एग्रीकल्चर का जी0एस0डी0पी0 में मात्र 13 प्रतिशत कंट्रीब्यूशन रहता है। हिमाचल के बजट में इसका हिस्सा 1.9 प्रतिशत है जबकि भारत का हिस्सा 3-4 प्रतिशत है। हमारा पहाड़ी इलाका है इसलिए यह हिस्सा ज्यादा नहीं आता। हमारे यहां इंडस्ट्री लिमिटिड है लेकिन टूरिज्म एक ऐसा पोटेंशियल था जिसमें अगर हम सब मिलकर सिंसियरली काम करते तो बहुत अच्छा होता।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

31.08.2026/1825/बी.एस./ डी.सी.-1

श्री जीत राम कटवाल जारी...

मैंने भारत सरकार को फॉरेस्ट की हिमालयन स्टेट्स के लिए फॉरेस्ट प्लांटेशन का एक मॉडल दिया था। मैंने इस सदन में इसे ले किया हुआ है। वह हिमाचल,नागालैंड, त्रिपुरा, असम, मेघालय मणिपुर, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर सभी राज्यों में लागू हो रहा है और यहां भी लागू हुआ लेकिन अभी इस सरकार ने मुझे इस बारे में पूछा तक नहीं है।

मुझे इस बारे में भारत सरकार की चिट्ठी आई है कि यह आपका मॉडल है और हमने ठीक पाया और इसे इन-इन हिमालयन स्टेट्स को भेजा है। उससे लैंड इरोजन भी रुकता और लोगों की विपत्तियां भी कम होती। आपने कभी इस बारे में बात तक नहीं की। इस बारे में मुख्य सचिव को पत्र आया है और माननीय अमित शाह जी के दफ्तर से तथा माननीय भूपेंद्र यादव, वन एवं पर्यावरण मंत्री महोदय के कार्यालय से यह पत्र आए हैं।

आपको इस संबंध में अवश्य बात कर लेनी चाहिए थी। हमने इसका पैसा नहीं मांगना था, न ही तनख्वाह लेनी थी और न ही कोई कंसल्टेंसी लेनी थी। यह मेरी और आपकी स्टेट है। I could have contributed some parameters.

इसी तरीके से मैंने टूरिज्म का प्रोजेक्ट भी भारत सरकार को भेजा है। मैंने गोबिंद सागर में वाटर स्पोर्ट्स और ट्रेकिंग तथा होमस्टे का एक नया मॉडल तैयार करके दिया है। वह भी आपको आया हुआ परंतु सरकार बात तक नहीं करती है। मैं कहता हूं कि बात कर लेनी चाहिए।

हम तो मुफ्त में आपको इस प्रदेश के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और एक विधायक के नाते जो सेवाएं दे सकते हैं उन्हें देने के लिए तैयार हैं। हम सदन में भी तो

सारी स्टेट की बात करते हैं और पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं। I could have contributed परंतु ऐसा नहीं हुआ।

इन चीजों को देखना चाहिए। ये बारिकियां हैं और ये एक आदमी की नहीं बल्कि सभी के योगदान की बात थी।

31.08.2026/1825/बी.एस./ डी.सी.-2

मैं आपको district specific issues and challenges की बात करना चाहता हूं। सभी विधायक मेरे भाई हैं उनको मैं थोड़ा-सा इंडिकेटर्स बताऊंगा कि किस-किस डिस्ट्रिक्ट में क्या स्थिति है।

कांगड़ा, मण्डी, बिलासपुर, हमीरपुर और चंबा की जो स्टडी बोलती है और जो इसका सर्वे है उसमें कहा गया है कि these districts are high job seekers. यहां ज्यादा जॉब की जरूरत है। इनको ध्यान में रख कर ही टूरिज्म की पॉलिसी बनानी चाहिए थी। सरकार को टूरिज्म के बारे में इनको देखना चाहिए था because placements especially government sector remain comparatively low in these areas.

इन जिलों में पढ़े-लिखे आदमी हैं। जिला कांगड़ा, मण्डी, बिलासपुर, हमीरपुर और चम्बा में बहुत ज्यादा स्कोप है। अगर इनको टूरिज्म की कोई एक्टिविटी और एलाइड एक्टिविटीज करते तो इनका भी योगदान अवश्य लेना चाहिए था।। वे हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं और हमारा परिवार हैं वे इसके लिए बहुत अच्छा योगदान देते और उसके बाद मैं बताऊं कि industrial employment concentration but limited absorption capacity सोलन, ऊना और सिरमौर ये तीन डिस्ट्रिक्ट हैं जहां छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज हैं।

यहां उप-मुख्य मंत्री महोदय बैठे हैं। ये पहले इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे हैं और ऊना जिला से आते हैं। मैं भी कभी वहां पर जिलाधीश रहा हूं। उस जिले में भी इनको ज्यादा अच्छा अनुभव है और सर्वे का जो मैं डॉक्यूमैंट पढ़ रहा हूं उसमें इंडस्ट्रियल हब्स पर इसका लिमिटेड एब्जॉर्प्शन है।

इनके पास बड़ी सिफारिशें आती होंगी कि ये कर दो और वो कर दो परंतु नहीं हो पाता। यहां एक और सिस्टम है कि 100 प्रतिशत एजुकेशन मानी जाती है और बहुत स्लिक पॉपुलेशन है जिसमें 80-90 साल वाले लोग आते हैं जो मैटर नहीं करते। Otherwise we have declared ourselves a Literate State.

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री जीत राम कटवाल : सभापति महोदय, कृपया मुझे थाड़ा और समय चाहिए मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कह रहा हूं।

31.08.2026/1825/बी.एस./ डी.सी.-3

इसलिए इंडस्ट्री में कोई ज्यादा स्कोप नहीं बनता। हमें इन सेगमेंट्स में जिलावार सोचना चाहिए।

कुल्लू, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में लोकल कारोबार है। वहां या तो हॉर्टिकल्चर है या कोई छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज हैं। वहां शॉल और पट्टी का कार्य है और इनकी heavy reliance on Tourism and Seasonal Economic Activities है। एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोड्यूस के साथ-साथ छोटे-छोटे शॉल पट्टी और चुन्नी बनाने के काम हैं। उनमें भी आज के इकनॉमिक इंडेक्स के अनुसार सस्टेनेबिलिटी ज्यादातर नहीं बनती।

उसके बाद लाहौल-स्पीति और किन्नौर को देखें तो रिमोट होने की वजह से वहां छोटे-छोटे लिमिटेड काम हैं। वहां भी स्वरोजगार के अलावा बहुत अधिक विकल्प उपलब्ध नहीं होते। कुल्लू, चम्बा, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों के बारे में जो मैंने पढ़ा तथा समझा है उसके अनुसार लोग सेल्फ एम्प्लॉयमैंट के सहारे चलते हैं। वहां छोटी-छोटी इलैक्ट्रिसिटी प्रोजैक्ट्स चली हैं। उनसे भी नुकसान होता है और हुआ भी है। परंतु इन्होंने

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

31.08.2026/1830/DT/HK-1

श्री जीत राम कटवाल जारी...

वहां के लोग कुछ-न-कुछ छोटा-मोटा काम करके जैसे होटल, ढाबा, टूरिज्म या अन्य छोटी-छोटी एक्टिविटीज के माध्यम से जीवन-यापन करते हैं। किनौर लाहोल और स्पिती और शिमला में Reliance on Government jobs यानी व्हाइट कॉलर जॉब, नौकरियां कम हैं लेकिन वहां पर भी मेरिट सिस्टम है, इसलिए उसका भी एक प्रेशर रहता है। Conversion into placement remains modest compared to demand, ज़्यादा जॉब सीकर्स हैं और उनको रोजगार नहीं मिल पाता है।

इसके बाद मैं आपको विभिन्न विभागों में वैकेंसीज के बारे में के बारे बताना चाहूंगा। शिक्षा विभाग में ही नौकरी पाने के लिए जो पात्र उम्मीदवार हैं उनकी संख्या ही 65,254 हैं यानी यह वे लोग जो बी0एड0 ट्रेंड हैं और यह रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड हैं। 16028 जे0बी0टी0, डी0एल0एड0 हैं।

Chairman : Please now wind up.

श्री जीत राम कटवाल : सभापति महोदय, कहने का अर्थ है कि प्रदेश में अभी भी इतने टीचर हैं जो बेरोजगार हैं, यह भी एक लायबिलिटी है। वे लोग क्वालीफाइड हैं। सबसे दुखद बात यह है कि जे0बी0टी0 या डी0एल0एड0 का कोर्स भी सरकार ही करवाती है और यह ट्रेनिंग पूरी तरह से सरकार के रेग्युलेशन में ही होती है। लेकिन सरकार उनको जॉब नहीं दे पा रही है। इनमें अभी जो वैकेंसी पोजीशन है उसमें 754 पद बी0एड0 और टी0जी0टी0 के भर रहे हैं और बैच वाइज या कुल मिलाकर स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। इसलिए प्रदेश में एम्प्लॉयमैंट सिनेरियो जो वर्तमान में है उसे अगर हम इस तरीके देखें तो वह नहीं बन पाता। आउटसोर्स में कर्मचारी रखें हैं, उनकी सोशल सिक्योरिटी के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। आउटसोर्स में कई कर्मचारियों को उन्नीस-उन्नीस-बीस-बीस साल हो गए हैं, उनको भी कुछ देना चाहिए। पूर्व में हमारी सरकार समय शायद सितंबर, 2022 की बात है, हमने उन्हें कहा था की उन्हे उनके काम से नहीं निकाला जायेगा और सरकार आउटसोर्स एम्प्लॉयीज के लिए पॉलिसी बनाएंगी। Government in continuity होती है।

आपको भी वह डाक्यूमेंट मिला होगा और आपको भी चाहिए था। इस समय प्रदेश में लगभग 30000 आउटसोर्स

31.08.2026/1830/DT/HK-2

एम्प्लॉयीज हैं। उनके बारे में भी कुछ सोचिए और उनको भी एम्प्लॉयमैंट दें क्योंकि वे भी परिवार को चलाते हैं, उनके छोटे-छोटे परिवार हैं और वेतन के मामले में उनको बहुत बड़ी डैफिशिएन्सीज हैं। जब आउटसोर्स के कर्मचारी हमें फील्ड में मिलते हैं तो मैं देखता हूं कि उनका जीवन आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर दौर में गुजर रहा है। उन्हें नौकरी करते-करते कम-से-कम 18 से 19 साल हो गये हैं लेकिन उन्हें अभी भी 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार रुपये का वेतन मिल रहा है। उन्हें अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा तो इस नौकरी के लिए दे दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में विग्रह हो रहा है। शादी के कुछ साल बाद ही डाइवोर्स हो रहे हैं- जो कि अच्छा संकेत नहीं है। इनके लिए भी आर0एंड0पी0 रूल्ज बनाइए।

सभापति : माननीय सदस्य, कृप्या वाइंड-अप कीजिए।

श्री जीत राम कटवाल : सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा समय और लूंगा। मैं इनकी सिक्योरिटी के संबंध में कुछ बोलना चाहूंगा मुझे बस तीन मिनट दीजिए, यह आपके भी फायदे की बात है क्योंकि आप को भी लोगों के बीच जाना पड़ता है, नहीं तो आउटसोर्स वाले आपको ही कहेंगे कि सदन में हमारे बारे में बात हो रही थी तो आप टोक रहे थे। क्योंकि वह भी देख रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनके लिए आर0एण्ड0पी0 रुल्ज बनाकर इनको इनके एक्सपीरियंस का लाभ देकर इनको भी गवर्नमेंट जॉब दें। जैसे उप-मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि 58 साल वाली पक्की नौकरी मिलेगी। उन्होंने 15 साल तो जीवन के आउटसोर्स में लगा दिए अभी भी उनको 58 साल वाली नौकरी दे दो। उसके लिए हमारा भी सरकार को समर्थन है। आउटसोर्स एम्प्लॉयीज के अतिरिक्त पैरा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्ज हैं, आशा वर्कर्ज हैं, पैरा पंप ऑपरेटर हैं, आर0के0एस0 एम्प्लॉयीज हैं। रोगी कल्याण समिति में जो लोग लगें हैं उनके साथ तो बहुत बड़ा अन्याय शुरू हो गया है। पहले जो तनख्वाह मिलती थी, छुट्टियां काटने के बाद उनकी तनख्वाह कम होगी।

उनमें कोई लैब टैक्निशियन लगा हुआ है या रेडियो रेडियोलॉजिस्ट लगा हुआ है, रेडियोग्राफर लगा हुआ है, तो उनकी तनख्वाह कम होगी। पहले 14 हजार या 15 हजार मिलते थे उनकी चार छुट्टियां काटकर अब उनकी तनख्वाह 11-12 हजार रुपये कर दी। जन आरोग्य समितियां जो बनी हैं वह भी बड़ी नुकसानदायक है उससे भी उन लागों की प्रताड़ना हो रही है, उसको भी देखिए। आशा वर्कर्ज और पैरा पंप ऑपरेटर को सरकार

31.08.2026/1830/DT/HK-3

अटल पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाए और इनका को-कंट्रीब्यूशन दें क्योंकि आउटसोर्स और पैरा पंप आपरेटर्ज ये दोनों लगभग एक लाख। एक लाख के लगभग है, एक लाख का मतलब है एक लाख परिवार और पांच लाख उन परिवारों के सदस्यों की संख्या। अगर हम इसको ठीक तरीके से आंकें तो इनके बारे में भी सोशल सिक्योरिटी और सोशल पेंशन का आश्वासन सुनिश्चित होना चाहिए। इसके लिए भी काम करें और अटल पेंशन स्कीम में जैसे हिमाचल में लगभग

श्री एन0जी0द्वारा जारी...

31.08.2026/1835/एच.के.-एन.जी./1

श्री जीत राम कटवाल......... जारी

3 लाख पेंशनर हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति हर माह एक जैसा पैसा जमा करता है और उसको बाद में पेंशन मिलती है। सरकार इस दिशा में भी कुछ कर सकती है। इनके बारे में सोचना चाहिए। नौकरियों के बारे में भी सोचना चाहिए और जो अभी हाफ-एम्प्लॉयड हैं, 1/4th एम्पलॉयड हैं, उन्हें 5,500 या 6,000 रुपये मिलते हैं। इसमें क्या बनता है? 6,000 रुपये में आज के समय में क्या होता है? कहीं अगर अस्पताल जाना पड़ जाए तो टैक्सी वाला ही उससे ज्यादा पैसे मांग लेगा।...(घण्टी)...

Chairman : Please wind-up.

श्री जीत राम कटवाल : इसलिए मैं कम-से-कम यह कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को 5,000-6,000 रुपये मिलते हैं, उनके लिए 1,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन सरकार की ओर से जमा किया जाए। इनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करें और कुछ पेंशन का बंदोबस्त करें। नहीं तो 50-55 साल की उम्र में रेगुलर होंगे और जिस दिन घर जाएंगे, मुंह लटकाकर जाते हैं। उस समय बड़ी भारी दुःखद परिस्थिति होती है। सबसे बड़ा सहारा यह है कि सरकार ने लेबर कोड बनाए हैं। भारत सरकार ने Code of Wages, 2019, Code of Social Security, 2020, Health and Working Condition Code, 2020 बनाए हैं। इनका उद्देश्य पार्ट-टाइम वर्कर्स को लाभ देना और आउटसोर्सिंग वर्कर्स के लिए विशेष मामलों में अनिवार्य नियुक्ति-पत्र जारी करने की अपेक्षा होती है।...(घण्टी)...

Chairman : Please wind-up.

श्री जीत राम कटवाल : इसमें कुछ भारत सरकार वहन करेगी और कुछ प्रदेश सरकार करेगी। इन कर्मचारियों को Provident Fund, Social Security Coverage, Statutory Right of Minimum Wages under Code of Wages 2019 में दें। Health check-up or workers की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। ई0एस0आई0 अस्पताल इसी के

31.08.2026/1835/एच.के.-एन.जी./2

लिए हैं। अगर इनको अटल पेंशन योजना में लाएंगे और इनको अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे, तो प्रदेश की जो सबसे नीचे की बुनियादी कड़ी है, जो आधार है, जो समाज की और रोजगार व्यवस्था की नींव है, वह मजबूत होगी।...(घण्टी)... ग्रेच्युटी की एलिजिबिलिटी को एक साल कर देना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं Department Labour, timely wages, Department to Enforce or Eligibility of Gratuity को भी देखें।

Chairman : Hon'ble Member, please wind-up. अभी बहुत माननीय सदस्यों ने बोलना है।

श्री जीत राम कटवाल : यह जो ह्यूमन पावर या ह्यूमन रिसोर्स हैं, इनका प्रॉपर और ऑप्टिमम उपयोग होना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।

सभापति : अभी मेरे पास पक्ष और विपक्ष के कुल 20 लोगों के नाम आए हैं। इसलिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि कृपया समय का ध्यान रखें।

अब इस चर्चा में माननीय सदस्य, श्री राम कुमार भाग लेंगे।

श्री राम कुमार : सभापति महोदय, नियम-130 के तहत जो प्रस्ताव माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा जी, श्री सुधीर शर्मा जी, श्री राकेश जम्वाल जी, डॉ0 हंस राज जी और श्री जीत राम कटवाल जी द्वारा लाया गया है, वह रोजगार के संबंध में है। यह बहुत ही ज्वलंत प्रस्ताव है। रोजगार का विषय पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा, क्योंकि रोजगार का मामला युवाओं से जुड़ा हुआ है। हमारे साथी हमेशा राजनीतिक बात करते हैं। इस सरकार ने आते ही पहले जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जो बेरोजगार होकर घर जाते हैं, उनको ओ0पी0एस0 जारी करके सबसे बड़ा तोहफा दिया। उसके बाद जो बैचवाइज भर्तियां बंद थीं, उनको खोला और जिसके माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार मिला। कमीशन के माध्यम से भर्तियां बंद थीं, वे भर्तियां भी खोली गईं। शिक्षा विभाग में ही लगभग 2 से 3 हज़ार लोगों को इस सरकार ने रोजगार दिया है। इसके अलावा लगभग सभी

31.08.2026/1835/एच.के.-एन.जी./3

विभागों में भर्तियां हुईं और लोगों को रोजगार दिए गए। जल शक्ति विभाग में भी भर्तियां हुईं। लोक निर्माण विभाग में मल्टीटास्क वर्कर्स की संख्या बढ़ाई गई। हम देखते थे कि लोग रिटायर हो गए थे और सड़कों की दशा ठीक करने तथा उनको मेंटेन करने के लिए पी0डब्ल्यू0डी0 के पास पर्याप्त मैनपावर नहीं थी। सरकार ने सोचा कि हमारी सड़कें जोकि लेबर द्वारा रिपेयर होती हैं और उनको मेंटेन करने के लिए मल्टीटास्क वर्कर्स की जरूरत

है, इसलिए उनकी भर्ती की गई। वन विभाग में भी हम देखते हैं कि जलते हुए वनों को बुझाने के लिए लोगों की जरूरत होती थी। इसमें नौजवान लड़कियां भी बहुत सारी नियुक्त हुई हैं। आज हम देखते हैं कि नौजवान लड़कियां ग्रीन वर्दी में वन मित्र के रूप में कार्य कर रही हैं। हजारों लड़कियों और लड़कों, नौजवान साथियों को वन विभाग में भर्ती किया गया। पुलिस की भर्तियां भी बंद थीं

पी0बी0 द्वारा......जारी

31.08.2026/1840/pb/yk-1

श्री राम कुमार....जारी

ये भर्तियों की बात करते हैं। पुलिस विभाग में भी पूर्ण पारदर्शिता के साथ भर्तियां की गई हैं तथा अब पुनः लड़कों और लड़कियों के लिए पुलिस भर्ती प्रक्रिया आरम्भ की गई है। इनके कार्यकाल की तरह पेपर लीक नहीं हुए, घपले नहीं हुए और न ही चुनिंदा लोगों तक प्रश्न-पत्र पहुंचाए गए। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस चयन आयोग को बंद करके नया तंत्र स्थापित किया है। शिक्षा विभाग में भर्तियां हुई हैं, परिवहन विभाग में कंडक्टरों और ड्राइवरों की भर्ती की गई हैं तथा स्वास्थ्य विभाग में नर्सों, सी0एच0ओ0 और डॉक्टरों की नियुक्तियां की गई हैं। बिजली विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी थी। गांवों में फ्यूज लगाने तक के लिए कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे। इसलिए विभाग में फील्ड स्तर पर अत्यधिक आवश्यक निम्न श्रेणी के कर्मचारियों की भी भर्ती की गई है। इसी प्रकार हमारी वैटरनरी डिस्पैंसरियों में टीका लगाने वाले कर्मचारी तक उपलब्ध नहीं थे। फार्मासिस्टों तथा उनके सहायक कर्मचारियों के पद भी रिक्त थे। इसलिए वहां भी भर्तियां की गई हैं। सरकार ऐसी स्टार्टअप योजनाएं लेकर आई है, जिनके माध्यम से जो नौजवान साथी स्वयं का रोजगार स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें सब्सिडाइज्ड आधार पर ई-टैक्सी और ई-बसें सब्सिडी में उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्हें रोजगार की गारंटी भी दी जाएगी कि उनकी बसें और टैक्सियां सरकारी कार्यों में संचालित होंगी। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से उन्हें एकमुश्त प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। हमारी गवर्नमैंट द्वारा बहुत बड़ी प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। सरकार सोलर सिस्टम की योजना भी लेकर आई है

जिसके माध्यम से एक बीघा, दो बीघा या पांच बीघा भूमि वाले लोग, जहां खेती नहीं होती है या जो ढलानदार क्षेत्र हैं, वहां सोलर सिस्टम स्थापित करके स्वयं रोजगार के अवसर सृजित कर सकते हैं। इस योजना में इंटरस्ट सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। चाहे वह अपर एरिया हो या लोअर एरिया, दोनों क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है, जिसकी घोषणा मुख्य मंत्री जी ने की है। 'राजीव गांधी वन संवर्धन योजना' भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। हाल ही में माननीय संजय अवस्थी जी के क्षेत्र के दौरे के दौरान मेरे क्षेत्र के भी तीन-चार महिला मंडलों को लगभग 4,00,000 रुपये के चैक प्रदान किए गए। इस योजना के अंतर्गत महिला मंडल तथा नौजवान साथी किसी वन क्षेत्र की पहचान कर सकते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमैंट उनकी सहायता करेगा तथा वे वहां वनारोपण का कार्य करेंगे। इसके बदले

31.08.2026/1840/pb/yk-2

सरकार उन्हें प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। रोजगार सृजन के लिए यह सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। यहां यह कहा जा रहा था कि प्रदेश में इंडस्ट्री नहीं आ रही है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र में लगभग 20 बड़ी इंडस्ट्रीज़ ने विस्तार किया है जिनमें लगभग 50,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमैंट आया है तथा लगभग 2,000 हिमाचली युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। अभी 'जुपिटर' नामक कंपनी स्थापित हुई है। उसके लगभग चार यूनिट 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में संचालित हैं। उन चारों यूनिटों में लगभग 1,500 हिमाचली युवाओं को रोजगार मिला है जिनमें से लगभग 500 युवाओं को मैंने स्वयं वहां नियुक्त करवाया है। पूरे हिमाचल प्रदेश से लोग वहां रोजगार के लिए पहुंच रहे हैं। इसी प्रकार संधार कंपनी लगभग 400 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमैंट लेकर आई है। बिरला ग्रुप की एक कंपनी, जो प्रयुक्त प्लास्टिक की बोतलों को क्रश करके उनसे धागा तैयार करती है, उसमें भी लगभग 1,000 युवाओं को रोजगार मिला है। इसी प्रकार क्रोन एक अन्य कंपनी में भी लगभग 400 से 500 लोगों की भर्ती हुई है। इसके अतिरिक्त छोटी-बड़ी अनेक कंपनियां स्थापित हुई हैं। किसी कंपनी में 20 लोग कार्यरत हैं, किसी में 50 लोग कार्यरत हैं। कुल मिलाकर लगभग 100 नई इंडस्ट्रीज़ स्थापित हुई हैं। ये लोग उद्योग बंद होने की बात करते हैं जबकि इनके कार्यकाल में भी लगभग 350 उद्योग बंद हुए थे। किसी का एग्रीमैंट समाप्त हो गया, किसी के

साझेदारों में से एक की मृत्यु हो गई या किसी को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। ऐसी अनेक परिस्थितियों के कारण उद्योग बंद होते हैं। साढ़े तीन सौ इंडस्ट्रीज़ इनके समय में भी बंद हुई हैं। कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी भी हो सकती हैं जिनमें से 100-200 इंडस्ट्रीज़ का जॉब वर्क एग्रीमैंट समाप्त हो गया हो और उनके पास अब कोई काम न हो। स्वाभाविक रूप से 20 वर्ष पुरानी मशीनरी के कारण, बैंकक्रप्ट होने या अन्य व्यावसायिक कारणों से भी कुछ इंडस्ट्रीज़ बंद होती हैं। जिस एम0एस0पी0 के मुद्दे को लेकर हमारे देश के किसान दिल्ली में बैठे थे वहां लगभग 700 किसानों ने अपनी जान दी लेकिन उस विषय पर भारत सरकार ने एम0एस0पी0 नहीं दिया। लेकिन हिमाचल प्रदेश की

श्री ए0पी0द्वारा जारी

31.08.2026/1845/एच0के0/ए0पी0-01

श्री राम कुमार जारी .....

माननीय मुख्य मंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ऐसी पहली सरकार बनी, जिसने धान, कनक और मक्की पर एम0एस0पी0 दिया है। जब देश आज़ाद हुआ तब कांग्रेस के नेताओं ने पहले मिल्क क्रांति लाई और उसके बाद हरित क्रांति लाई ताकि देश को हरा-भरा किया जा सके। क्योंकि उस समय देश के पास खाने के लिए अनाज नहीं था। उसी तरह माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश में मिल्क क्रांति लाकर, सोसाइटीज़ के माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार दिया है। लोग गांव में अपनी गाय और भैंस पालते हैं और सोसाइटी उनका दूध बेचने के लिए उठाती है। सरकार उन्हें ज्यादा रेट पर उसका भुगतान कर रही है। इसके बायप्रोडक्ट के लिए भी गांव में छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज़ लगाई गई हैं। ...(व्यवधान) इन छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से दूध के बायप्रोडक्ट बनाकर लोग उससे तीन गुना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। आगे बात हुई कि और वर्ष- 1990 से मेरे पिता जी इस माननीय सदन के चार टर्म तक सदस्य रहे हैं। यह कई बार बात होती थी कि बंदरों के कारण हिमाचल प्रदेश में खेती नहीं हो पा रही है। यह पहली ऐसी सरकार है जिसने सोचा कि इसका ट्रीटमेंट किया जाए और ऐसी फसल उगाई जाए, जिसे न बंदर

खाएं, न सेउं खाए और न कोई और जानवर खाए। इसी कारण हल्दी का रेट पहले 100 रुपये था, जिसे अब 150 रुपये किया गया है। इसके माध्यम से जो बंजर जमीनें पड़ी थीं, हमारे जमींदार और हमारे नौजवान साथी अपने खेतों में काम करने लगे हैं। वो जमीनें जो बंजर हो गई थी, उन्हें लोगों ने हल्दी के माध्यम से हरा-भरा किया है। इसके माध्यम से लोग हजारों करोड़ रुपये कमा रहे हैं और लोगों को अपने घर और अपने गांव में ही रोजगार मिल रहा है। अब मैं मनरेगा की बात करूंगा, जिसे कांग्रेस ने लाया और स्वर्गीय डॉ0 मनमोहन सिंह जी ने लाया था। जिसके माध्यम से 100 दिन के रोजगार की गारंटी कांग्रेस सरकार ने दी थी ताकि गांव में कोई विधवा बहन हो या गांव में कोई ऐसा आदमी हो जो काम करने के लिए दूर नहीं जा सकता, उसे 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिल सके। इनकी सरकार ने इसे खत्म किया और इसका नाम बदलकर वीबी-जीराम-जी कर दिया। इसका पैसा और दिहाड़ी भी इन्होंने कम कर दिया

31.08.2026/1845/एच0के0/एए0पी0-02

है। इसलिए धोखा तो ये लोग कर रहे हैं। अभी ये युवाओं की बात कर रहे हैं क्योंकि चुनाव एक साल के बाद है। ये सोच रहे हैं कि युवाओं की बात करेंगे तो शायद बच जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं आप बचोंगे नहीं। हजारों-लाखों युवा, जहां-जहां राहुल गांधी जा रहे हैं, वहां इकट्ठे हो रहे हैं। आपने देखा कि दिल्ली में भाजपा की करतूतों के कारण युवाओं ने इनको मजबूर किया। ये चाहते थे कि जो पद पर आ गए हैं, वे कभी इस्तीफ नहीं देंगे। लेकिन इनके शिक्षा मंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा। यह ताकत हमारे युवाओं की है और युवा आज भाजपा के पूरी तरह खिलाफ हैं। पहले हम स्वर्ण की बात करते थे, लेकिन अब वे भी इनके खिलाफ हैं। प्राकृतिक खेती की शुरुआत हमारी सरकार ने की है। इसमें ज्यादा रेट दिया जा रहा है। इसके माध्यम से जो बहुत अच्छे किसान हैं, वे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल न करके प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और अपने घर में ही रोजगार कमा रहे हैं। अभी एक नया कार्य भी हमारी सरकार ने शुरू किया है। हमारी पंचायतों और स्कूलों में चौकीदार नहीं थे। अगर चौकीदार थे भी तो वे रिटायर हो गए थे। सरकार ने उनके पद

सृजित किए हैं। जिसके माध्यम से ग्रामीण परिवेश से आने वाले जरूरतमंद लोगों को रोजगार मिलेगा है। जिन संस्थाओं को इसकी जरूरत थी चाहे वे पंचायतें हों या हमारे स्कूल हो, उन सभी जगहों पर चौकीदार के पद सृजित किए गए हैं। एयरपोर्ट की स्थापना की बात करें तो इतना टाइट होने के बावजूद भी एक हजार करोड़ की डी0जी0 मिली। आर0डी0जी0 बंद होने के बावजूद मुख्य मंत्री जी ने साहस किया कि हम एयरपोर्ट बनाएंगे। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद यह था कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले सके। इसके बाद नई सिटी बसाने की शुरुआत बद्दी, शिमला और कांगड़ा में की गई। जिसके माध्यम से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और उन्हें यह रोजगार अपने क्षेत्र में ही मिलेगा। इससे लोग पैसा भी कमाएंगे और उन्हें रहने के लिए घर भी मिलेंगे। अब पेंशन की बात करते हैं। मैं इस सदन में हमारे साथियों से भी कहना चाहूंगा कि हर मंच पर इसकी बात करें कि जिन लोगों की 1,100 रुपये पेंशन थी। हमारी सरकार के आने के बाद इसे 1,500 रुपये कर दिया गया। अभी अपना परिवार, सुखी परिवार की स्कीम चलाई गई है। इसमें कहा गया कि हमारे बी0पी0एल0 के लोगों की संख्या सीमित है। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा कि किसी पंचायत में 60 बी0पी0एल0 हैं या 80 बीपीएल हैं

31.08.2026/1845/एच0के0/ए0पी0-03

तो उतने ही रहेंगे। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उन सभी लोगों को बी0पी0एल0 की परीधी में लाएगें। जिनकी आय 70 हजार रुपये से कम है, जिनके घर में एक दिव्यांग व्यक्ति 40 प्रतिशत से अधिक है

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

31.08.2026/1850/AT/AG/01

श्री राम कुमार जारी....

या जिनके घर में परिवार का सरपरस्त अथवा कमाने वाला व्यक्ति नहीं है। उन सभी लोगों के लिए नई योजना लाई जा रही है। लगभग दो लाख परिवारों को माननीय मुख्य मंत्री जी, उस योजना के तहत ला रहे हैं। आप मंगेरीलाल के सपने देखना छोड़ दीजिए कि आज इनकी सरकार है और कल हमारी आएगी। ये मंगेरीलाल के सपने लेने छोड़ दीजिए। मुख्य मंत्री जी, दिन-रात इस पर काम कर रहे हैं।

जैसे इन्होंने कहा कि हम होमस्टे को प्राथमिकता देंगे, जिसमें बाहर से जब लोग घुमने आते हैं। तो इसमें आपने विरोध किया। पर मुख्य मंत्री जी ने होमस्टे को लीगलाइज किया है और नौजवान साथीयों से कहा कि, वे अपने घर में अपना छोटा-सा आशेयाना बनाएं। जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिलेगा।

मुख्य मंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि रोजगार के विभिन्न संसाधन उन्होंने तैयार किए और हजारों युवा जिनको निचले स्तर पर अनदेखा किया जा रहा था, जिन्हें कभी कोई पूछता नहीं था, उन्हें नौकरी देने का काम उन्होंने किया और सभापति महोदय, अपना मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद।

सभापतिः अब इस माननीय सदन की बैठक मंगलवार, दिनाक 01 सितंबर, 2026 के 11:00 बजे पर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला : 171004
दिनांकः 31.08.2026 **यशपाल शर्मा**
सचिव